MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no, that is over. ...(*Interruptions*)... That is over. Now, we have to take the next discussion.

श्री के. सी. त्यागीः माननीय मंत्री श्री किरन रिजिजु जी जो cattle trader का जिक्र कर रहे थे, इसकी जगह...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is over.

श्री के. सी. त्यागीः सर, मैं आधे मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। जब आप शुरू में ही लिख देंगे cow and beef ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, you cannot go back to that. ...(*Interruptions*)... No, no clarification. That is not possible. That is against the rule.

श्री के. सी. त्यागीः सर, आधा मिनट तो मेरी बात सुन लीजिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. That is against the rule.

SHRI K. C. TYAGI: Cow and beef traders ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. You cannot. No, you cannot ask a question now.

श्री के. सी. त्यागीः Cattle trader में और cow and beef trader में फर्क होता है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: मैं क्या कर सकता हूं? It is against the rule. Asking a question now is against the rule. That is the point. What do I do? It is already over. Now, Message from Lok Sabha.

MESSAGE FROM LOK SABHA

The Finance Bill, 2016

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha.

> "In accordance with the provisions of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Finance Bill, 2016, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 5th May, 2016.

The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill within the meaning of Article 110 of the Constitution of India."

Sir, I lay a copy of the Bill on the Table.

DISCUSSION ON THE WORKING OF THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, discussion on the working of the Ministry of Human Resource Development. Shri Naresh Agrawal.

श्री नरेश अग्रवाल (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति जी, एक महत्वपूर्ण मंत्रालय पर चर्चा शुरू करने की जिम्मेदारी मुझे दी गयी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री महोदया अपने जवाब में, हम लोग जो सुझाव देंगे, जो बातें कहेंगे, उनके बारे में यह नहीं सोचेंगी कि हम कोई allegation लगा रहे हैं। हमारा कतई यह परपज़ नहीं है कि हम उन्हें allege करें, लेकिन हम जो सुझाव देंगे, जहां-जहां कमी देखें, आप उन कमियों को गंभीरता से लेकर उन्हें सुधारने का प्रयास करेंगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। आप बड़ी सौभाग्यशाली हैं कि इतनी जल्दी राजनीति में इतने उच्च पद पर पहुंच गयीं। महोदय, ये भी अकसर विवाद में रहती हैं। हमारी पार्टी का यह मानना है कि जो चर्चा में रहे, जो पर्चा में रहे और जो खर्चा में रहे, उसको राजनैतिक रूप से कभी कोई डाउन नहीं कर सकता। आपके पोस्टर भी लग गए, उत्तर प्रदेश में लगे, यह तो अच्छी बात है, लेकिन आपने अपनी मिनिस्ट्री में उनको बिठा दिया, हमें लोगों ने बताया कि वे आरएसएस द्वारा बिठाए गए हैं और वे जो डायरेक्शन देते हैं, चाहे एआईसीटीई हो, चाहे यूजीसी हो ...**(व्यवधान)**...

श्री प्रभात झा (मध्य प्रदेश): आप नाम क्यों ले रहे हैं?

डा. सत्यनारायण जटिया (मध्य प्रदेश): उनका नाम लेने का क्या औचित्य है? वे तो सदन में नहीं हैं।

श्री नरेश अग्रवाल: क्या मतलब? किसी का नाम ही नहीं लिया जाएगा?

श्री प्रभात झा: नरेश जी, आप सही नाम लें।

श्री नरेश अग्रवाल: उनका क्या नाम है? झा साहब, आप सही नाम बता दें।

श्री प्रभात झा: उनका नाम श्री कृष्ण गोपाल है और उनका इस संबंध में कोई ...**(व्यवधान)**...

श्री नरेश अग्रवाल: सर, मैं प्रभात झा जी को बहुत-बहुत बधाई दूंगा कि कम से कम उन्होंने ...**(व्यवधान)**... जटिया जी, आप तो बहुत सीनियर हैं। सर, बाहर एक चर्चा है कि कृष्ण गोपाल जी जो एआईसीटीई में कह देंगे, जो यूजीसी में कह देंगे, जो मिनिस्ट्री में कह देंगे, वही माना जाएगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री जावेद अली खान (उत्तर प्रदेश): क्या किसी का नाम लेने में कोई पाबंदी है?

† **جناب جاوید علی خان:** کیا کسی کا نام لینے میں کوئی پابندی ہے؟

श्री नरेश अग्रवाल: सर, किसी का नाम लेने में कोई पाबंदी नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

† Transliteration in Urdu script.

THE MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (DR. NAJMA A. HEPTULLA): One should not be taking the name of a person not present in the House, who is not a Member of this House. So, he should not take the name. ...(*Interruptions*)...

श्री नरेश अग्रवालः श्रीमन्, कल डिस्कशन में इटली, रोम सबके नाम ले लिए गए। ...(**व्यवधान**)... मिशेल वगैरह के नाम ले लिए गए, वे भी तो सदन के सदस्य नहीं हैं। ...(**व्यवधान**)... कल इटली वगैरह तमाम नाम लिए गए, तमाम रक्षा सौदागर, दलालों के नाम लिए गए, उस समय कोई आपति नहीं हुई। ...(**व्यवधान**)... वे आपके भाग्य विधाता हैं, हमारे नहीं हैं। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You can't criticize or raise an allegation against a person who can't come and defend here.

श्री नरेश अग्रवालः सर, कल क्यों हुआ, कल क्यों हुआ? कल क्यों allegation लगे, कल मिशेल वगैरह पर कैसे allegation लगे? ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः अगर allegation है, तो मैं... ...(**व्यवधान**)...

श्री नरेश अग्रवालः स्वामी जी क्या करते रहे? स्वामी जी तो अपने भाषण में allegation लगाते रहे और उन्हीं लोगों पर लगाते रहे, जो सदन के सदस्य नहीं हैं। ...(**व्यवधान**)... उनका कोई लेना-देना नहीं। ...(**व्यवधान**)... सीधे-सीधे कांग्रेस अध्यक्ष पर, कांग्रेस के नेताओं पर लगाते रहे। श्रीमन्, उस समय क्या बात थी? ...(**व्यवधान**)...

डा. नजमा ए. हेपतुल्लाः आपने objection क्यों नहीं किया? ...(**व्यवधान**)...

एक माननीय सदस्यः आप तो संविधान की बात करते हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः आप allegation मत बोलो। आप अच्छी बात बोलो। ...(**व्यवधान**)... चलिए, you can praise them, not allege them. Talk good words about them. Those who are not present here, talk good words about them.

SHRIMATI JAYA BACHCHAN (Uttar Pradesh): Sir, he is not criticizing him. He has not said anything negative. (*Interruptions*)

SHRI JAIRAM RAMESH: What about Dr. Swamy? Did he not raise it yesterday? I was present when he was making allegations.

श्री नरेश अग्रवालः उपसभापति महोदय, मैंने तो किसी की आलोचना नहीं की है। मैंने कुछ कहा भी नहीं है। मैंने यह कहा है कि यह सुनने को मिला है ...(**व्यवधान**)... चलिए, एक आदमी जो आरएसएस के नेता हैं, वे आपकी मिनिस्ट्री में बैठ गए हैं। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I expunged everything. Wherever specific, I expunged everything. ...(*Interruptions*)... I can't guess and expunge.

श्री नरेश अग्रवालः मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। मैं भागवत साहब का नाम नहीं ले रहा हूं, किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। मैंने कहा कि एक आदमी, यह सही है या गलत है, यह तो माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में बता देंगी। मैंने कौन सी गलत बात कही है? आप मंत्री हैं,

[श्री नरेश अग्रवाल]

मंत्रालय पर कोई सुपर मंत्री हो जाए, मंत्रालय कोई दूसरा चलाने लगे, यह उचित नहीं है। मैं चाहूंगा कि इसमें सुधार होना चाहिए। ये जो बाहर चर्चाएं हैं, मैं तो कहता हूं कि ये चर्चाएं असत्य होंगी, ये सत्य नहीं होंगी, यह तो मैं खुद कह रहा हूं, लेकिन जो कहा जा रहा है, उसको मैं आपको बता रहा हूं। हम और आप आलोचना सुनने के लिए बने हैं। हम आलोचना भी सुनते हैं, प्रशंसा भी सुनते हैं, दोनों चीजें सुनकर निर्णय लेते हैं, तो आप उस हिसाब से निर्णय ले लीजिए।

श्रीमन्, कभी भी ऐसा नहीं हुआ, किसी मानव संसाधन विकास मंत्री के ज़माने में कि वी.सी. के माध्यम से छात्रों का उत्पीड़न हो। आज सवेरे ही शुरुआत हुई। जे.एन.यू. में क्या हो रहा है? कन्हैया कुमार वगैरह अनशन पर बैठे हुए हैं, उनकी हालत बहुत खराब है, यह अखबारों में दिया हुआ था। डॉक्टरों ने कह दिया कि अगर अनशन नहीं तोड़ा गया, तो कोई भी हादसा सम्भव है। क्या वी. सी. की जिम्मेदारी नहीं थी कि वहां पर व्यक्तिगत रूप से जाकर कहते, उससे अनुरोध करते? इसमें वी.सी. को कौन-सी अड़चन थी? ऐसा ही इलाहाबाद में हुआ। वहां पर पहली बार एक महिला, छात्र संगठन की अध्यक्ष बनी, उसके साथ वैसा ही हुआ, आपने क्या किया? आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में क्या हुआ? हैदराबाद में रोहित वेमुला का कांड हुआ? क्यों सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में सारे कांड हो रहे हैं, क्या कारण है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपना एजेंडा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में चला रहे हैं, लड़के उसको पसन्द नहीं कर रहे हैं। मैं एक बात कह दूं कि स्टूडेंट्स मूवमेंट बनता देर से है, लेकिन जब बनता है, तो बहुत तकलीफदेह होता है। यह कहावत है कि "अभी तो अगड़ाई है, आगे और लड़ाई है।" आप स्टूडेंट्स मूवमेंट मत बनने दीजिए। मैं नहीं चाहता कि स्टूडेंट्स मूवमेंट बने। हम भी स्टूडेंट रहे हैं, हम भी यूनिवर्सिटी में लीडर रहे हैं। हम जानते हैं, हमारा काम है। लड़के हठधर्मी करते हैं, लेकिन वी.सी. का काम यह नहीं है कि हठधर्मी को पुलिस के बल पर तुड़वाए। वी.सी. का काम होता है कि अगर हठधर्मी गलत भी है, तो उस हठधर्मी को तर्कों के साथ, उनके साथ बैठकर खत्म करवाएं। आप अपने वी.सीज़ को इन्स्ट्रक्शन्स दें, क्योंकि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी तमाम मसायल पैदा हो गए हैं। अगर वी.सीज़ छात्रों के साथ महीने में एक बार भी बैठक कर लें, यूनियन के लीडर्स के साथ बैठक कर लें या फिर आप यूनियन्स को बैन कर दीजिए। अगर यूनियन है, छात्रों का अपना नेता है, जैसे हम सब हैं, तो उसको महीने में एक बार अपने साथ बैठा लें, तो शायद इस तरह की समस्याएं खड़ी भी न हों। मैं चाहूंगा कि ये समस्याएं खड़ी न हों।

श्रीमन् संविधान का 86वां संशोधन हुआ, तो उस समय बड़े जोर से कहा गया कि शिक्षा अनिवार्य हो गई है। आप अपने आंकड़ों में कहते हैं कि हम 72 per cent लोगों को education दे पाए हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि हमारे राज्यों में अभी महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे हैं। GDP का कुल तीन प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है। इसके लिए कमेटी बनी और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी। GDP का 6 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। क्या शिक्षा अनिवार्य नहीं है? जब शिक्षा अनिवार्य है और मैं तो कहूंगा कि जिस देश में सब शिक्षित हो गए, वह देश आगे बढ़ गया और जिस देश में अशिक्षा है, वह देश आगे नहीं बढ़ा और कहीं न कहीं वह देश असभ्य कहलाने लगा। आप मिसाल के तौर पर देखिए कि हिन्दुस्तान के कुछ राज्यों में 100 per cent education है। आप देखिए, केरल, पुडुचेरी और एक और राज्य है, इन तीनों राज्यों की प्रगति और अन्य प्रांतों की प्रगति देख लीजिए, दोनों में कितना अंतर है? दोनों

की प्रगति में बहुत बड़ा अंतर है। समाज की सभ्यता के लिए शिक्षा है। अगर सबको शिक्षा मिल जाए, तो देश के सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आबादी की है, वह भी दूर हो जाएगी। हम खुश हो रहे हैं कि हम चीन से आगे हो जाएंगे, लेकिन देश के लिए आबादी कितनी प्रॉब्लम बनती जा रही है? अब तो यह हो गया है कि अगर यही हाल रहा, तो दिनों बाद पीने के पानी के लिए world war हो जाएगा। आज हमारे पास टोटल जितना पानी है, उसका 3 per cent कुल पीने का पानी है। अगर इस बढ़ती हुई आबादी में पीने के पानी की कमी होगी, तो देश के सामने समस्या पैदा होगी, इसलिए आप इसको देखिए। श्रीमन्, आज तमाम यूनिवर्सिटीज़ में शिक्षकों की कमी है। इनके आंकड़ों के अनुसार teaching staff में कुल 16,525 पद हैं और इनके पास 10,538 staff है और 5,987 पद खाली हैं और non-teaching staff में 8,026 पद खाली हैं। मैं पूछता हूं कि इतना बड़ा गैप क्यों है? आप क्यों नहीं Recruitment Board गठित करतीं? आप Recruitment Board बनाकर यह आदेश दीजिए कि एक साल के अंदर शिक्षा का पूरा recruitment कर दें। हमारे यहां उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा में बोर्ड बनने के कारण teachers की कमी हो गई है। हमारे यहां कॉलेजों में कुल चार-चार teacher रह गए, बच्चों को पढ़ाने वाला कोई नहीं है। हम teachers रख नहीं सकते, क्योंकि teachers को तो गवर्नमेंट भर्ती करेगी या बोर्ड भर्ती करेगा। आज यूनिवर्सिटीज़ में इतने शिक्षकों की कमी है, तो आप इस कमी को कैसे पूरा करेंगे, यह तो आपको तय करना है। आप कोई निर्णय लीजिए और निर्णय लेकर आप तय करें, नहीं तो कैसे शिक्षा का काम पूरा होगा? हमारी quality of education बहुत गिरी है। हमारे पास quantity तो बढ़ गई है, बहुत यूनिवर्सिटीज़ बन गई हैं, शायद सबसे ज्यादा deemed universities की संख्या हमारे यहां हो गई है। मैं आपको इसकी संख्या आगे बताऊंगा। आज हमारे यहां quality of education क्या है? आज विश्व की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में हिन्दुस्तान की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं आती है। इसका क्या कारण है? यदि आप 200 यूनिवर्सिटीज़ को भी ले लें, तो 200 में हिन्दुस्तान की कोई यूनिवर्सिटी नहीं आएगी। अगर एजुकेशन में निजी क्षेत्र की भागीदारी नहीं हुई होती, तो स्थिति इससे भी और खराब हो जाती। निजी क्षेत्र की भागीदारी ने education को नया आयाम दिया है। मैं कहूंगा कि आज निजी क्षेत्र की education को लोग पसंद कर रहे हैं और सरकारी स्कूलों की education को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। आज convent schools में बच्चों को भर्ती कराने के लिए मारा-मारी हो रही है और दिल्ली के अच्छे स्कूलों और कॉलेजों में भर्ती कराने के लिए मारा-मारी हो रही है। मैं कुछ स्कूल व कॉलेजों के नाम जानता हूं, जिनमें 99 और 98 per cent लाने वाले बच्चों को प्रवेश मिलता है, तो कम अंक लाने वाले बच्चे प्रवेश नहीं पाते हैं। इसके लिए दिल्ली सरकार को रूल बनाने पड़ रहे हैं। आखिर हम उन स्कूलों में क्यों जाना चाहते हैं? हम उनमें इसलिए जाते हैं कि वे quality देते हैं। अब तो लोगों का यह मन हो गया है कि हम डिग्री हासिल कर लें। आज डिग्री हासिल करना बहुत आसान है। देश के सभी प्रांतों में आप डिग्री ले लीजिए। आप जिसका नाम बताएंगे, उसी की डिग्री बन जाएगी। शिक्षा मंत्री की डिग्री पर विवाद है। आप बताइए, जहां से आप कहेंगी, आपकी डिग्री वहीं से बनवा देंगे। मैं कल ही पढ़ रहा था, किसी न्यायालय ने तीन राज्यों के चुनाव अधिकारियों से मांगा है कि आप हमें affidavit दीजिए। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और गुजरात के चुनाव अधिकारियों से affidavit मांगा गया है कि क्या-क्या affidavit दिए थे? डिग्री बनवानी है तो तमाम ऐसी डिग्रियां बन रही हैं कि जिस युनिविर्सटी की चाहिए, उस युनिविर्सटी की बनवा लीजिए। जो स्थिति है, उस पर हम खुद चिंता कर रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन का अर्थ एजुकेशन होना चाहिए, न कि डिग्री होना चाहिए, लेकिन आज हमारी यह सोच बन गई है।

[श्री नरेश अग्रवाल]

आज नकल कितना बड़ा रोग है। टीवी पर दिखाया जाता है कि लोग कैसे कॉलेज पर चढ़कर नकल करा रहे हैं। नकल रोकने का कोई सिस्टम नहीं है। राज्यों में भी नकल रोकने का कोई सिस्टम नहीं है। आज नकल के माध्यम से न जाने कितने colleges पैसा पैदा कर रहे हैं। नकल कराने का college का धंधा हो गया है। नकल उतारकर लोग डिग्री ले रहे हैं और वही डिग्री धारण करने वाला जब किसी सरकारी नौकरी में जाता है तो क्या स्थिति खड़ी होती है? क्या आपने नकल रोकने के लिए कोई प्रावधान रखने की बात की है? आप यह बनाइए, आप सारे राज्यों के शिक्षा मंत्रियों को बुलाइए, उन शिक्षा मंत्रियों के साथ बैठकर इस नकल को, जो देश के लिए अभिशाप है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको रोकने के लिए कोई एक कानून बनाइए।

मैं तो कहता हूं कि शिक्षा भी समान होनी चाहिए। हर University का सिलेबस अलग, हर University का कोर्स अलग, विषय अलग है। ऐसा क्यों है? जब समान शिक्षा की बात करेंगे तो हर University का सिलेबस एक क्यों नहीं होना चाहिए? इसमें क्या दिक्कत है? आप क्रांतिकारी परिवर्तन कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। आप निर्णय लीजिए, आपके निर्णय को कोई अपोज़ नहीं करेगा, लेकिन कहीं न कहीं निर्णय अवश्य लेना चाहिए।

हमारे हिंदुस्तान में न जाने कितने तरीके की शिक्षा हो गई है। प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, कांवेन्ट शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा आदि। शिक्षा भी भौतिक की अलग हो गई, संस्कृत की अलग हो गई, उर्दू, फ़ारसी की अलग हो गई। इस देश में इतने तरीके की शिक्षा हो गई है कि यह समझ ही नहीं आता कि कौन-सी शिक्षा पढ़ें? संस्कृत की अलग शिक्षा है। अभी एक आदेश आया है कि University में, आई.आई.टी. वगैरह में संस्कृत पढ़ाई जाएगी। हम नहीं समझ पाए कि वहां पर संस्कृत पढ़कर क्या होगा? यह आदेश एक तुगलकी फ़रमान जैसा लगा। यह आदेश क्यों हुआ? मैं अखबार पढ़ता हूं, मैंने उसको पढ़ा है।

यहां बोर्ड भी दस तरह के हैं। हमारे यहां यू.पी. का बोर्ड अलग है, बिहार का अलग, अन्य राज्य का अलग है। उन बोर्डों में सीबीएसई अलग और आईसीएसई अलग है। ये तमाम बोर्ड बने हुए हैं, जिनके अलग-अलग कोर्स हैं, अलग-अलग डिग्रियां हैं। मैं चाहूंगा कि आप इस पर विचार करें और कहीं न कहीं कोई कदम उठाएँ।

यूजीसी और एआईसीटीई दो ऐसी बॉडीज़ हैं, जो रेग्युलेट करती हैं। यू.जी.सी. तो सभी Universities को रेग्युलेट करती है, लेकिन क्या आज वह अपने फंक्शन को पूरा कर रही है? मैं आगे आपसे इस पर बहस करूंगा।

राज्यों में हायर एजुकेशन का मुद्दा है। हर गवर्नर ने Higher Education अपने कब्जे में कर ली है। ऐसा लगता है कि राज्य सरकार का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। गवर्नर चांसलर हो गया। गवर्नर ने क्या किया? गवर्नर ने सारी Universities अपने कब्जे में कर लीं। अगर वाइस चांसलर भी नियुक्त करना है तो वह भी गवर्नर नियुक्त करेगा। पहले राज्य सरकारों से नाम मांगे जाते थे, लेकिन अब तो गवर्नर सीधे-सीधे नाम पढ़कर वी.सी. को नियुक्त कर देता है और राज्य सरकार का कोई मतलब नहीं रहता। उनको राज्य सरकार का फ़र्क तब पता चले, जब हम फंड करें और रेग्युलेट करें, बाकी तो गवर्नर Universities चला रहे हैं। आपको इसमें संशोधन करना चाहिए। क्योंकि उच्च शिक्षा केंद्र का विषय है, इसलिए आपको कहीं न कहीं इसमें संशोधन करना

चाहिए। उस संशोधन के माध्यम से, यदि यह राज्य सरकार का काम है तो राज्य सरकारें बोलेंगी, लेकिन यह गवर्नर का काम नहीं है। शायद देश का कोई ऐसा गवर्नर नहीं बचा है, जिसने उच्च शिक्षा को अपने कब्ज़े में न ले लिया हो। राज्य सरकार और गवर्नर के बीच में टकराव से उच्च शिक्षा का और बुरा हाल हुआ है।

आप देश में महिलाओं की शिक्षा बढ़ाने के लिए "कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय" खोलेंगे। उस दिन क्वेश्चन भी हुआ था, इस पर डिश्कशन भी हो रहा था कि क्यों नहीं हर ब्लॉक में एक ऐसा विद्यालय खुलता है? अगर आप महिलाओं की शिक्षा बढ़ाना चाहते हैं, तो देश के हर ब्लॉक में एक "कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय" खुल जाना चाहिए, जिससे महिलाओं की शिक्षा का अपने आप स्तर बढ़े। मेरा आज भी यह मानना है। हो सकता है कि पुरुष की शिक्षा 72 परसेंट तक पहुंच गई हो, लेकिन अभी भी महिला शिक्षा 50 परसेंट से ऊपर नहीं पहुंची है। गांवों में तो लोग बच्चियों को पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं। गांव में कहां लोग बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं?

अब शिक्षा तीन स्तर पर है। प्राइमरी शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा केंद्र का विषय है, प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा राज्य का विषय है, लेकिन ऐसा नहीं है, केंद्र उस पर भी निर्णय लेता है। आपने प्राइमरी एजुकेशन के लिए "सर्व शिक्षा अभियान" चलाया है। श्रीमन्, यह "सर्व शिक्षा अभियान" बड़े जोर-शोर से चला। इस "सर्व शिक्षा अभियान" अभियान के तहत् कुछ एक्ट्स पास हुए। यह कहा गया कि 100 परसेंट एजुकेशन होगी। राज्यों से कहा गया कि 'education to all'. फिर राज्यों से कहा गया कि 65 परसेंट पैसा आप लगाइए, 35 परसेंट पैसा केंद्र लगाएगा और आप सबको प्राइमरी स्तर पर शिक्षा दीजिए। राज्यों ने इसका विरोध किया कि हमारी financial स्थिति ऐसी नहीं है, परसेंट 35 परसेंट हम लगाएँगे और 65 परसेंट केंद्र को देना चाहिए। आज भी उस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया है। यही कारण है कि अभी भी तमाम प्राइमरी विद्यालय खुलने हैं। प्राइमरी विद्यालयों को आगे बढ़ाना है, लेकिन को निर्णय न होने के कारण और पैसे की कमी के कारण हमारी प्राइमरी एजुकेशन की स्थिति ही अच्छी नहीं है। श्रीमन्, प्राइमरी एजुकेशन का स्तर भी बहुत गिरा है। एक तरफ 4 लाख टीचर्स की कमी है। कुछ राज्यों में करीब 4.5 लाख untrained teachers पढ़ा रहे हैं, जिनमें बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। ये सब राज्य हैं, जहां 4.5 लाख ऐसे शिक्षक हैं, जो खुद ही untrained हैं, जिनको शिक्षा के बारे में पता ही नहीं है और वे छात्रों को पढ़ा रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में भी 'शिक्षा मित्र' शुरू हुआ था। अब तो यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास *sub judice* है, लेकिन अगर आप बच्चों को untrained teachers से पढ़वाएँगे, तो यह अच्छी बात नहीं होगी। मैं एक स्कूल का प्रबंधक हूँ। वहां आठवीं पास के दो बच्चे हमारे पास आए, उनके पास First Class की डिग्री थी। उन्होंने जूनियर हाई स्कूल First Class से पास किया था। वे हमसे प्रिंसिपल की शिकायत करने लगे कि आपके यहां हमारा एडमिशन नहीं लिया जा रहा है। हमने प्रिंसिपल को बुलाया और उनसे पूछा कि इनका एडमिशन क्यों नहीं लिया जा रहा है, तो प्रिंसिपल ने कहा कि आप जरा रुक जाइए, मैं इनकी मार्क शीट देख लूं। उन्होंने उनका जो टेस्ट लिया था, लौट कर जब उन्होंने दिखाया तो चार सब्जेक्ट्स में से चारों में उन्होंने ज़ीरो पाया था। ...**(व्यवधान)**... हां, वे First Class पास हुए। मुझे उस जूनियर हाई स्कूल के प्रिंसिपल को suspend कराना पड़ा, लेकिन बेसिक शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ है कि अगर आपकी mid-day meal योजना न चल रही हो, क्योंकि mid-day meal तमाम छात्रों की उपस्थिति पैदा कर रही है, अगर mid-day meal योजना न हो, तो शायद स्कूलों की संख्या भी बहुत घट जाए। हम तो कहते हैं कि mid-day meal योजना को

[श्री नरेश अग्रवाल]

तुरंत बन्द करना चाहिए। आपकी दो बेसिक योजनाएँ हैं – एक, सर्व शिक्षा अभियान और दूसरी, mid-day meal. आज mid-day meal योजना पर पूरी तरह से ban होना चाहिए, क्योंकि यह पैसा waste जा रहा है। इस पैसे में जितना करप्शन है, मैं बता नहीं सकता कि mid-day meal योजना में कितना करप्शन है। कौन से स्कूल में किचन है?

विपक्ष के नेता (श्री गुलाम नबी आज़ाद): इसको बन्द करने के लिए मत कहिए, आप कहिए कि करप्शन को दूर करिए।

†**قائد حزب اختلاف (جناب غلام نبی آزاد) :** اس کو بند کرنے کے لئے مت کہئے، آپ کہئے کہ کرپشن کو دور کرئیے۔

श्री नरेश अग्रवाल: मेरा जो मानना है, चलिए, आपके कहने से मैं कहता हूँ कि इसको बंद मत करिए, करप्शन को दूर कर दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी): आपकी स्टेट में है।

श्री नरेश अग्रवाल: सिर्फ हमारी स्टेट में ही नहीं, बल्कि सभी जगह ...(**व्यवधान**)... वह आपकी भी स्टेट है। आप खुद ही कहती हैं कि आप मुरादाबाद की रहने वाली हैं, इसलिए स्टेट तो आपकी भी है।

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी: लेकिन सरकार आपकी है।

श्री नरेश अग्रवाल: यह आपकी या हमारी थोड़े ही न होती है! अब दिल्ली में जो सरकार है, हम थोड़े ही न कह रहे हैं कि यह आपकी है, यह हम सबकी सरकार है। यह ठीक है कि हम विपक्ष में हैं और आप सत्ता में हैं, लेकिन इसका मतलब यह थोड़े ही न है कि सरकार किसी की बपौती हो गई! सरकार तो जनता की होती है। मैं मोदी जी की सरकार के बारे में कभी नहीं कहता कि यह हमारी सरकार नहीं है। हम तो कहते हैं कि हमारी सरकार है, इसको कहने में क्या दिक्कत है? मैं हाउस में खुलेआम कह रहा हूँ। सरकार में प्रधान मंत्री आते-जाते रहते हैं, लेकिन सरकार तो हमारी है। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में विरोधी दल की सरकार है, तो फिर हम उसका विरोध करेंगे और इसलिए हम उत्तर प्रदेश की मदद नहीं करेंगे। यह थोड़े ही न हमारी मानसिकता होनी चाहिए! सरकार है, तो सरकार है, चाहे किसी की हो। अब नीतीश जी से चुनाव में आपका इतना झगड़ा हुआ। प्रधान मंत्री जी और नीतीश जी के बीच किस तरह से छत्तीस का आँकड़ा था, लेकिन जब प्रधान मंत्री जी बिहार जाते हैं, तो एक ही मंच पर दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिहार को फंड देने में कमी रख रही हैं। ठीक है, उनकी मांग ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार है, हम सबकी, लेकिन हमारी सरकार किसी चीज की कमी के बारे में कह रही है, तो उस कमी को दूर करना चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान में पूरी कंट्री में आप क्यों नहीं Compulsory Education लागू कर देती हैं? Compulsory Education हो जाए, जब Compulsory Education का एक्ट पास है, तो क्यों नहीं Compulsory Education शुरू होती है? क्या दिक्कत है Compulsory Education में? कोई राज्य तो इसके लिए मना नहीं कर रहा है! आप फंडिग तो करिए! मैंने तो कहा कि अगर

† Transliteration in Urdu script.

देश की शिक्षा पर GDP का 6 परसेंट खर्च कर दिया जाए, तो देश की शिक्षा में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा और देश की शिक्षा एक देखने वाली शिक्षा होगी। इससे आज तमाम शिक्षा के क्षेत्र में जो प्राइवेट लोगों की monopoly हो गई है, वह monopoly भी कहीं न कहीं खत्म होगी। गरीब का बच्चा भी अच्छी शिक्षा ले ले। ऐसा न हो कि गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल से पढ़े, बड़े आदमी का बच्चा कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े और दोनों के बीच एजुकेशन का गैप बहुत अधिक हो जाए, तो मैं समझता हूं कि यह बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। मैं चाहूंगा कि सर्व शिक्षा अभियान को कानून बनाकर कंपल्सरी कर देना चाहिए। आपके जो मिड-डे मील के आंकड़े आए हैं, कई राज्यों ने तो वह मील उठाया ही नहीं था। इनमें हरियाणा भी आता है। हरियाणा के लिए मिड-डे मील का जितना एलॉटमेंट था, उसने उसका केवल 31 प्रतिशत ही उठाया, फिर तमिलनाडु ने 31 प्रतिशत उठाया, पश्चिमी बंगाल ने 35 प्रतिशत उठाया और मध्य प्रदेश ने 36 प्रतिशत उठाया। यह मैं आपको कुछ राज्यों के आंकड़े दे रहा हूं। जब ये राज्य एलॉटमेंट का पूरा भाग उठा ही नहीं रहे हैं, तो बच्चों को पूरी मिड-डे मील कहां से मिलेगी? मैं तो स्कूलों का इंस्पेक्शन करता रहता हूं, स्कूलों में किचन ही नहीं है और रसोइए की जो हालत है, उसके बारे में तो मैं कहना नहीं चाहता हूं। फिर वहां बरतन भी हैं नहीं, ऐसे में काहे का मिड-डे मील है? तमाम जगहों पर मिड-डे मील खाकर बच्चे बीमार पड़ गए हैं। गर्मी में जब 42-44 डिग्री टेम्परेचर होता है, ऐसे में अगर खाना जरा भी खराब हो गया, तो बच्चों के भविष्य का क्या होगा? मैं चाहता हूं कि आप इन चीज़ों में सुधार लाइए।

श्रीमन्, अब मैं स्कूल ड्रॉप रेश्यो की बात करता हूं। स्कूलों में मिड-डे मील की वजह से बच्चे ड्रॉप कर रहे हैं। 2013-14 में 95 प्रतिशत एडमिशन हुए और 36 प्रतिशत बच्चों ने ड्रॉप किया, 2012-13 में 95 प्रतिशत एडमिशन हुए और 39 प्रतिशत बच्चों ने ड्रॉप किया और 2011-12 में 41 प्रतिशत बच्चों ने ड्रॉप किया। अगर इतने बच्चे ड्रॉप करेंगे, तो हमारी एजुकेशन का परसेंटेज कहां से बढ़ेगा? ऐसे में हम चाहे जितनी कोशिश कर लें, लेकिन एजुकेशन का परपज़ पूरा नहीं हो पाएगा।

आपको हर दो किलोमीटर पर एक जूनियर हाई स्कूल जरूर खोलना चाहिए, बल्कि हम तो कहेंगे कि हर एक किलोमीटर पर जूनियर हाई स्कूल खोलना चाहिए। अगर हर गांव में प्राइमरी पाठशाला होगी, तो कम से बच्चे उसमें जा तो सकेंगे, लेकिन अगर ये स्कूल बड़ी दूरी-दूरी पर होते हैं, तो वहां छोटे बच्चे कैसे जाएंगे?

अब आप माध्यमिक शिक्षा ले लीजिए, वह ठीक है। मैं सीबीएसई और आईसीएसई, दोनों बोडर्स की प्रशंसा करता हूं। अब भी दोनों बोडर्स की साख बनी हुई है। बहुत सी स्टेट्स के जो बोडर्स हैं, उन बोडर्स की हालत बड़ी खराब हो गई है। एक ज़माना था, जब कह दिया जाता था कि अगर बिहार की मार्क शीट लाओगे या डिग्री लाओगे, तो वह मान्य नहीं होगी। सब यह मान कर चलते थे कि अगर तुमने बिहार से पास किया है, तो तुम्हारी डिग्री मान्य नहीं होगी, यह स्थिति थी। हमारी स्टेट में भी आज यह हो गया है कि बहुत जगह पर लोग कह देते हैं कि हम बिना टैस्ट लिए एडमिशन नहीं देंगे।

जब हम लोग पढ़ते थे, तो शायद दो-चार लोगों के फर्स्ट क्लास में मार्क्स आते थे, ऐसे बच्चों को बहुत मेधावी समझा जाता था। उस समय फर्स्ट क्लास आना बहुत बड़ी चीज़ होती थी, सबमें चर्चा होती थी कि लड़का फर्स्ट क्लास से पास हो गया है। अब तो कॉलेज में जाओ और पूछो तो 90 प्रतिशत बच्चे फर्स्ट क्लास से पास होते हैं। आज सैकैंड क्लास से पास होने वाला बच्चा

[श्री नरेश अग्रवाल]
तो ढूंढ़े नहीं मिलता है। ऐसा लग रहा है कि अब सब बच्चे फर्स्ट क्लास से ही पास हो रहे हैं। क्या यह एजुकेशन की गुणवत्ता की वजह से हुआ है? आज बच्चों की जो हालत है, उसे आप खुद देख लीजिए। मैं अपने कॉलेज में पूछता हूं, तो वे कहते हैं कि 80 प्रतिशत बच्चे फर्स्ट क्लास से पास हुए हैं। हमें बड़ी खुशी होती है, लेकिन अंदर से हम सोचते हैं कि ये 80 प्रतिशत बच्चे, जो फर्स्ट क्लास से पास हुए हैं, जरा इनकी गुणवत्ता भी देख ली जाए। कक्षा पांच में पढ़ने वाले बच्चे, कक्षा दो की पुस्तकों की रीडिंग नहीं कर सकते हैं, यह तो नीचे की कक्षाओं की स्थिति है।

महोदय, हालांकि माध्यमिक शिक्षा स्टेट का विषय है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए सेंटर को भी इंटरवीन करना पड़ेगा। अगर हम यह कहें कि प्राइमरी शिक्षा नींव है, तो माध्यमिक शिक्षा को हम रीढ़ कह सकते हैं। जब आदमी अच्छी माध्यमिक शिक्षा लेकर आगे बढ़ता है, तभी वह इंटेलिजेंट बनता है। हमारे देश में जितने इंटेलिजेंट लोग हैं, वे सब आज बाहर भागे जा रहे हैं। आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल कॉलेज इत्यादि में जो बच्चे अच्छे नम्बरों से पास करते हैं, मालूम पड़ता है कि सब विदेश चले जा रहे हैं। अगर आप लंदन और अमरीका इलाज करवाने चले जाओ, तो आपको अधिकांश डॉक्टर हिन्दुस्तान के मिलेंगे। हम सोचते यह हैं कि हम इलाज करवाने अमरीका जा रहे हैं, लेकिन वहां पर मिलते हिन्दुस्तान के ही डॉक्टर हैं, क्योंकि हिन्दुस्तान के डॉक्टर ज्यादा अच्छा काम करते हैं। अतः आज जो माध्यमिक शिक्षा का स्तर गिरा है, मैं चाहूंगा कि कहीं न कहीं उसे देखने की जरूरत है। आप माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई में जल संरक्षण, प्रदूषण, रोड सेफ्टी इत्यादि विषयों को भी जुड़वा दीजिए। हर रोज़ रोड एक्सिडेंट्स से कितनी की डेथ्स होती रहती हैं। आज लाइसेंस तो किसी का भी बन जाता है। जब हम ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, तो एक पत्रकार मेरा ही लाइसेंस बनवा कर ले आया। यह देख कर मैं तो हैरत में रह गया। वह मुझसे कह कर गया था कि नरेश जी, मैं आपका लाइसेंस बनवा देता हूं और वह आरटीओ ऑफिस से मेरा लाइसेंस बनवाकर ले आया। मुझे उस आरटीओ को सस्पेंड करना पड़ा। लेकिन अगर इस तरह से ड्राइविंग लाइसेंसेज़ बन जाएँगे और रोड सेफ्टी सिस्टम नहीं होगा, तो क्या स्थिति बनेगी? तो मैं चाहूँगा कि इन चीज़ों को पढ़ाई में अनिवार्य करें।

आज जल संरक्षण भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं कह रहा था कि मैं यह नहीं चाहता कि एजुकेशन में आप बहुत बड़ा चेंज करें, लेकिन जो नेसेसिटी आज हो गई है, उसे भी देखें। एक तो वृक्ष नेसेसिटी हो गई है। आज फॉरेस्ट की कमी के कारण पर्यावरण में पूरा बदलाव हो गया है। तो अगर आजकल इन सब विषयों को हम अपने बच्चों को नहीं सिखाएँगे, तो आगे बढ़ कर वे उनका संरक्षण कैसे करेंगे? उनका संरक्षण करने के लिए हमें कहीं न कहीं यह काम करना चाहिए।

आप कुछ ऐसी गाइडलाइंस बनाइए कि सभी स्टेट्स में रिजल्ट एक ही साथ निकल जाएँ। सीबीएसई की तो information आ गई है कि फलां तारीख को रिजल्ट आएगा, लेकिन राज्यों के रिजल्ट कब आएँगे? किसी राज्य का मई में आएगा, तो किसी का जून में आएगा, यानी हर राज्य का अपना-अपना रिजल्ट आएगा। तो जो बच्चे अलग-अलग समय पर पास हो कर निकलते हैं, उसमें जिनका रिजल्ट पहले आता है, वे दाखिला लेने के समय पहले पहुँच जाते हैं और जिनका रिजल्ट बाद में आता है, उनका दाखिला, रिजल्ट देर से आने के कारण मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कॉलेजेज़ कम हैं, सीट्स कम हैं और बच्चों की संख्या ज्यादा है। आज हर आदमी चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छी एजुकेशन ले। मैं चाहूँगा कि इस पर भी आप विचार करें। इसके लिए मैं

यह कह रहा हूँ कि आप कोई भी क्रांतिकारी कदम उठाइए, लेकिन कहीं न कहीं इसको सफल बनाने के लिए काम कीजिए, ताकि आपने जो 'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, 2000' चलाया, वह सफल तो दिखाई दे। सिर्फ नारा देने से काम नहीं चलेगा कि 'बढ़े चलो', 'पढ़े भारत, बढ़े भारत' या 'बढ़े शिक्षा।' ये नारे तो हम लोगों ने बहुत दिए हैं। हम राजनीतिक लोग तमाम नारे देते हैं, लेकिन अगर वे नारे सही रूप में इम्प्लीमेंट हो जाएँ, तो शायद ज्यादा अच्छा होगा।

अब आप हायर एजुकेशन में UGC और AICTE को देखिए। UGC के अंडर सारी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, मेरे ख्याल में deemed universities भी उसी के अंडर में आती हैं। उनको रेगुलेट करना, शिक्षा का स्तर अच्छा करना, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना, फैकल्टी ठीक हैं या नहीं, शिक्षा का स्तर क्या है, तो आपने UGC के अन्दर NET बनाया है, NET उन चीज़ों को देखता है। मैं कहूँगा कि NET पर पर कुछ अनिवार्यता कर दीजिए। NET जो इंस्पेक्शन करने जाए, तो कुछ चीजें अनिवार्य होनी चाहिए। अगर इसे अनिवार्य नहीं करेंगे, तो हायर एजुकेशन में भी गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी, क्योंकि NET बहुत से ऐसे कॉलेजेज़ को भी सर्टिफिकेट दे देता है, जिनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं होती है। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ। एजुकेशन से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ, मैं आपके सामने कह रहा हूँ। जब तक आप यूजीसी की ग्रांट को नहीं बढ़ाएँगे, तो कैसे काम चलेगा? आज यूजीसी कितनी ग्रांट देता है? वह यूनिवर्सिटीज़ को थोड़ी-थोड़ी ग्रांट देता है। युनिविर्सटी में फीस बहुत कम है। यह ठीक है कि आपने IIM और IIT में फीस बढ़ा दी, लेकिन युनिविर्सटी में कितनी फीस है? जब हम लोग पढ़ते थे, तब वह 12 रुपये थी। अब कितनी है? ...**(व्यवधान)**... अभी यह 40 रुपये है। मैं कह रहा हूँ कि अगर युनिविर्सटी की फीस इतनी है और अगर यूनिवर्सिटीज़ को इनकम नहीं होगी, तो युनिविर्सटी राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड रहेगी और यूजीसी के ऊपर डिपेंड रहेगी। इसलिए उसकी अपनी भी आमदनी होनी चाहिए। अभी 12 रुपये या 40 रुपये में कौन सी एजुकेशन होती है? जब आपकी फीस इतनी बढ़ी, जैसे आपने अभी IIM की फीस बढ़ाई, आपने IIM की फीस 2 लाख रुपये कर दी, तब किसी ने कुछ नहीं बोला। तो फिर आप वहां पर भी देखिए कि अगर युनिविर्सटी की इनकम नहीं बढ़ेगी, तो कैसे काम चलेगा?

डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपकी जो गाइडलाइंस हैं, उनमें कुछ रिलेक्सेशन कीजिए। आज जमीन की दर बहुत ज्यादा है। आपने डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के बारे में यह प्रावधान कर दिया कि इतने एकड़ जमीन होगी, तब यह खुलेगी। यह पहले की है। यह पहले से है। जब अर्जुन सिंह जी एचआरडी मंत्री थे, तब बहुत सी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ बनी थीं। शायद उस समय एक तरफ से तमाम डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ बन गई थीं, लेकिन ये यूनिवर्सिटीज़ बननी रुक गईं, जब बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाई, अब रोक खुली है। मैं कहना चाहूँगा कि इसमें जो इतनी ज्यादा जमीन की अनिवार्यता की बात है, तो आज बड़े-बड़े शहरों में इतनी ज्यादा जमीन कहां है? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऐसा नहीं किया। पहले मेडिकल कॉलेज के लिए 25 एकड़ की बात थी, फिर उसने इसे घटाकर 20 एकड़ किया और small towns में 10 एकड़ को भी उसने अलाउ कर दिया कि आप 10 एकड़ में मेडिकल कॉलेज बनाइए। तो अगर जमीन की कॉस्ट इतनी ही रही और उसको यदि हम जोड़ें, तो एजुकेशन अनइकोनॉमिकल हो जाएगी। तो मैं चाहूँगा कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपकी जो गाइडलाइंस हैं, उनमें कुछ परिवर्तन कीजिए, जिससे कि और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ इस देश में बनें। मान्यवर, मैंने शुरू में जो कहा था कि हमारी यूनिवर्सिटी का स्तर बहुत अच्छा नहीं है, यह ठीक है कि विदेश की तमाम यूनिवर्सिटीज़ हिन्दुस्तान में आना

[श्री नरेश अग्रवाल]

चाहती है। आप रोके हुए हैं, अगर कहीं आप समझौता कर लें, न जाने कितनी... यह भी आज क्वैश्चन ऑवर में उठ रहा था कि तमाम कॉलेजेज़ विदेशों से टाई अप कर लेते हैं। अब वह कौन-सी यूनिवर्सिटी से टाई अप किया, वह बच्चे को 10 या 15 दिन के लिए विदेश भेज देते हैं और फिर उनको उस यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट मिल जाता है। वे कहते हैं कि हम विदेश की यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। चीन, रूस, लंदन, तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लोगों ने पता नहीं कौन-से एमओयू साइन कर रखे हैं? आप कम से कम उन एमओयूज़ को कैंसिल कराइए। यह जो विदेश की यूनिवर्सिटी के नाम पर छात्रों को ठगा जा रहा है, फीस लेकर उनको 15 दिन के लिए विदेश भेज दिया और 15 दिन में वे इतने काबिल हो गए कि वे फॉरेन की एजुकेशन ले आए और उनको सर्टिफिकेट दे दिया गया, इस तरह के सर्टिफिकेट पर आपको रोक लगानी होगी। मैं चाहूंगा कि इस पर कहीं न कहीं आपकी रोक होनी चाहिए।

एआईसीटीई सीटें बढ़ाने में बहुत दिक्कत करती है। यह ठीक है कि आपने एमबीए कर रखा है, एमबीए जाता है, जांच करता है, देखता है, लेकिन आज अगर डिमांड ज्यादा है, लोग ज्यादा इंजीनियर बनना चाहते हैं, ज्यादा लोग मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहते हैं, तो फिर अगर चीजें अच्छी उपलब्ध हैं, तो एआईसीटीई को सीट बढ़ाने में क्या दिक्कत है? एक कोर्स की 60 सीटें एक बार में देती है। अगर वह इसको एक बार में 100 सीटें कर दे, तो ज्यादा अच्छा हो। मेडिकल काउंसिल ने नहीं किया? पहले 100 सीटें देते थे, अब तो उन्होंने 200-250 सीटें कर दीं। जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस हिसाब से उन्होंने सीटें बढ़ा दीं। अगर एआईसीटीई भी अच्छे कॉलेजेज़ में सीटें बढ़ा देगी, तो बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी। कुछ कॉलेजों में जो डोनेशन की प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया अपने आप समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जब डिमांड ज्यादा होगी और आवक कम होगी, तो automatic black marketing बढ़ जाएगी। अगर दोनों चीजों को बराबर कर दिया जाए, तो मैं समझूंगा कि एआईसीटीई और यूजीसी का जो काम है, जो मेन काम है, वह काम पूरा हुआ।

हमारे उत्तर प्रदेश में मात्र चार सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। जब जोशी जी शिक्षा मंत्री बने थे, तब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया गया। अब इतना बड़ा प्रदेश, जहां 22 करोड़ की आबादी हो, वहां सेंट्रल यूनिवर्सिटी मात्र चार हैं! आप उत्तर प्रदेश को भी एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी दे दें। मैं कहूंगा कि पूर्वांचल में दे दीजिए। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो जाए। अभी एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, एक बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी है, एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है और एक लखनऊ में डा. भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है। ये चार सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। मेरी यह मांग है कि एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी बढ़ जाए। मैं तो कहूंगा कि इसकी घोषणा कर दी जाए। मैं तो ऐसे ही आपका बहुत प्रशंसक हूँ, तब और प्रशंसा करूंगा कि चलिए, हमारे कहने पर आपने यही घोषणा कर दी, उत्तर प्रदेश को कुछ दे दिया, क्योंकि वहां हमारी सरकार है, आपकी नहीं है। यहां आपकी सरकार है, लेकिन वहां हमारी है। इस नाते ही अगर आप घोषणा कर देंगी, तो मैं समझूंगा कि हमारा और आप वाला झगड़ा खत्म हो जाएगा।

श्री बैष्णव परिडा (ओडिशा)ः इसी से खत्म हो जाएगा?

श्री नरेश अग्रवालः कहीं न कहीं कुछ तो प्रदेश को मिले। आप भी तो ओडिशा के लिए रोज कितना लड़ाई लड़ते हैं, मैं तो देखता हूँ। जरा-जरा सी बात पर आप ओडिशा के लिए लड़ने

4.00 P.M.

लगते हैं। मैं तो चाहूंगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ पूरे देश में बढ़ें और एजुकेशन का स्तर बढ़े। हम तो कहेंगे कि कम से कम कोई एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी इस स्तर की कर दीजिए कि उसका नाम विश्व की यूनिवर्सिटीज़ में आ जाए। विश्व की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में हिन्दुस्तान की भी कम से कम एक यूनिवर्सिटी का नाम आ जाए कि हिन्दुस्तान की भी एक यूनिवर्सिटी में विश्व स्तर की पढ़ाई हो रही है और एजुकेशन का स्तर बढ़ा। आप इसको चाहे आलोचना समझ लीजिएगा या चाहे सुझाव समझ लीजिएगा। ...(**समय की घंटी**)...

मान्यवर, मैं मिड-डे मील के संबंध में फिर कहूंगा कि मिड-डे मील में जो भ्रष्टाचार है, उसको रोकने का आप कोई उपाय कीजिए। यह ठीक है कि मिड-डे मील चालू रहनी चाहिए, क्योंकि बहुत-से गरीब बच्चे हैं, जिनको इसी बहाने खाना मिल जाता है। अगर मिड-डे मील में भ्रष्टाचार को रोकने का कोई उपाय आप करेंगी, तो शिक्षा के स्तर में भी सुधार होगा और हम सब जो चाहते हैं कि सबको अच्छी शिक्षा मिले, हमारे देश में भी अच्छी शिक्षा मिले, उसमें हम सफल हो सकेंगे। ...(**समय की घंटी**)... इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए यह आशा करता हूँ कि जब आप रिप्लाई देंगी, तो इन बातों का जवाब जरूर देंगी।

श्रीमती विप्लव ठाकुर (हिमाचल प्रदेश)ः माननीय उपसभापति जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे Ministry of Human Resource Development की वर्किंग पर बोलने का मौका दिया। शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसके साथ देश की उन्नति, देश की प्रगति, देश की आने वाली पीढ़ियों का भविष्य जुड़ा हुआ है। शिक्षा को हमें एक विभाग या मिनिस्ट्री के तौर पर नहीं देखना चाहिए। यह एक ऐसा मंत्रालय है, जिसके साथ भारत की युवा पीढ़ी का भविष्य जुड़ा हुआ है, उनका फ्यूचर जुड़ा हुआ है, इससे उनका आने वाले फ्यूचर बनता है। शिक्षा को हासिल करना हर नागरिक का अधिकार है, इसीलिए Right to Education का बिल पास किया गया।

[**उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया)** *पीठासीन हुए*]

शिक्षा कहां से शुरू होती है? बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले वह अपनी मां को देखता है, उसके बाद वह बाप को पहचानता है, उसके बाद वह बाकी रिश्तेदारों को जानता है। उसके बाद वह अपने दायरे में आकर कुछ सीखने की कोशिश करता है और फिर वह स्कूल जाता है। उसे शिक्षा के नाम पर जो सबसे पहले मिलता है, वह प्राथमिक शिक्षा है। शिक्षा को हम कई भागों में बांट सकते हैं— प्राथमिक शिक्षा, एलिमेंटरी शिक्षा, हायर शिक्षा, टेक्नीकल शिक्षा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की शिक्षा। इस तरह से उसे काफी भागों में बांटा जा सकता है। जहां तक Grants-in-aid की बात है, मुझे अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि शिक्षा का बजट यूपीए सरकार के मुकाबले में काफी कम हुआ है। मैं इस बात के लिए बधाई देती हूँ कि इस बार यह कुछ बढ़ा है, लेकिन हम अपनी जीडीपी का मात्र तीन परसेंट ही अपनी शिक्षा पर खर्च करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, उन्नति करे!

यहां कई तरह के नारे दिए जाते हैं। एक "मेक इन इंडिया" का नारा है, एक "उठो भारत" का नारा है और एक "गांव को बढ़ाओ" का नारा है। इस तरह की कई बातें की जाती हैं, लेकिन जो सबसे जरूरी है, जो बना सकती है, वह शिक्षा है और उसके नाम पर हमारे पास कुछ नहीं है। इसलिए मैं सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा की बात करूँगी। मुझे मालूम है कि मंत्री जी कहेंगी कि

[श्रीमती विप्लव ठाकुर]

शिक्षा राज्य सरकार का विषय है, लेकिन मैं यह कहना चाहूँगी कि पॉलिसी यहां से भी बनती है। आज हमें जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, वह प्राथमिक शिक्षा है। आप गांवों में जाइए, वहां के स्कूलों की हालत देखिए। वहां बच्चे इस तरह से बैठे होते हैं, जैसे कोई बच्चा फुटपाथ पर बैठा हो। वहां बैठने के लिए बैंचेज़ नहीं हैं, स्टूल्स नहीं हैं। आज लोग कॉन्वेंट स्कूल या पब्लिक स्कूल की तरफ जा रहे हैं, यह सोचने की बात है, क्योंकि वहां पर टाई लगाकर, स्कर्ट पहनकर जाने वाले बच्चों को बैठने के लिए जगह मिलती है और मां-बाप यह सोचते हैं कि हम जो नहीं कर सके, वह हमारे बच्चे कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहूँगी कि गवर्नमेंट के जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, उनका स्तर बढ़ाया जाए। उसके लिए हमें यहां केंद्र से प्रावधान करना पड़ेगा।

आप देखिए, मैं भी पढ़ी हूँ, आप भी पढ़े हैं। जब हम छोटे थे, तब हम पहली क्लास में गए। हमें अ, आ, इ, ई सीखनी है, हमें एक, दो, तीन सीखना है, जबकि पांच क्लासेज़, यानी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवीं क्लास के लिए केवल दो अध्यापक हैं! इससे क्या नींव बनेगी, क्या फाउंडेशन बनेगी? अभी नरेश भाई कह रहे थे कि वे आठवीं पास करके 90 परसेंट ले आए, लेकिन उनको लिखना नहीं आता। उनको लिखना कहां से आएगा, उनको कौन पढ़ाएगा, उनके ऊपर कौन ध्यान देगा? हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं, हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, हम IITs की बात करते हैं, हम IIMs की बात करते हैं, हम मेडिकल कॉलेजेज़ की बात करते हैं, लेकिन जहां से हमारी फाउंडेशन बननी है, जहां से हमारी नींव बननी है, उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए मैं चाहूँगी कि पहले हमें प्राथमिक शिक्षा को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि वे बच्चे कच्चे होते हैं। कहते हैं कि बच्चा कच्चे घड़े की तरह होता है, उसको जैसे मर्जी ढाल लीजिए, उसको शेप दे दीजिए। वह शेप कौन दे सकता है — वहां का जो अध्यापक है, वह दे सकता है। इसलिए मैं चाहूंगी कि आप पॉलिसी बनाइए, यह जरूरी कीजिए कि पांच क्लासेज़ के लिए पांच टीचर्स होने चाहिए, जो उन बच्चों पर ध्यान दे सकें, उनकी नींव को पक्का कर सकें, उनकी फाउंडेशन को पक्का कर सकें। फिर ही हम एलिमेंटरी शिक्षा में जाएं, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गरीबी और अमीरी का डिफरेंस तो बढ़ ही रहा है, लेकिन गांवों और शहरों की शिक्षा का अंतर भी बढ़ रहा है। आप देखिए कि कितने गांवों के बच्चे मेडिकल कॉलेजेज़ में जाते हैं या आईआईटीज़ में जाते हैं या आईआईएम्ज़ में जाते हैं या बायो टेक्नोलॉजी में जाते हैं। आप उनकी परसेंटेज देखिए — वह न के बराबर है। उनके पास ठीक ढंग से शिक्षा प्राप्त करने का प्रावधान ही नहीं है, टीचर्स नहीं हैं। मैं यही चाहूंगी कि स्मृति जी, आप इस बात पर ध्यान दीजिए, पॉलिसी बनाइए कि हमें अपनी प्राथमिक शिक्षा को मज़बूत करना है, नींव को मज़बूत करना है, तभी हमारी आने वाली पीढ़ियां सही ढंग से चल सकेंगी, आगे बढ़ सकेंगी। इसलिए सबसे पहले तो मुझे यही कहना है क्योंकि मैं गांवों में जाती हूं, मैं देखती हूं, वहां दो टीचर्स हैं, वे आपस में पूल कर लेते हैं, एक छुट्टी पर चला जाता है और कहता है कि मेरी एप्लिकेशन ले लेना, अगर कोई पूछने आ गया तो वह एप्लिकेशन दे देना कि मैं छुट्टी पर हूं।

सर्व शिक्षा अभियान में भी आपका बजट कम हो गया है। अब उनके पास कमरे बनाने के लिए पैसे नहीं हैं, मेंटेनेंस के लिए कोई पैसे नहीं है। गांव की पंचायत क्या करेगी? उसकी इन्कम कितनी है? हमारे यहां तो पंचायतों की इन्कम तो है नहीं, शहरों में, बड़े-बड़े प्रदेशों में होगी मैं कह नहीं सकती, इसलिए इसकी तरफ भी आपको ध्यान देना होगा। जब हमारी प्राथमिक शिक्षा

की फाउंडेशन बन जाएगी, तभी हम आगे जा सकेंगे। फिर माध्यमिक शिक्षा की बारी आ जाती है, एलिमेंटरी शिक्षा की बारी आ जाती है। वहां पर भी टीचर्स कम हैं। स्कूल्स बहुत खुल रहे हैं। इसके लिए भी मैं चाहूंगी, जैसे आपका बीएड कॉलेजेज़ के लिए बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड है, उसी तरह से कॉलेज खोलने के लिए भी प्रदेश में बोर्ड बनाइए। कहीं के भी मुख्य मंत्री हैं, वे इस तरह से प्रदेश में कॉलेज खोल रहे हैं, व्हिम्स के ऊपर खोल रहे हैं, चाहे वे एमएलएज़ के हैं या लीडर्स के हैं, जिनमें न तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, न लेक्चरर्स हैं और न ही सही ढंग की शिक्षा है। हम डिग्री कॉलेजेज़ में हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस पढ़ाकर बेरोज़गारों की पूरी की पूरी लाइन खड़ी कर रहे हैं। न वहां साइंस है, जिसकी आज हमें जरूरत है, न बीकॉम है, न इकोनॉमिक्स है, न कॉमर्स है। गांव के बच्चे बीए की डिग्री लेकर घूमते हैं कि हमने ग्रेजुएशन कर ली है, हमें नौकरी दीजिए। फिर हम उन्हें कहते हैं, भाई, इससे अच्छा आपने कोई स्किल का काम किया होता, प्लम्बिंग का काम सीख लिया होता, इलेक्ट्रिशियन का काम सीख लिया होता, ड्राफ्ट्समैन का काम सीख लिया होता, पंप ऑपरेटर बन जाते तो हम आपको नौकरी दिला देते, बीए के बाद आपको नौकरी नहीं मिलने वाली है। इस चीज़ पर भी आप ध्यान दीजिए। ये जो मशरूम की तरह प्रदेशों में कॉलेजेज़ खुल रहे हैं, उनको रोकिए, तभी हमारी क्वॉलिटी एजुकेशन हो सकेगी। क्वांटिटी से फर्क नहीं पड़ेगा, क्वांटिटी बहुत हो गयी, अब इसको क्वॉलिटी में लाने की कोशिश कीजिए। We know that it is a State subject, but जो सर्व शिक्षा अभियान गया, वह यहीं से गया, केंद्र सरकार से गया, मिड-डे मील गया, वह भी केंद्र सरकार से गया, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि यह विषय राज्य सरकारों का है, राज्य सरकारें इसे देखेंगी। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इसके बारे में भी कोई नीति बनाइए। आज बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ खुल रही हैं – इस तरह से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ खुलती जा रही हैं, उनको ज़मीनें दे दी जाती हैं, 90-90 साल की लीज़ पर ज़मीनें दे दी जाती हैं और वे यूनिवर्सिटीज़ खोलने के बजाय पता नहीं वहां क्या-क्या काम करते हैं, क्या उनका और काम होता है? A university is a university. उसके लिए भी एक पैमाना होना चाहिए, उसके लिए भी नॉर्म्स होते हैं। ठीक है, रेगुलेटर हो गए हैं, आपने अपने जवाब में भी बताया। मैं मानती हूं कि वे हैं, हर प्रदेश में रेगुलेटर्स हैं, लेकिन वे कितना देख पाते हैं, कितना देखने के बाद वे यूनिवर्सिटीज़ के लिए परमिशन देते हैं? ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर भी लगना चाहिए, जिससे कि बच्चों को सही एजुकेशन मिल सके ।

मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि आज समय आ गया है कि हम अपने बच्चों को गाइड करें कि आज किस कोर्स की जरूरत है, किस कोर्स से उनको employment मिल सकता है। हमारी नीड बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए, केवल शिक्षा के लिए शिक्षा नहीं होनी चाहिए। हमारे यहां करोड़ों बच्चे unemployed हैं, वे इसीलिए हैं कि उनके पास कोई गाइड नहीं है, उनको कोई बताने वाला नहीं है कि बच्चों, इस तरफ जाइए। आप स्कूलों में, सेकेंडरी स्कूलों में ऐसा एक गाइड रखिए जो उन बच्चों को गाइड कर सके, उनके aptitude के मुताबिक, अगर बच्चा साइंस में अच्छा है, तो उसको प्रोत्साहित कर सके कि आप साइंस लीजिए, आपको मेडिकल में, नॉन-मेडिकल में एडमिशन मिल सकता है, आपका भविष्य बन सकता है। हमारे ज़माने में ज्यादा कोर्सेज़ नहीं थे— लॉ, डॉक्टर और इंजीनियर के कोर्स थे। आज तो इतने अच्छे कोर्सेज़ आ गए हैं, आज तो शिक्षा का इतना ज्यादा विस्तार हो चुका है कि हम उनको गाइड कर सकते हैं कि आप biotech में जाइए, आप information technology में जाइए, आप कम्प्यूटर सीखिए, कम्प्यूटर को रिपेयर करने का काम सीखिए, आपको घर में बैठकर employment मिलेगा, लेकिन गांव के

बच्चों को कोई गाइड करने वाला नहीं है, उनको कोई समझाने वाला नहीं है। इस बारे में आप सोचिए और इस तरह से पॉलिसी बनाइए, जिससे हमारे देश का बच्चा, हमारे देश का नौजवान आज भटके नहीं।

आज पंजाब में क्यों कहा जा रहा है कि ड्रग्स आ गईं, आज और जगह पर क्यों बात कही जा रही है, क्योंकि उनके पास कोई ध्येय नहीं है, कोई मकसद नहीं है, उनके पास कोई उद्देश्य नहीं है। उन्होंने पढ़ाई जरूर कर ली है, लेकिन नौकरी नहीं है। कितनी मेहनत करके उनके मां-बाप पढ़ाते हैं, वे अपना पेट काटकर अपने बच्चे को शिक्षा देते हैं, इस आशा में कि इसकी नौकरी लग जाएगी, हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे, हम अच्छे बन जाएंगे। इसलिए इस शिक्षा को व्यापार मत बनने दीजिए, शिक्षा को शिक्षा ही रहने दीजिए। इसी से हमारे देश की उन्नति होगी। जैसा कि अभी नरेश जी ने कहा कि हमारे देश में इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, फिर भी हम वर्ल्ड के नक्शे पर नहीं आ रहे हैं। हम क्यों नहीं आ रहे हैं, यह सोचने की बात है, यह समझने की बात है? मैं आपसे कहूंगी कि आप इस तरफ ध्यान दीजिए। इसके लिए पॉलिसीज़ बनाइए। प्रदेश की सरकारों जरूर उसको इम्प्लीमेंट करेंगी। इसके साथ ही साथ बजट के बारे में भी सोचिए।

मैं एक और बात कहना चाहती हूं, जो कि बहुत ही दुख और दर्द की बात है। शिक्षा को भी आप एक राजनीतिक अखाड़ा बनाने जा रहे हो। यूनिवर्सिटीज़ एक battle बनती जा रही हैं, एक संघर्ष का मैदान बनती जा रही हैं, आप वहां पर ऐसा मत होने दीजिए। जो शिक्षा ले रहा है, उसको मत किसी राजनीति से जोड़िए। उसे मत इंगित कीजिए, मत उसको प्वाइंट आउट कीजिए, देश को बांटने की कोशिश मत कीजिए। देश के जो पुराने intellectuals हैं, जो historians हैं, जिन्होंने history लिखी है, उन्होंने वह history उस ज़माने के context में लिखी है, उसको आज पढ़ने की कोशिश की जा रही है। उसको उस तरह से बनाया जा रहा है, किताबों को बैन किया जा रहा है, किताबों को हटाया जा रहा है, हम कौन सी संस्कृति की बात करते हैं? मैं आप लोगों से पूछती हूं कि कितने लोगों के बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते हैं और इंग्लिश की पढ़ाई भी करते हैं? वे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं। पहले हम इसको अपने पर लागू करें, फिर दूसरों को बताएं। मैं आप लोगों से यही पूछना चाहती हूं। हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, हम बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। हम रखवाले बनते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? खुद क्या करते हैं, खुद हम कहां जाते हैं, तो क्या वह उदाहरण नहीं है? पहले हमें उदाहरण पेश करना पड़ेगा, फिर आगे अपनी बात चलानी पड़ेगी। मैं फिर से यह बात कहूंगी कि यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजों को ऐसा मत बनने दीजिए, जो देश को बांट दें, बच्चों को बांट दें और आज एक ऐसा वातावरण खड़ा कर दें कि जिसके लिए हमें बाद में पछताना पड़े। हमने बड़ी मुश्किल से आज़ादी ली है, हमने इसे बड़ी मुश्किल से हासिल किया है। हजारों लोग जेलों में गए हैं, हजारों लोगों ने गोलियां खायीं हैं, लाठियां खाईं हैं और उसके बाद यह आज़ादी मिली है। कांग्रेस ने आज़ादी को इतने सालों तक सम्भाल कर रखा है। आप इसको मत तोड़िए, इसको मत गिराइए, पुरानी संस्कृति के नाम पर इसको बिखरने मत दीजिए, मेरा आपसे यह कहना है, अनुरोध है। कहते हैं कि अगर मां शिक्षित है, तो सारा परिवार शिक्षित है, इसलिए यह कहना ...(**समय की घंटी**).... कि उन्हें पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। मैं आपसे यही कहना चाहती हूं कि आपने दुनिया घूमी है, बहुत कुछ देखा है, इसलिए अपने mindset को आगे ले जाइए और ऐसे लोगों से बचिए, जो ऐसी संस्कृति और ऐसी बातें बताना चाहते हैं। हमारा एक इतिहास है, हमारी हिस्ट्री है, हमारे वेद हैं, सब हैं और इससे कोई इन्कार नहीं करता है, लेकिन धर्म के

नाम से शिक्षा को मत जोड़िए। आप पहले यह देखिए कि क्या यह सच है? हमारा रिसर्च विंग ही नहीं है। ...**(व्यवधान)**....

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): आप पूरा करिए।

श्रीमती विप्लव ठाकुर: मैं conclude ही कर रही हूं। हमारा कहीं भी रिसर्च विंग नहीं है। हमारे जो साइंस के बच्चे एम. फिल. और पी.एच.डी. कर रहे हैं, वे रो रहे हैं कि हमारे पास लैब्स नहीं हैं, हमारे पास रिसर्च करने के लिए कुछ नहीं है। जब वे बाहर जाते है, इतने बड़े-बड़े नाम कमा लेते हैं, खुराना ने नोबेल प्राइज़ ले लिया। वह भी तो यहीं से पढ़ा हुआ था। हमारे पास प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे पास कमी है, तो साधनों की कमी है, हमारे पास कमी है, तो सोच की और विज़न की कमी है। मैं चाहती हूं कि आप इसको पूरा करें और एक नई क्रांति लाएं तथा शिक्षा को आगे बढ़ने में एक नई दिशा प्रदान करें, ताकि यह आगे जा सके। भारत में भी बहुत intellectual, अच्छी शिक्षा वाले रहते हैं और हम गर्व से कह सकें कि हम भारतीय हैं और शिक्षा में हमारा नाम है, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री प्रभात झा: आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आज मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कार्यकरण पर चर्चा हो रही है और इस गंभीर चर्चा में अच्छे विचार आ रहे हैं। चाहे स्वामी विवेकानन्द हों, महर्षि अरविन्द हों, सर्वपल्ली राधाकृष्णन हों, डॉ, राजेंद्र प्रसाद हों या डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों, जितने भी इस देश के शिक्षाविद हुए, उनके दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हुआ करते थे कि जिस देश की शिक्षा और संस्कृति प्रबल होगी, उस देश का तंत्र और लोकतंत्र बहुत मजबूत होगा। मुझे खुशी है कि इन शिक्षाविदों के इस शिक्षण से वर्तमान मानव संसाधन विकास मंत्रालय उसी रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा है। चिंता व्यक्त करना और चिंता के साथ चिंतन करना, यह शिक्षण और शिक्षा का स्वभाव होता है। इसलिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 30 वर्षों के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने की तरफ ध्यान दिया है। हम सबको आश्चर्य होगा कि जैसे अभी विप्लव जी ने चिंता व्यक्त की कि सबका involvement होना चाहिए, तो देश में व्यक्तिगत स्तर पर लोगों से सुझाव लेने की शुरुआत हुई है। स्कूली शिक्षा के मामले में 1,10,506 गांवों में, 3,249 ब्लॉकों में 742 अर्बन लोकल बॉडीज़ और 339 जिले और 18 राज्यों में grass root consultation report *www.mygovernment.in portal* पर upload किए गए। विप्लव जी, आपने जो राष्ट्रीय शिक्षा की बात कही है, तो सरकार ने इतने वर्षों बाद एक सामरिक और जिसको कहते हैं, सामूहिक निर्णय लेने की कोशिश की है। यह तो प्राइमरी शिक्षा में हुआ है। यदि इससे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे..... क्योंकि सरकार जो कदम उठाती है, उस ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए। सरकार किसी एक पार्टी की नहीं होती बल्कि सरकार सबकी होती है। उसके निर्णय से देश का हर व्यक्ति प्रभावित होता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि शिक्षा के मामले में 2,722 ब्लॉक्स, 925 अबर्न लोकल बॉडीज़, 405 जिले और 17 राज्यों में grass root consultation report portal पर upload किए गए हैं।

सभी stakeholders के सुझावों को महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि शिक्षा सबकी है। आज भारत के लिए शिक्षा आवश्यक है। यह आज से आवश्यक नहीं है, यह सनातन काल से आवश्यक है। इस सच को हर सरकार जानती है, इसीलिए इस सरकार ने प्रत्येक व्यक्ति को इसमें involve करने की कोशिश की। एक कमेटी गठित की गई है, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अंतिम रूप देगी। मैं छोटी-छोटी बातें बताना चाहूंगा। National Institutional Ranking Framework का गठन

[श्री प्रभात झा]

किया गया। जो बातें की जाती हैं, उनको बताना भी चाहिए, क्योंकि विरोध का अर्थ यह नहीं होता कि हम सिर्फ विरोध करें। मैं यह निवेदन सिर्फ इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि विश्व में जो सबसे बड़ा सहभागी ranking क्रिया कलाप है, उसके लिए इसका गठन किया गया है। पहली बार joint counselling लागू की जा रही है। इसको IIT, NIT एवं अन्य संस्थाओं को विभिन्न undergraduate programmes के लिए लागू किया जा रहा है। जो आपकी चिंता है, सरकार उसको समझ रही है। आपकी शिक्षा के प्रति जो चिंता है, वह देश की चिंता है और हर देश चाहता है कि उसका नागिरक शिक्षित हो, इसलिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। IIT Bill, 2014 को gazette में notify किया गया, जोकि चार IIT's, इलाहाबाद IIT, ग्वालियर IIT, जबलपुर IIT और कांचीपुरपम् IIT को स्वायत्तता प्रदान करता है। इतना ही नहीं, सरकार ने, प्रधान मंत्री जी ने विकलांग का नाम "दिव्यांग" करने के लिए कहा, उन "दिव्यांग" छात्रों को IIT में निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का ऐतिहासिक फैसला वर्तमान मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने किया। अच्छी बातों को कहना चाहिए और अच्छी बातें किसी के विरोध के बाद भी रुकती नहीं हैं। इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा हूं। यह October, 2015 से लागू हो चुका है। उच्च शिक्षण संस्थाओं में महिलाओं के विरुद्ध harassment को रोकने के लिए "UGC कानून, 2015" लागू किया गया है। यह चिंता इस सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने व्यक्त की है। उच्च शिक्षण संस्थाओं में छात्रों की सुरक्षा के लिए कानून बनाया गया है। UGC की सभी योजनाओं में transgender को third gender के रूप में मान्यता दी गई है। Bachelor of Vocation Study Programme आरंभ किया गया है। इतना ही नहीं कौशल विकास में certificate course को लेकर Ph.D. तक की डिग्री प्रदान करने के लिए "दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र" स्थापित किए जा रहे हैं। यह काम लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय विश्वविद्यालय और deemed विश्वविद्यालयों में कोई एक वित्त प्रबंधन व्यवस्था के तहत भुगतान करने की व्यवस्था की गई है, जिसमें पूरी तरह से पारदिर्शता रखी गई है। NCERT के तहत् पहले तीन वर्षों में National Achievement Survey किया जाता था, जिसमें कुछ क्षेत्र शामिल किए जाते थे, लेकिन इस बार से यह हुआ है कि अब यह सर्वे वार्षिक तौर पर होगा और सभी क्षेत्रों के सभी वर्गों को एवं सभी विषयों को इसमें शामिल किया जाएगा। यह फैसला पहले नहीं हुआ, यह फैसला वर्तमान मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने किया है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी। अभी नरेश जी चिंता व्यक्त कर रहे थे, उन्होंने सरकार के बारे में नहीं, उत्तर प्रदेश की शिक्षा प्रणाली के बारे में बताया। वे जो स्वयं बोल रहे थे, उससे लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रणाली ठीक नहीं चल रही है। National Council for Teacher Education के तहत् नए integrated teacher education programme शुरू किए जा रहे हैं। यह इसी सरकार की देन है। Technology का शिक्षा के क्षेत्र में पूरा उपयोग किया जा रहा है। National Apprenticeship Training Scheme के national web portal, इसी सरकार ने आरंभ किए हैं। IGNOU का e-Gyankosh Digital Repository, जिसे 2013 में deactivate कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था, रोक दिया गया था, उसे restore किया गया है और दूरस्थ शिक्षा व open learning द्वारा शिक्षा ले रहे लाखों छात्रों को इससे लाभ पहुंचाने की बात की गई है। अगले academic session से सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में online admission की शुरुआत की गई है। बहुत सारे आरोप लगते थे कि यह किसने किया? यह इसी मंत्रालय ने किया है। Know Your College Portal नवंबर, 2014 में आरंभ किया गया। मैं ये बातें डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि सरकार के

किए गए अच्छे कार्यों की जानकारी सबको होनी चाहिए। होता यह है कि हम अखबारी जानकारी रखते हैं और संपूर्ण जानकारी की ओर नहीं बढ़ते हैं। केंद्रीय विद्यालय में online admission हो रहा है, e-classroom आरम्भ कर दिया गया है। ...**(व्यवधान)**... आगे सुन तो लीजिए। उसकी व्यवस्था भी यही सरकार करेगी न, जो जहां नहीं है, लेकिन जो हो रहा है, उसको समझने की, उसको सराहने की और उसको बढ़ाने की बात अवश्य होनी चाहिए। Visual class आरम्भ की गई है। केंद्रीय विद्यालय में बैंक के माध्यम से fee collection की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। Go Green School Building Project के तहत काम किया जा रहा है। On Demand Examination System पूरे भारत में 500 केंद्रीय विद्यालयों के माध्यम से आरम्भ किया गया है, जो अपने आप में जीवटता भरा निर्णय है। National Digital Literacy Mission के तहत Online Assessment and Certification की प्रणाली आरम्भ कर दी गई है। इतना ही नहीं, Central Board of Secondary Education (CBSE) द्वारा technology का उपयोग करते हुए उठाए गए सुधारात्मक कदम मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। 'Digital India Programme', यह किसने शुरू किया है? E-CBSE portal का आरम्भ किसने किया है? 'Saransh' नामक In- house Decision Support System की शुरुआत किसने की है? Practical परीक्षा का डिजिटीकरण किसने किया है? शिक्षकों की सुविधा के लिए 'Online Internal Assessment Grade Collection System' की शुरुआत किसने की है? प्राइवेट छात्रों के लिए 'Online Application System' की शुरुआत किसने की है? प्रतिस्पर्द्धात्मक परीक्षा के लिए 'Online Free Examination System' हमने प्रारम्भ किया है। प्रतिस्पर्द्धात्मक परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए OMR Sheet की image को उपलब्ध कराना, यह हमारी सरकार ने शुरू किया है। देश और विदेश में कंम्प्यूटर आधारित टेस्ट संचालित किया जा रहा है। बोर्ड परीक्षाओं के लिए 'Online Pre-exam System', उत्तर पुस्तिकाओं की digital marking, mobile app द्वारा 'Certificate Verification System', यह लागू हो रहा है। ये छोटे काम नहीं हैं। यह इतना बड़ा reform हो रहा है, इसको आज समझने की जरूरत है।

सर, इसी तरह से 'उन्नत भारत अभियान' के तहत सभी तकनीकी व उच्च शिक्षा संस्थानों से 5 गांव गोद लेने को कहा गया है। गांव के बारे में अभी विप्लव जी ने चिन्ता व्यक्त की। यह क्यों कहा गया है? यह इसलिए कि अगर गांव मजबूत होगा, अगर गांव में शिक्षा का केंद्र बनेगा, यदि गांव आधार बनेगा, तो देश आगे बढ़ेगा। यह हमारी सरकार की प्राथमिकता है। गांव बढ़ेगा, तो देश बढ़ेगा, गांव बनेगा, तो भारत बनेगा और उसी दिशा में इन शिक्षण संस्थानों को 5 गांव गोद लेने के लिए कहा गया है। IIT, Delhi को इसका National Coordinator बनाया गया है। ऐसे हवा में बातों नहीं हो रही है।

सर, इसी प्रकार 'Skill Assessment Matrix for Vocational Advancement of Youth' कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। इन सब जानकारियों से लोगों को लाभ मिलता है। जब यह जानकारी नहीं होती है, तो जन-प्रतिनिधि होने के नाते हम यह समझते हैं कि हमारा एक और दायित्व है कि सरकार की जानकारी को हम अपनी जनता, जिसने हमें चुन कर भेजा है, उन तक ले जाएँ, इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा हूँ।

सर, इसी तरह से कौशल विकास के क्षेत्र में NICT द्वारा इंजीनियरिंग क्षेत्रों के लिए 'प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना' है। यह छोटी बात नहीं है। हम रोजगार के लिए रो रहे हैं। कौशल

[श्री प्रभात झा]

से रोजगार मिलेगा। इससे इस दिशा में रोजगार ही नहीं मिलेगा, बल्कि वह 10 लोगों को रोजगार भी दे पाएगा।

इसी प्रकार 'स्वच्छ विद्यालय कार्यक्रम' की शुरुआत की गई है, जिसके तहत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में शौचालय बनाए जा रहे हैं। यह कितनी बड़ी बात है कि प्रधान मंत्री को आजादी के 68 साल बाद लाल किले से यह कहना पड़ा कि शौचालय बनाना है और 4.5 लाख शौचालय बनाए गए। हम किसी को दोष नहीं देंगे, लेकिन यह सोच की बात है। इस देश में स्वच्छता की बात गांधी जी के बाद किसने की है? इसलिए इस मिशन के प्रति अगर भारत सरकार का मानव संसाधन मंत्रालय कुछ करता है, तो हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, हमें उसको धन्यवाद देना चाहिए।

सर, प्रधान मंत्री द्वारा Teachers' Day celebrate करने के लिए नए आयाम स्थापित किए गए, जिसके तहत प्रधान मंत्री video conferencing द्वारा देश के स्कूल के लाखों बच्चों के साथ जुड़े। सबके मन में यह बात होती है कि मेरा प्रधान मंत्री मुझसे बात करे और उन्होंने इसके लिए पूरा समय निकाला। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिन पर 5 सितम्बर को उन्होंने देश के बच्चों के साथ, आने वाली पीढ़ी के साथ बात करके उन्हें एक ऐसा अवसर दिया और उन्हें वह गौरव प्रदान किया कि तुम उस भारत के हो, जिस भारत में एक नहीं, अनेक लाल पैदा हुए हैं। उन्होंने उनको एहसास कराया कि तुम आने वाली पीढ़ी हो, तुमको सजाने-सँवारने और बनाने का काम भारत का है, मैं उसके लिए प्रतिबद्ध हूँ और मैं यह काम कर रहा हूँ। National Book Trust द्वारा परमवीर चक्र अवार्डियों की वीर गाथा प्रकाशित की गई है। यह काम आज तक नहीं हुआ था। हम वीरता का गुणगान तो करते हैं और कहते हैं कि हमारे शहीदों ने खून बहा दिया तभी भारत आजाद हुआ, लेकिन हमने उन परमवीर चक्र प्राप्त लोगों की जीवनी कहीं भी एकतित्र नहीं की। मैं स्मृति जी को बधाई देना चाहता हूं कि उनके मंत्रालय ने नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा परमवीर चक्र अवार्डियों की "वीर गाथा" को प्रकाशित किया। यह बहुत बड़ी बात है। आने वाली पीढ़ी को हमने पराभव का इतिहास नहीं पढ़ाना है। मैंने बहुत सारे राष्ट्रों का इतिहास पढ़ा है, लेकिन पराभव का इतिहास कभी भी कहीं नहीं पढ़ाया जाता। भारत का दुर्भाग्य यह रहा कि वर्षों तक हमें पराभव का इतिहास ही पढ़ाया गया। हर देश का इतिहास गौरवशाली पन्नों से पटा होता है, लेकिन हमने अब अपने गौरवशाली इतिहास को पढ़ाने की शुरुआत की है। इसको किसी अन्य नज़रिए से नहीं देखना चाहिए।

स्कूलों में आर्टिस्टिक टेलेंट को पोषित करने और बढ़ावा देने के लिए "कला उत्सव कार्यक्रम" की शुरुआत की गई है। इतना ही नहीं, 'स्वच्छ भारत मिशन' के साथ 'स्वच्छ विद्यालय कैंपेन' की शुरुआत स्वयं स्मृति जी ने जाकर की है। स्कूलों द्वारा स्वच्छता की ऑनलाइन रिपोर्टिंग का प्रावधान भी किया गया है।

सरदार पटेल जन्म वर्षगांठ के अवसर पर सीबीएसई द्वारा हर वर्ष 31 अक्तूबर को स्कूलों में 'राष्ट्रीय एकता दिवस' मनाने का निर्णय लिया गया है। यह सामान्य बात नहीं है। हम सरदार पटेल को 'लौह-पुरुष' बोलते हैं। हमने आजादी में अपने देश के पहले गृह मंत्री के योगदान के बारे में बहुत बातें की हैं। वे एकता के सूत्र में बांधने वाले भारत के सबसे बड़े व्यक्तित्व थे। आने वाली पीढ़ी उनके व्यक्तित्व को पढ़े और समझे, इसीलिए 'राष्ट्रीय एकता दिवस' को मनाने का

निर्णय लिया गया। 'राष्ट्रीय एकता दिवस' मनाने उद्देश्य देश में एकता और अखंडता को कायम रखना है। इसमें कोई राजनीति नहीं की गई है। शिक्षा में कोई भी राजनीति नहीं करता है। न मैं उन पर आरोप लगाता हूं, जिन्होंने पहले शासन किया और न ही मैं उन पर आरोप लगाता हूं, जो आज शासन में हैं। शिक्षा की जरूरत सबको है। जैसे शरीर के लिए सांस की आवश्यकता है, भारत की आत्मा को मजबूत करने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है और उस आवश्यकता को मानव संसाधन विकास मंत्रालय मजबूती दे रहा है।

यूनेस्को द्वारा 'अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस' मनाए जाने के आलोक में सीबीएसई द्वारा 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाए जाने की शुरुआत की गई है।

मंत्रालय द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में एक समर्ग एप्रोच को अपनाया गया है। पहले यह चिन्ता व्यक्त की गई कि भारत के विश्वविद्यालयों के नाम विश्व के 200-100 विश्वविद्यालयों में भी नहीं आते हैं। हमारे मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ पार्टनरशिप को सुगम बनाने के लिए Global Initiative of Academic Networks Programme की शुरुआत की है।

हमारे मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने Commonwealth Education Ministers Conference में Malviya Commonwealth Chair for Cross Border मानव संसाधन विकास मंत्री और यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल के बीच एक समझौता किया गया, जिसके तहत महान भारतीय वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों व बौद्धिकों के कार्य को पहचान प्रदान करने का काम किया गया। अभी तक उन्हें विश्व पटल पर पहचान नहीं मिली थी। इनमें गणितज्ञ रामानुजम एवं आर्यभट्ट के नाम प्रमुखता से शामिल हैं। यह भारत के गौरव को बढ़ाने वाली बात है। ये सब काम कौन कर रहा है ? यह हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर रहा है। इसमें कोई अत्युक्ति नहीं है। इन सब कामों से भारत का नाम ऊँचा हो रहा है और हम सभी भारत के नागरिक हैं। अगर भारत नहीं होगा तो हम भारतीय कैसे होंगे? भारत रहेगा, तभी हम सब गौरव से कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं।

IMPRINT India Programme की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य प्रासंगिक सामाजिक क्षेत्रों, जैसे स्वास्थ्य की देख-रेख, ऊर्जा सुरक्षा, जल एवं नदी व्यवस्था में फोकस्ड शोध के कार्य प्रीमियर संस्थानों में किए जाने की बात कही गई है। मैं आपको एक-एक बात इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि हम सबके लिए इसकी जानकारी होना जरूरी है। इन सब बातों को समझने से हमारी जनता को लाभ होगा और हमारी आने वाली पीढ़ी को लाभ होगा।

उच्चतर आविष्कार योजना के तहत, आईआईटीज़ को उद्योगों के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि इनोवेशन के क्षेत्र में उच्च उपलब्धियां हासिल की जा सकें।

राज्य स्तरीय संस्थानों के साथ संबंध को मज़बूत करने के लिए एनसीईआरटी एवं विभिन्न राज्यों के बोडर्स के साथ सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। नरेश जी चिन्ता व्यक्त कर रहे थे, लेकिन हमारी सरकार उसी तरफ बढ़ रही है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय उसी दिशा में जा रहा है। मंत्रालय द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में सहभागिता को एप्रोच किया गया है, इसे समझना चाहिए। लड़कियों के लिए "प्रगति स्कॉलरशिप" की शुरुआत की गई है। लड़कियां अब पीछे नहीं हैं। आज लड़कियां लड़ाकू हवाई जहाज़ चला रही हैं, हम उनको पीछे कैसे कह सकते हैं? बस, उन्हें थोड़ी सी बात बतानी है कि सरकार आपके लिए यह कर रही है। उनके उत्साह को बढ़ाना है, इसीलिए 'Pragati Scholarship' है। सभी भारतीय विश्वविद्यालयों में 'Choice

[श्री प्रभात झा]

Based Credit System' की बात है। यूजीसी द्वारा शोधार्थियों और स्कॉलर्स को स्कॉलरशिप में पचपन फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। जैसा कहा गया कि स्कॉलरशिप में कमी की गई, जबकि स्कॉलरशिप में बढ़ोतरी की गई है। विश्वविद्यालय और कॉलेजों को 'स्पेशल हेरिटेज स्टेटस' प्रदान करने की बात कही गई है। 'यूजीसी स्टूडेंट्स शिकायत पोर्टल' की शुरुआत की गई है। यूजीसी द्वारा 'स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत' की शुरुआत की गई है। स्कूलों में लैबोरेटरी का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, ताकि छात्रों को अनुसंधान करने में कोई तकलीफ न हो। हम कहते हैं कि हमें हमारी संस्कृति पर गर्व है। विश्व की हर भाषा की उद्गमी, उसकी मां, यानी भाषा की मां का नाम 'संस्कृत' है। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 'संस्कृत सप्ताह' की शुरुआत की है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें कुछ बातों पर सोचना होगा। अभी बजट वाली बात आई। मंत्रालय द्वारा फंड का लगभग शत प्रतिशत उपयोग किया गया है। एनडीए सरकार आने के बाद शिक्षा विभाग द्वारा फंड के उपयोग में बढ़ोतरी हुई है। पता नहीं कहां से जानकारी मिल जाती है कि यह कम हो गई या यह काट दिया, वह काट दिया, यह समझ में नहीं आता है। विभाग फंड के शत प्रतिशत उपयोग की ओर अग्रसर है। 2013-14 में शिक्षा विभाग द्वारा फंड का उपयोग 92.9 परसेंट था। मुझे खुशी है और मैं मंत्रालय को और मंत्री जी को बधाई देता हूँ कि 2014-15 में यह बढ़ कर 97.69 परसेंट हो गया है। इसमें राजनीतिक तौर पर एक आरोप लगता है कि स्वायत्तता पर कब्जा कर रहे हैं, यह कर रहे हैं, भगवाकरण, आदि क्या-क्या नहीं बोला जाता है, लेकिन भारतीयकरण के सिवा कोई करण नहीं होता। संविधान हमारा ग्रंथ है और भारतीयकरण करने में हम माहिर हैं। हम तो चाहते हैं कि जो इस भारत का नागरिक है, हर भारतीय को गौरव हो। कुछ लोग आरोप लगा रहे थे कि संस्थानों की स्वायत्तता पर प्रहार किए जा रहे हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक निर्दश दिया है कि सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय या संस्थान पहले मंत्रालय के माध्यम से पूछें कि किस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। तो पहले वे मंत्रालय से पूछें। देश का संविधान यह कहता है कि देश की संसद में जो निर्णय लिया जाएगा, उस निर्णय के तहत देश की सरकार को काम करना है। इसलिए देश की सरकार द्वारा संचालित सभी शिक्षण संस्थान इस संसद का सम्मान करेंगे, यह अधिनियमित है। यह थोपा नहीं गया है, यह अधिनियमित है। इसलिए जब केंद्र में यूपीए की, कांग्रेस की सरकार थी, संसद द्वारा आईआईटी एक्ट का उल्लंघन क्यों किया गया था, इसका जवाब देश जानना चाहता है। हमने कोई उल्लंघन नहीं किया है, क्योंकि एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया, जिसमें भारत के टैक्स देने वाले लोगों के पैसे से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आईआईटी एक्ट का उल्लंघन करते हुए एक कैम्पस के निर्माण की बात की गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब लोग संविधान से बँधे हुए हैं। हमने कभी नहीं कहा। सबके अपने-अपने ग्रंथ होंगे, धार्मिक ग्रंथ होंगे, लेकिन हम सबका भारत के नागरिक होने के नाते एक ही ग्रंथ है, जिसके बारे में हमारे प्रधान मंत्री जी बार-बार कहते हैं, उसका नाम हैः 'भारत का संविधान'। उससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। हम यह पूछना चाहते हैं कि उस समय के नये मंत्री मूक दर्शक बनकर क्यों तमाशा देखते रहे? क्या हमें संसद की गरिमा, संविधान और कानून का भय या उसकी चिन्ता नहीं थी? दिल्ली विश्वविद्यालय में चार वर्षीय पाठ्यक्रम के बारे में भी बहुत बातें की गईं और आरोप लगाए गए। ...(**व्यवधान**)... थोड़ा-सा सुन लीजिए। दिल्ली विश्वविद्यालय का चार वर्षीय पाठयक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नहीं चलाया जा रहा था। मंत्रालय के दस्तावेजों से पता चला कि 77 हजार छात्रों को 40 से अधिक इन कार्यक्रमों में शामिल किया गया, जिसकी अनुमित स्वयं राष्ट्रपति जी ने नहीं दी

थी। क्या हम ऐसा नजारा देखना चाहते थे, जब चार साल बाद दिल्ली की सड़कों पर, देश की राजधानी में, लगभग 4 लाख ऐसे छात्र उपस्थित हैं, जिनकी डिग्री का कोई मोल नहीं हो। डिग्री बहुत मेहनत से, बहुत परिश्रम से मिलती है। मां-बाप बरतन मांजकर, गरीबी से तंग आकर भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर यह निर्णय नहीं लिया जाता, तो ये जो 4 लाख बच्चे सड़कों पर थे, उनकी डिग्रियों का कोई मोल नहीं ...(**समय की घंटी**)... सर, दो-तीन मिनट और चाहिए।

सर, शिक्षा के क्षेत्र में एक गैरकानूनी हरकत को रोका गया है और छात्रों को संरक्षण दिया गया, इसकी सराहना होनी चाहिए। राजनैतिक विद्वेष से शिक्षा के मसले पर कभी कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए, यह मेरा आग्रह है। फिर सरकार के इस फैसले का विपक्ष ने एतराज़ क्यों किया? ऐसा नहीं करना चाहिए। राजनीति हर जगह अच्छी नहीं लगती। राजनीति शिक्षा में, संस्कृति में, भारत के मसले पर, संविधान के मसले पर कभी नहीं होनी चाहिए। यह न मेरी पार्टी की ओर से होनी चाहिए और न किसी और की पार्टी की ओर से होनी चाहिए। इतिहास में दखल देने के बहुत बड़े-बड़े आरोप हम पर लगते हैं। सरकार पर आरोप लगाया गया कि आईसीएचआर के माध्यम से इतिहास में दखल देने की कोशिश की जा रही है। सवाल यह है कि आईसीएचआर में आज कौन हैं? क्या इसकी जानकारी लोगों को नहीं है? क्या इस सरकार ने उसको बदल दिया है? आईसीएचआर में पूर्वी राय उच्च पद पर हैं। उनके पित कल्याण राय, सीपीआई से राज्य सभा में मेम्बर थे। पूर्वी राय, नेता जी सुभाष चंद्र बोस और भारत-रूस स्वतंत्रता संबंध के संघर्ष में जानी-मानी इतिहासकार हैं। आप किस पर आरोप लगा रहे हैं? क्या यह पक्षपात है? पूर्वी राय का आईसीएचआर में होना किस एंगल से पक्षपात है, यह हम जानना चाहते हैं? सिर्फ इसलिए कि किसी ने नाम दे दिया? कोई न कोई तो वीसी बनेगा और उसके लिए एक ही criteria है कि विश्वविद्यालय की गरिमा, भारत की गरिमा, शिक्षकों की गरिमा और शिक्षा की गरिमा कैसे बढ़ेगी, यह इस आधार पर होता है। आईसीएचआर में आनन्द साहब सचिव हैं। उन्हें Professor of Epigraphy किसने बनाया? यूपीए सरकार ने बनाया था, हमने नहीं बनाया था। क्या उनका सम्मान कर एनडीए सरकार ने इतिहास में दखल दे दिया? उन्हें Professor of Epigraphy नियुक्त करते हुए ऐसा क्यों सोचा जा रहा है? यह समझ में नहीं आता है। ...(**व्यवधान**)...

DR. K. KESHAVA RAO (Andhra Pradesh): Sir, ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Please, sit down. He is not yielding. ...(*Interruptions*)...

श्री प्रभात झा: आप मेरे बाद बोलिएगा। ...(**व्यवधान**)... आप सच सुन लीजिए। ...(**व्यवधान**)... आपने विश्व भारती मामले पर पक्षपात का आरोप लगाया। विश्व भारती के कार्यक्रम पर व्यापक स्तर पर चिंता व्यक्त की गई है। इसके लिए इन्क्वायरी कमेटी गठित की गई, लेकिन इन्क्वायरी कमेटी के मेम्बर कौन हैं? उसके मेम्बर बी.बी. दत्त हैं। वही बी.बी. दत्त, जो North-East Congress Coordination Committee के General Secretary थे। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें राज्य सभा का सदस्य बनाया था। आज सरकार के तहत शिक्षा के क्षेत्र में वही लोग काम कर रहे हैं, जो भारत के नवनिर्माण का काम करते हैं। हम अपनी पीली आंखों से नहीं देखते कि कौन क्या था? अगर शिक्षा उसकी रग-रग में है और भारत को शिक्षित करने की सामर्थ्य उसमें हैं, तो हम उसे गले लगाते हैं और उसको आसन भी देते हैं, न कि वे लोग संस्थानों पर कब्ज़ा करते हैं। ...(**समय की घंटी**)... सर, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): आपकी पार्टी का समय खत्म हो रहा है। ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रभात झाः जयंत कुमार रे, जिन्हें कांग्रेस ने यूपीए सरकार के दौरान Maulana Azad Institute of Asian Studies का चेयरमैन बनाया था, आज एनडीए सरकार के दौरान उन्हें नेशनल प्रोफेसर बनाया गया। इसमें कहां पक्षपात है? बताइए, कौन-सा पक्षपात है? ...(**व्यवधान**)... आपने इतने आरोप लगाए हैं। ...(**व्यवधान**)... आप भगवाकरण का आरोप लगाते हैं। ...(**व्यवधान**)...

SHRI P. BHATTACHARYA (West Bengal): Sir, please hear me out for a minute. ...(*Interruptions*)...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): कृपया आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)...

DR. K. KESHAVA RAO: I condemn this statement. ...(*Interruptions*)...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): जब आपकी टर्न आएगी, तब आप बात कीजिएगा। ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रभात झाः आपने हमेशा आरोप लगाया है। ...(**व्यवधान**)... सत्य सुनने की हिम्मत रखिए। ...(**व्यवधान**)... भारतीय जनता पार्टीनीत एनडीए सरकार शिक्षा के मामले में कोई राजनीति नहीं करती है। ...(**व्यवधान**)... एनडीए, भाजपा सरकार पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के द्वारा शिक्षा के भगवाकरण का आरोप लगाया जाता है और आज भी लगाया जा रहा है। संविधान की मर्यादा में ही शिक्षा दी जाएगी, यह देश के छात्रों को सरकार की ओर से वचन है और यह वचनबद्धता मानव विकास मंत्रालय ने पूरी की है। ...(**व्यवधान**)... जैसा कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने सदन में और सदन के बाहर कई बार यह दोहराया है कि उनका धर्मग्रंथ देश का संविधान है, उनका धर्म भारतीयता है। हम सब लोग उस पर विश्वास करते हैं। ...(**व्यवधान**)... शिक्षा की नई नीति कैसी हो? इस पर मंत्रालय द्वारा 33 विषय विकसित किए जा रहे हैं। इसको आप समझिए। नाराज मत होइए। आपकी नाराजगी से हम रुकने वाले नहीं हैं। ...(**समय की घंटी**)...

"खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़,
मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है।"

आप यह समझ कर रखिए कि हम कोई कठपुतली नहीं हैं। हम जनादेश पर आए हैं, किसी की कृपा पर नहीं आए हैं और जनादेश पर आए हैं, तो जनता के हित में, देश की आने वाली पीढ़ी के हित में वे सारे काम करेंगे, जो देश का भविष्य उज्ज्वल करेगा। मैं स्मृति जी को, उनके मंत्रालय को शत-शत बधाई देता हूँ और कहता हूँ कि और अच्छे से काम कीजिए। हम भारतीयों को आप पर गर्व है, आपके मंत्रालय पर गर्व है। जय हिन्द, जय भारत।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): विप्लव जी, बैठिए। ...(**व्यवधान**)... श्री हरिवंश।

श्री हरिवंश (बिहार): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं आरंभ में निवेदन कर दूँ कि मेरा समय अभी शुरू हो रहा है और आपने जैसे सब के प्रति उदारता बरती है, पांच-सात मिनट मेरे प्रति भी बरतेंगे।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): यहां जो समय लिखा हुआ है, उसी के अनुसार मुझे बर्ताव करना होगा। आपकी पार्टी के लिए 11 मिनट दिए हुए हैं।

श्री हरिवंशः आपने सबको उदारतापूर्वक 10 मिनट दिए हैं और मैं यह अपेक्षा करूँगा कि आप मुझे भी चार-पांच मिनट देंगे।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): पार्टी का जितना टाइम है, उससे ज्यादा समय किसी को नहीं दिया जा सकता, यह यहां का अनुशासन है।

श्री हरिवंशः महोदय, मैं देश की सर्वोच्च पीठ के माध्यम से देश, केंद्र सरकार और माननीय मंत्री जी के सामने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जुड़े कुछ जमीनी तथ्य रखना चाहता हूँ। मैं अपनी बात मंत्रालय के कुछ अच्छे प्रयासों के उल्लेख से शुरू करता हूँ। स्कूलों में टॉयलेट्स बनवाना, ऑनलाइन अटेंडेंस की शुरुआत, अभिभावकों को घर बैठे अपने बच्चों की गतिविधियों की जानकारी के लिए ऐप की पहल जैसे प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय हैं। उपसभाध्यक्ष जी, हमारे गांवों में एक कहावत है, "पेड़ की जड़ में जब गहरी बीमारी हो तो फुनगी के इलाज से पेड़ नहीं बचते।" हमारी शिक्षा प्रणाली आज गम्भीर चुनौतियों से घिरी है। घोषणाएँ तो बहुत बड़ी-बड़ी हो रही हैं, लेकिन क्रियान्वयन की क्या गति है और क्या यथार्थ है, उसको मैं आपके सामने रखना चाहूँगा।

हमने इस वर्ष भी माननीय वित्त मंत्री जी का बजट भाषण सुना, जिसमें शिक्षा के लिए कुछ बड़ी घोषणाएँ थीं। मैं आपके सामने महज तीन या चार घोषणाएँ रखूँगा, जिनमें उन्होंने उल्लेख किया कि "Quality of education is the next big step forward." Universalisation of primary education, विश्व स्तर के कुछ विश्वविद्यालयों, शायद 10 विश्वविद्यालयों को विकसित करने का सपना है। कणार्टक में IIT की स्थापना, ISM, धनबाद को आईआईटी का दर्जा देना, आंध्र प्रदेश तथा जम्मू-कश्मीर में IIMs खोलना आदि घोषणाएँ थीं। 23 फरवरी, 2016 को माननीय राष्ट्रपति जी ने संसद को सम्बोधित करते हुए इस सरकार की शिक्षा के बारे में प्राथमिकता बताई। Priority of priorities for his Government, पर इन घोषणाओं को पूरा करने के लिए बजट में क्या प्रावधान है? मैं एक एक्सपर्ट का ओपिनियन क्वोट कर रहा हूँ, "However, the commitment of the Government to the Finance Commission is not reflected in its allocation pattern." बिना बजट, बिना बड़ी पूँजी, बिना निवेश के बड़ी घोषणाएँ कैसे साकार होंगी, यह मैं माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहूँगा।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय का बजट कुल जीडीपी के मुकाबले किस स्थिति में है, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। अभी हमारे माननीय सांसद प्रभात झा जी बता रहे थे कि कैसे शिक्षा पर बजट बढ़ रहा है। मैं यह फिगर पढ़ रहा हूँ, Union Government's budgetary spending on education in per cent. Union Government's expenditure on education as per cent of GDP - वर्ष 2012-13 में यह 4.7 परसेंट था, 2013-14 में 4.6 परसेंट, 2014-15 में 4.1 परसेंट, 2015-16 में 3.8 परसेंट और 2016-17 में यह 3.7 परसेंट है, यानी इस सरकार के आने के बाद शिक्षा का यह बजट लगातार घट रहा है। दूसरा, Union Government's expenditure on education as per cent of Union Budget. वर्ष 2012-13 में यह 0.66 परसेंट था, 2013-14 में 0.63 परसेंट, 2014-15 में 0.55 परसेंट, 2015-16 में 0.50 परसेंट और 2016-17 में यह 0.48 परसेंट है। उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि जब शिक्षा पर निवेश

[श्री हरिवंश]
लगातार घट रहा हो, खर्चे घट रहे हैं, तो इतनी बड़ी घोषणाएँ जो माननीय वित्त मंत्री जी ने की हैं, वे कैसे पूरी होने वाली हैं?

अब मैं क्वॉलिटी एजुकेशन की चर्चा पर लौटना चाहता हूँ। स्कूल शिक्षा मद में वर्ष 2016-17 में बजट एस्टिमेट वर्ष 2015-16 के बजट एस्टिमेट से महज 3.2 परसेंट अधिक है। स्कूलों में ट्रेंड टीचर्स का अभाव है, जिसे आपने पूर्व वक्ताओं से सुना, पर टीचर्स ट्रेंनिग में वर्ष 2016-17 का बजट एस्टिमेट 510 करोड़ है, जबकि इसके पहले के बजट में यह 558 करोड़ था, यानी आप शिक्षकों की ट्रेंनिग का पैसा घटा रहे हैं, जबकि देश सबसे अधिक उनकी स्किल की जरूरत महसूस कर रहा है और आप कहते हैं कि हम क्वॉलिटी एजुकेशन देंगे!

इसी तरह, अगर आप मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बजट में अन्य मदों पर भी ग़ौर करें तो आप पाएँगे कि सरकार की स्थिति यह है कि वह रोज बड़ी और आकर्षक घोषणाएँ करती है, लेकिन उनको पूरा करने के लिए ठोस धरातल पर कोई काम दिखाई नहीं देता। अच्छी बात है कि Skill India, Start up India, Stand up India – कुछ लोग कहते हैं कि कुछ दिनों में Sit down India भी आएगा, मैं इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता – सरकार इन सबकी जो बात कर रही है, अच्छे दिनों के लिए ये सब चीज़ें जरूरी हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें तब पूरी होंगी, जब आप बजट में शिक्षा के लिए उचित प्रावधान करेंगे। आप सपने दिखाते हैं, लेकिन बजट में प्रावधान नहीं रखते। इस तरह से आप देश को गफलत में ले जा रहे हैं, यह मेरा आप पर आरोप है। सेंसस 2011 के आंकड़े बताते हैं कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच 4.3 करोड़ बच्चे अब भी स्कूलों से बाहर हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीया मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि बड़ी घोषणाएं बड़ी पूंजी, पर्याप्त बजट या निवेश के बिना कैसे, किस हालत में और कब तक पूरी होंगी? अब मैं आपको धरातल की बातों बताना चाहता हूं। विप्लव जी ने बहुत अच्छी तरह से प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बताया, लेकिन मैं स्कूलों की बिल्डिगों, खेल के मैदान — जिनके बारे में दो वर्ष पहले तक सूचना थी कि सिर्फ 52 परसेंट स्कूलों के पास खेल के मैदान हैं — फर्नीचर, आधुनिक सुविधाएं, कम्प्यूटर वगैरह की चर्चा नहीं कर रहा हूं, अध्यापक और छात्र अनुपात की बात कर रहा हूं। जहां तक मेरी जानकारी है, अध्यापक-छात्र अनुपात का ऑल इंडिया एवरेज 45:1 है। कुछ लोग इसके 36:1 होने की बात भी कहते हैं, माननीया मंत्री जी इसकी सही फिगर बताएंगी। केरल की स्थिति इसमें सर्वश्रेष्ठ है, वह 29:1 है, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता में यह 100:1 है— सौ विद्यार्थियों के पीछे एक अध्यापक है। कैसे? आप स्कूलों में चले जाइए, कभी अध्यापक सेंसस के काम में लगे हैं, कभी चुनाव के लिए काम कर रहे हैं, कभी पोलिया वगैरह का सर्वे कर रहे हैं, कभी स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार के काम में लगे हैं। हमारे पूर्व वक्ता ने बताया, मिड-डे मील के काम में लगे हैं। मिड-डे मील अध्यापकों के लिए जी का जंजाल है। ईमानदार अध्यापक ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता, वह बुककीपिंग और इन सबसे दूर रहना चाहता है। हमने अध्यापकों को पठन-पाठन से हटा दिया है, उन्हें विवश कर दिया है। मैं माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि यह दूर करने की कोशिश कब होगी? पिछले वर्ष तक कक्षा 8 में 30 फीसदी dropouts थे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पिछले वर्ष के आंकड़ों में 60 लाख बच्चों के स्कूल से बाहर होने का उल्लेख था। वर्ष 2014 तक सर्व शिक्षा अभियान के तहत 6 लाख शिक्षकों के पद खाली थे। केंद्रीय विद्यालयों में भी साढ़े 7 हज़ार पद रिक्त थे।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की और मांग हो रही है, केंद्रीय विद्यालय लोग और चाहते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालयों को बढ़ाने की भी मांग हो रही है, क्योंकि हर भारतीय आज quality education चाहता है। हम इस देश में वह अवसर कब तक दे पाएंगे?

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, गांवों और स्लमों के स्कूलों में बुनियादी आधुनिक सुविधाओं का अभाव अलग है। एक तरफ समर्थ लोगों के बच्चे महंगे स्कूलों से पढ़कर निकलते हैं, आधुनिक स्कूलों से निकलते हैं और दूसरी ओर सुविधाविहीन स्कूलों से निकलकर जो बच्चे आते हैं, उनकी क्या स्थिति बनती है? प्राइमरी स्कूलों से कैसे बच्चे आ रहे हैं? The National Achievement Survey, PISA, ASAR वगैरह की रिपोर्ट देखें, निष्कर्ष यह है कि पांचवीं कक्षा के आधे से अधिक बच्चे कक्षा दो का text नहीं पढ़ पाते। इससे भी गंभीर बात यह है कि शिक्षा में इस विषमता से भारी खतरा social inequality का है। कल ही अखबारों में बड़ी प्रमुखता से खबर आयी है कि "IMF warns of increasing inequality in India and China. Higher growth rates are not reducing inequality." बहुत वर्षों पहले, जब मैं छात्र था, मैंने Mary Tyler की पुस्तक पढ़ी थी, 'My Years in Indian Prison'. वे विदेशी महिला थीं, जिन्होंने एक भारतीय से शादी की थी जो बाद में नक्सल आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने लिखा है कि किस तरह से गरीब तबकों में जो बच्चे रहते हैं, उनके अंदर क्या सपने जगते हैं और जब वे सपने पूरे नहीं होते, तब वे हथियार उठाते हैं, तब नक्सली बनते हैं। यह व्यवस्था उन गरीबों को गलत रास्ता चुनने पर बाध्य कर रही है। अगर आप उनको अवसर नहीं देंगे, तो वे क्या रास्ता अपनाएंगे? मैं यह कहना चाहता हूं कि शिक्षा पर बड़ा निवेश बढ़ाए बगैर स्थिति में कोई सुधार नहीं होने वाला। महोदय, सेकेंडरी स्कूल्स की क्या हालत है, वहां पर भी स्थिति बहुत खराब है। सही अर्थ में आप पाएंगे कि आए दिन छुट्टियां होती रहती हैं, कभी गर्मी की छुट्टियां, कभी बरसात की छुट्टी, कभी जाड़े की छुट्टी, कभी राजनैतिक कारणों से छुट्टी, कभी पंचायत इलेक्शन हो रहे हैं, उससे छुट्टी, संसद के चुनाव में, विधान सभा के चुनाव में छुट्टी– और पढ़ाई कितने दिनों हो रही है? भारत में सिर्फ केरल की स्थिति अलग है, शायद 200 दिनों से अधिक पढ़ाई वहां होती है। माननीया शिक्षा मंत्री इसकी सही फिगर बताएंगी, हमारी सूचना के अनुसार शायद औसतन सौ दिन भी पढ़ाई नहीं होती, जबकि जापान में यह 300 दिन है, अमेरिका में 250 दिन है। सरकार बताए कि ये हालात कैसे सुधरेंगे?

महोदय, अब मैं उच्च शिक्षा की चर्चा करना चाहूंगा। उच्च शिक्षा पर चर्चा से पहले मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि सरकार इस बात से क्षणिक या आंशिक संतोष कर सकती है कि सितम्बर, 2015 में आयी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के श्रेष्ठ 200 विश्वविद्यालयों में अब हमारे दो संस्थान आ गये हैं, 147वां स्थान पर The Indian Institute of Science, Bengaluru और 179वां स्थान पर IIT, Delhi. लेकिन चुनौती यह है कि दक्षिण कोरिया, सिंगापुर— चीन को तो छोड़ दीजिए– वहां के संस्थान आपसे आगे कैसे निकल गए? गुजरे दो वर्षों में कैसे-कैसे अनावश्यक विवाद इस सरकार ने उच्च शिक्षा में बढ़ाए हैं, मैं उसका उल्लेख करना चाहूंगा। यह मानव संसाधन मंत्रालय की संसदीय समिति की रिपोर्ट का अंश है, "The Committee is not satisfied with the reply of the Department. The Committee points out that UGC, AICTE, NAAC and NBA are regulatory bodies dealing with higher education in the country and there seems to be lack of transparency in these institutions. Higher education is suffering in this

[श्री हरिवंश]

country." उच्च शिक्षा के ...**(समय की घंटी)**... उपसभाध्यक्ष जी, मुझे चार-पांच मिनट का और समय दे दीजिए, जिससे कि मैं अपनी बात पूरी कर पाऊं ।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): आप अपने प्वाइंट्स बोल दीजिए, जिससे कि आप समय से पूरा कर सकें।

श्री हरिवंश: उच्च शिक्षा के इन संस्थानों की ज़मीनी हालत जानने की मैंने कोशिश की और मैं दो उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा। झारखंड की राजधानी रांची में मार्च, 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। आज तक यह विश्वविद्यालय अपने कैम्पस में या बिंल्डिग में नहीं है, यह पंचायत ट्रेंनिग सेंटर में चल रहा है। अब सुना है कि बिंल्डिग बन गई है। इस विश्वविद्यालय के अनेक विभागों में केवल पीएचडी करने वालों को दाखिला मिल रहा है, faculty staff नियुक्त है, परन्तु स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई शुरू नहीं हो सकी है। यह हमारा national wastage जो resources का है, यह इस रूप में चलता रहा है।

जुलाई, 2010 में झारखंड के रांची में IIM की स्थापना हुई। अपनी बिंल्डिग, कैम्पस के अभाव में यह राज्य सरकार के सूचना भवन में चल रहा है। हालांकि ज़मीन आवंटित होने की सूचना अब मिली है। जगह न होने से अपने मुख्य कोर्स में कम छात्रों को यह दाखिला देता है और infrastructure की कमी से औद्योगिक भागीदारी, प्रशासनिक प्रशिक्षण जैसे प्रोजेक्ट्स नहीं चल रहे हैं। अनेक कार्यक्रम बाहर या XLRI, Jamshedpur लगभग 150 किलोमीटर दूर करने के लिए संस्थान अभिशप्त है।

बिहार में भी दो-दो केंद्रीय विश्वविद्यालय बने हैं, उनकी क्या स्थिति है, वे कब तक पूरे होंगे, यह सूचना हमें माननीय मंत्री जी से मिलेगी। ...**(समय की घंटी)**... और दूसरा मेरा सुझाव होगा कि IIT, IIM पर जो पिछले सात-आठ वर्षों में बने हैं, वे किस स्थिति में हैं, उनके बारे में सरकार white paper जारी करे। हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि शिक्षा को ...**(व्यवधान)**...

श्री सतीश चंद्र मिश्रा (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, दो घंटे का और वक्त बढ़ा दीजिए। ...**(व्यवधान)**... घंटी बजाने की परेशानी न हो।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): परेशानी किसी को नहीं है।

श्री सतीश चंद्र मिश्रा: यह इतना गंभीर विषय है। अगर इसमें दो मिनट पहले से घंटी बजने लगेगी, तो बोलने वाले का तारतम्य टूट जाता है।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): समय पूरा हो गया है। याद दिलाने का काम करना पड़ता है। ...**(व्यवधान)**... माननीय सदस्य अच्छा बोल रहे हैं, किन्तु समय पर बोलना है।

श्री सतीश चंद्र मिश्रा: जब वे इतना बढ़िया बोल रहे हैं, माननीय मंत्री जी को कोई एतराज नहीं है, हम लोगों को भी एतराज नहीं है, जब वे बोल रहे हैं, तो उन्हें बोलने दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): यहां पर जो समय दिया गया है, उसके अनुसार ही पूरा करना है।

5.00 P.M.

श्री सतीश चंद्र मिश्राः अगर सरकार कहती है कि वे चुप हो जाएं, तो चुप हो जाएंगे, यह बात दूसरी है।

श्री हरिवंशः माननीय उपसभाध्यक्ष जी, दो-तीन मिनट का समय इसमें निकल गया है, इसलिए आप हमें पूरा समय दीजिएगा। शिक्षा के बारे में कहा गया कि इसको राजनीति से दूर रखिए, मुझे लगता है कि यह सही बात है, पर institution building का काम आप जिस रास्ते से कर रहे हैं, उससे होने वाला नहीं है। 12-15 वर्षों के दौरान ऐसी स्थिति चल पड़ी है कि हम लगातार राजनीतिक कारणों से IIT की घोषणा करें। हम लौटकर तो देखों कि institution building कैसी होती है? Kharagpur देश का पहला आईआईटी बना, बहुत तैयारी के साथ बना, बहुत सुसज्जित और सुंदर बना। उसके बाद पंडित नेहरू जी..

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया)ः आप इसको टाइम से पूरा कर लीजिए। अगर आप elaborate करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके पास समय नहीं बचेगा और आप बोल नहीं पाएंगे। मैं आपकी बात सुन रहा हूं।

श्री हरिवंशः मैं यह कह रहा हूं कि खड़गपुर के बाद और चार-चार आईआईटीज़ बने, लेकिन उनकी पूरी तैयारी की गई। अब हमारे यहां पिछले 8-10 सालों से क्या परम्परा चल पड़ी है, 2007 में Prof. C.N.R. Rao जिनको बाद में Bharat Ratna मिला, वे प्रधान मंत्री की Scientific Advisory Council के Head थे, IIT बनाने की Standing Committee के Chairman थे। एक दिन उन्होंने अखबार में देखा कि 8 नये IITs खुल रहे हैं, उन्हें कोई सूचना नहीं थी उन्होंने 2013 में कहा कि 'But you cannot create a good IIT by the stroke of a pen and newspaper announcement.' कहीं पर अपग्रेड करने की होड़ चल रही है, यह सरकार भी यही काम कर रही। आईआईटी अपग्रेड करने की प्रवृत्ति पर उन्होंने कहा, 'You cannot turn Mysore University into a Harvard by upgrading it.'

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि उसी संस्कृति को जो कुछेक वर्षों पहले शुरू हुई राजनीति कारणों से आईआईटी और आईआईएम खोलने की, यह सरकार भी उसी रास्ते और परंपरा पर चल रही है। इसके परिणाम क्या हुए हैं? वर्ष 2002-2003 में मेरी सूचना के अनुसार आईआईटी में एक अध्यापक और 12 छात्रों का अनुपात था जो आज बढ़कर एक अध्यापक और 48 छात्र का हो गया है। मानव संसाधन विकास संबंधी संसदीय समिति की रिपोर्ट 2 मई, 2016 को इंडिया टुडे में छपी है, मैं उसको क्वोट करता हूं," समिति ने उच्च शिक्षण संस्थानों में जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय, आईआईटी, आईआईएम की फैकल्टी की कमी पर चिंता ज़ाहिर की है और 16,000 में से लगभग 6,000 पद खाली हैं।"

उपसभाध्यक्ष महोदय, अन्य विश्वविद्यालयों की स्थिति क्या है, इस पर मैं रोशनी डालता, लेकिन आप उसकी इजाज़त नहीं दे रहे हैं। मैं एक-दो चीज़ों का और उल्लेख कर देना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप यह क्या कर रहे हैं, जिस ढंग से लगता है कि institutions बन नहीं पाएंगे। पिछले दो-एक वर्षों में जे.एन.यू., हैदराबाद, जादबपुर इलाहाबाद विश्वविद्यालयों में जो कुछ हो रहा है, क्या वे विश्वविद्यालय इसी के लिए बने थे? हम मुक्त माहौल में प्रतिभाओं को खिलने दों, सृजन को फलने-फूलने का मौका दें, उन्हें उनकी आज़ादी और स्वतंत्र्ता में दखल

[श्री हरिवंश]
न दें। उनके प्रमुख डॉयरेक्टर या कुलपति के रूप में श्रेष्ठ लोगों को लाएं, चयन में विचारधारा को आधार न बनाएं, तो इससे शायद स्थिति बदलेगी। मैं यह कहना चाहूंगा कि आपने मालवीय जी को 'भारत रत्न' दिया, मालवीय जी अपने विश्वविद्यालय के लिए किनको कुलपति चुना? राधाकृष्णन को, आचार्य नरेंद्र देव को, आपने मालवीय जी को 'भारत रत्न' तो दिया, लेकिन आपने उनके विश्वविद्यालय में किसको कुलपति बनाया? आपको खुद से पूछना चाहिए कि उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या शिक्षा में ऊंचाई है? यही नहीं भारतीय इतिहास परिषद का अध्यक्ष आपने किसको बनाया? नेशनल बुक ट्रस्ट में आपने किस आधार पर नियुक्ति की? ...(**समय की घंटी**)...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): आप conclude करिए। मैं दूसरे वक्ता को बुलाता हूं।

श्री हरिवंश: आपने पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में किसे बैठाया? जो एक योग्यता वाले और एक खास संगठन के लोग हैं, आप उन्हें कहीं और एडजस्ट करिए। मैं उनके काम पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। उन्हें कहीं और जगह दीजिए, जहां भारत का भविष्य बन रहा है, कम से कम उनको वहां मत बैठाइए। आशुतोष मुखर्जी या उन लोगों की कहीं चर्चा हुई, आशुतोष मुखर्जी कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जिस्टस थे और साथ में कोलकाता विश्वविद्यालय के VC भी थे। उन्होंने कैसे लोगों को वाइस चांसलर के रूप में कैसे लोगों को अध्यापक चुना— सी.वी. रमन, राधाकृष्णन को कोलकाता विश्वविद्यालय में अध्यापक के रूप में लाए — तब कोलकाता विश्वविद्यालय Oxford of East कहलाया। अमरनाथ झा इसी देश में 32 वर्ष की उम्र में VC बने। कम से कम उस परम्परा को तो लौटाइए और अच्छे लोगों को इस पद पर बैठाइए। आप कभी खुद से सवाल पूछिए कि क्या वजह है कि इस देश में सी.वी. रमन या रवींद्रनाथ टैगोर या मेघवाद साहा जैसे लोग नहीं निकल रहे हैं? हम लास्ट में कहना चाहेंगे कि आपने इस हाउस में जब बोलने का मौका दिया, गौरव की बात है इस हाउस के लिए कि यहां राधाकृष्णन रहे हैं, ज़ाकिर हुसैन रहे हैं, नुरुल हसन जैसे लोग रहे हैं और अनेक लोग रहे हैं। यहां मैथिलीशरण गुप्त रहे हैं, उपाध्यक्ष जी, आप तो साहित्य के आदमी हैं, उन्होंने भारत भारती में शिक्षा की क्या कल्पना की थी, याद करिए, इसी हाउस में रहते हुए, उसकी चर्चा है। पं. विद्यानिवास मिश्र थे। उनका भाषण जहां दिया गया भारतीय शिक्षा पर सबसे जीवंत है। आज हमारे देश से शिक्षा की वाचिक परम्परा खत्म हो रही है। विनोबा जी ने कहा था कि क्या हम स्थिति बना चुके हैं कि खूब वर्षों और शीत सहने की क्षमता जब छात्र की खत्म हो जाती है, छात्र गंवा चुका होता है, तब उसे कृषि विज्ञान का स्नातक होने की उपाधि देते हैं। इस देश में यह शिक्षा चलाई जा रही है।

मैं अंत में यह कहना चाहूंगा कि अच्छे दिनों के लिए शिक्षा ही हमारी पूंजी है। शिक्षा के क्षेत्र में एक नए विज़न के साथ संस्थाओं को आज़ादी स्वायत्तता व संसाधन दें प्रतिभाओं को फलने-फूलने का मौका दें। हजारों विपिन चंद्र, रोमिला थापरों को आगे बढ़ने का अवसर दें, जो विपरीत विचारधारा वाले हैं, उनको भी अवसर दें। इसमें किसी को एतराज़ नहीं हो सकता, लेकिन प्रतिभाओं को काम करने का एक अवसर तो दें ...(**समय की घंटी**)... तब यह देश मजबूत होगा, बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI MD. NADIMUL HAQUE (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you for allowing me to participate in this important discussion taking place in this august House.

I think, ₹ 82,700 crores has been allotted to this Ministry which is roughly around 3 per cent of the GDP. Education is categorized into three levels *i.e.*, education at the primary or elementary level, the secondary level and the higher level. Sir, I would like to point out that the Gross Enrolment Ratio at the elementary level is around 97 per cent. At the secondary level, there are two levels *i.e.*, for class IX and X it is 79 per cent and for class XI and XII it is 54 per cent. And, for higher education, the figure comes between 14 per cent and 24 per cent depending on various sources. However, it is a matter of great concern that we have a very huge dropout rate of around 40 per cent.

Sir, attendance constitutes the most important factor in children learning at all levels of education. Though the overall attendance under the SSA has shown improvement from 68.5 per cent in 2006 to 76.2 per cent in 2013 at the primary level and from 75.7 per cent in 2006 to 77.8 per cent in 2013 at the upper primary level, However, Sir, a pattern of low attendance still continues to pose a challenge for children's learning and development at the primary and upper-primary levels. One of the reasons for the students' absence from school has been attributed to children being required to help parents in agricultural activities, especially, in the rural areas. This is, particularly, required because harvesting of some crops is a labour-intensive process. The problem is further aggravated by the fact that presently, there is no adequate system, put in place, to track students' attendance during the harvesting season which, in turn, culminates into a poor curriculum planning for the year and finally, leads to students not only breaking a continuous study momentum for a particular year but also missing important lessons for the learning. Hence, it is important that, education being a Concurrent subject, the Government must, put into place, adequate mechanisms to deal with the special needs of the children.

Sir, I would like to point out on the Mid Day Meal Scheme that it was designed to improve the nutritional status of school-age children nationwide as an added incentive for parents to send their children to school. This measure is, in conformity, with Article 24 of the Conventions on the Rights of the Child to which India is a party. It was supposed to provide adequate nutritious food for children. Sir, here, I would like to point out a curious observation that this incentive is working in a different way. In that, many a children are now enrolling in both private schools as well as Government schools. They are going to study in private schools but they are going to eat their food in Government schools. So, anyway, it is good. Sir, one serious fact that is as shocking as it might sound is that between 2013 and 2016, 280 complaints have been received regarding poisoning and supply of irregular food to children which includes the tragic incidence at Navsrijit Primary School in 2014 wherein 23 children had died.

[Shri Md. Nadimul Haque]

Though, Sir, it goes without a shadow of doubt that there are exhaustive monitoring mechanisms but despite them in place, such complaints of poisonous and poor quality of food are being received under the MDM Scheme. Hence, it is important that these mechanisms are made straight and accountable on their working. Sir, a big problem is the shortage of subject teachers which is a predictor of poor exam performance. Passing of the Class 10 Board Exam is determined by the composite score from all subjects a student takes. Thus, any student attending a school without a full complement of specialist teachers will be at a distinct disadvantage in the examination. Without a specialist teacher, it is predictable that the student would not meet the potential in a particular subject and therefore, underachieve in the State Board exams. Shortfall of teachers, especially, in Science, Maths and languages is common across India. In many instances, this may be further exacerbated by the sub-optimal teacher deployment. In combination, this is likely to contribute to high levels of exam failure, under-performance, particularly, of the most disadvantaged sections of the population. Sir, spending under RMSA is heavily dominated by two types of activities, that is, civil work and staff salaries. These two activities absorb around 61.6 per cent and 24.6 per cent of the expenditure respectively, which was in 2013-14. Sir, of the remaining amount, there have been very few resources spent on teacher and staff training which covers all types of training for all types of staff, training for community leaders and SMDCs and on quality and equity interventions. The funds on innovations can be significantly increased with some creative planning. It is also noticeable that there are no resources spent on innovative activities. Sir, ideally, education should lead to employability but, in reality, we see after the formal education, a student has to join some course and after completing that course, even if he gets a job, he still has to go for some on-the-job training. Sir, I have to say that in the Central universities, there are 16,000 posts. But, out of this, 6,000 varsity posts are lying vacant. These need to be filled up immediately. Furthermore, our universities have no international benchmark whereby there can be a comparison of the system of quality. That is the same about schools also.

Sir, in the name of providing quality education, the private schools are hiking fees which has made education very expensive. Sir, another important issue on which I would like to shed light is the IIM Draft Bill that threatens the autonomous working of the IIMs. In this regard, without going into the details, I would like to state that, as reported by 'The Indian Express' on 26.4.2016, it seems there has been a tussle between the PMO and the MHRD over the draft Bill. The Ministry of Human Resource Development, sources said, is not willing to dilute the clause that empowers the President to review the work of any IIM in his capacity as the

Visitor of the premier business schools. This, the Government thinks, is needed for accountability. The PMO has suggested that the Government remove the provisions for review in the Bill. The Ministry is also learnt to have retained the provision which makes the HRD Minister the Head of IIM Coordinating Forum on the ground that IITs too are governed by similar clauses.

Sir, besides these issues, this year has witnessed a dramatic turn of events at various universities, including JNU with students' protests being dealt with insensitively. In this regard, I would not like to state much as a lot has been discussed and debated in the House over this subject-matter. But, I would like to say that in an educational institution, children must be taught how to think and not what to think.

Sir, I end with an Urdu couplet:

"इल्म से बनती है जिन्दगी, बंदगी,
इल्म न हो, तो जिन्दगी कुछ भी नहीं।"

Thank you.

श्री सतीश चंद्र मिश्राः सर, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं केवल एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जब समय पूरा हो जाए, तब आप घंटी बजाइए, दो मिनट पहले नहीं, क्योंकि मैं disturb हो जाता हूँ।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): जरूर।

श्री सतीश चंद्र मिश्राः मैं कोशिश करूँगा कि आपको घंटी बजाने का मौका न मिले।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): आपके पास ९ मिनट हैं।

श्री सतीश चंद्र मिश्राः सर, मैं यह कह रहा हूँ कि आप सातवें मिनट में घंटी मत बजा दीजिएगा।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): हम घंटी नहीं बजाएँगे, यह मेरा वादा रहा।

श्री सतीश चंद्र मिश्राः सर, मेरा समय अभी से शुरू किया जाए।

सर, आज हमारे सामने एक ऐसा विषय है, एक ऐसे मंत्रालय के कार्यकरण के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है। इस country का जो social sector है, अगर उसमें कोई सबसे महत्वपूर्ण pillar है, तो वह education है। इसमें चीजों को बहुत ही गम्भीरता से लेने की जरूरत है, न कि एक चुनावी मुद्दा बना कर, जैसा कि अभी सुनने को मिल रहा था। हम गिनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम गिन नहीं पाए थे, जब सत्ता पक्ष की तरफ से एक बात कही जा रही थी, लगभग सौ योजनाओं की लिस्ट जल्दी-जल्दी बता दी गई और कहा गया कि हम लोग यह करने वाले हैं या करेंगे। यह उसी तरीके से हो गया, जैसे कि इलेक्शन के पहले वादे किए गए थे और उसके बाद आज तक लोग ढूँढ़ रहे हैं कि वे वादे कब पूरे होंगे? इसलिए करने के बाद बताना ज्यादा अच्छा रहता है, न कि यह कहना कि हम ऐसा करेंगे, फिर कर न पाएँ और फिर उसके बाद मुश्किलें हों।

[श्री सतीश चंद्र मिश्रा]

सर, भारतवर्ष में जो population है, उसकी लगभग 41 परसेंट population 19 वर्ष से नीचे की है। 19 वर्ष से नीचे की जो population है, वह स्कूलों में जाती है। 19 वर्ष से लेकर 24-25 वर्ष तक की population कॉलेजों में जाती है, यूनिवर्सिटीज़ में जाती है। इस 19 वर्ष से नीचे की जो population है, इसमें जो situation आज है, आंकड़े काफी बता दिए गए हैं, इसलिए मैं उन्हें repeat नहीं करूँगा, लेकिन 72 परसेंट तक का registration ही आठवीं क्लास तक होता है, जो बच्चे स्कूलों में जाते हैं। इनमें से फिर 48 परसेंट दसवीं क्लास तक रह जाते हैं। फिर 33 प्रतिशत बच्चे घटकर क्लास 12 तक पहुंचते हैं। जो 2011 का Census है, उसके हिसाब से लगभग 22 मिलियन बच्चे, जो 15 से 18 वर्ष की उम्र के है, वे इसलिए पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक कंडिशन ऐसी नहीं होती। उनमें से ज्यादातर बच्चे अपने कामों में लग जाते हैं, फार्म में या कहीं और मजदूरी करने लग जाते हैं और अपने परिवार को चलाने में अपना योगदान देने में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जो बच्चे स्कूलों में जाते हैं, आज उनकी स्थिति भी अच्छी नहीं है। जब 2009 में Right to Education Act आया था, उस समय बड़ी उम्मीद बंधी थी कि इसके तहत हर बच्चे को, जिसकी आयु 6 से 14 वर्ष है, अनिवार्य रुप से पढ़ाई करने का मौका दिया जाएगा। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है? वास्तविक स्थिति उसके बिल्कुल ठीक विपरीत है। Right to Education Act को आए छः साल हो चुके हैं, लेकिन स्कूलों में enrolment बढ़ने की जगह घटता ही चला जा रहा है। जो पब्लिक स्कूल्स हैं, वहां पर उन गरीब लोगों के बच्चे जाते हैं, जो अंग्रेज़ी स्कूलों और कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने में सक्षम नहीं हैं।

2014-15 में 97,000 पब्लिक स्कूलों में ऐसी स्थिति आ गई कि उन स्कूलों में पढ़ने वालों बच्चों की क्लासेज़ में बच्चों की संख्या घटकर सिर्फ 20 रह गई। ऐसा क्यों हुआ, इस पर सोचने की जरुरत है। जब हम लोग आज इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, तो मंत्रालय को कुछ चीजें सजेस्ट करने के हिसाब से कर रहे हैं, न कि माननीय मंत्री जी को नाराज़ करने के लिए कर रहे हैं। हम बस यही चाहते हैं कि वे नाराज़ न हों। ...**(व्यवधान)**... जब वे नाराज़ होती हैं तो बहुत दिक्क्त हो जाती है, इसीलिए हम बहुत संभल कर बोल रहे हैं। इन स्कूलों में 70 प्रतिशत बच्चे गरीबों के होते हैं, जो आंकड़ा मैंने पहले भी दिया है। मीडिया और RTI की enquiries से यह पता लगा है और सरकारी स्कूलों की situation सामने आई है। सरकारी स्कूलों के पास बिल्डिग नहीं है, अगर वहां टॉयलेट बना दिया गया है, तो पानी की व्यवस्था नहीं है, बच्चों के लिए कुर्सियां नहीं हैं, blackboards नहीं हैं, पढ़ाने के लिए कॉपी, किताब और दूसरी सुविधाएं नहीं हैं। जब बच्चे उनमें नहीं जा पाते हैं और जब वे देखते हैं कि ये सुविधाएं स्कूल में उपलब्ध नहीं हैं, तो वे प्राइवेट स्कूलों में चले जाते हैं, लेकिन आज RTE Act के बाद प्राइवेट स्कूलों में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि वे भी बंद हो रहे हैं। जो आंकड़े हमारे पास हैं, उनके हिसाब से लगभग 4,355 प्राइवेट स्कूल्स बंद हो चुके हैं और 15,000 स्कूलों को नोटिस दे दिया गया है कि अपना स्कूल बंद कर लें। उन्हें नोटिस क्यों दिया गया है? RTE Act के तहत जो प्रोविज़ंस रखे गए हैं, रूल्स रखे गए हैं, माननीया मंत्री जी उनको एक बार ज़रुर गंभीरता से देखें। इस ऐक्ट की जो मंशा थी, इन प्रोविज़ंस के कारण आज उसके विपरीत होने लग गया है। इस ऐक्ट की मंशा यह थी कि बच्चों को पढ़ाई का मौका मिले, पढ़ने के लिए स्कूल मिले, लेकिन हमने इस ऐक्ट में ऐसे-ऐसे प्रोविजंस रख दिए, 50 तरह की चीज़ों रख दीं कि अगर आप इन कंडिशंस को फुलफिल नहीं करते हैं, तो आप बच्चों को एडमिट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद उन पर

आपने यह कंडिशन भी लगा दी कि अगर आपने कोई ऐक्शन इसके विपरीत ले लिया, तो आपके ऊपर 10,000 रुपये का फाइन लगा देंगे। ऐसी स्थिति में आज अगर 4,355 प्राइवेट स्कूल्स बंद हो रहे हैं और लगभग 15,000 स्कूलों को बंद करने के लिए नोटिस दे दिए गए हैं, तो फिर गरीब बच्चे कहां पर पढ़ने के लिए जाएंगे?

आपकी एक योजना यह है कि हर जगह स्कूल होना चाहिए, हर वॉर्ड में स्कूल होना चाहिए, हर गांव में स्कूल होना चाहिए, लेकिन स्कूल बना कौन रहा है? जो सरकारी स्कूल बन रहे हैं, उनके बारे में सरकार बहुत अच्छी तरह से जानती है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत जो स्कूल बनते हैं, उनकी हालत यह है कि आज से 20 साल पहले उनका एक डिज़ाइन फिक्स कर दिया गया, उसी डिज़ाइन को उनके पास भेज दिया जाता है और कहा जाता है कि इस तरीके से स्कूल बना दीजिए और उसको बनाने के लिए रुपया भी फिक्स कर दिया गया है। मंत्रालय एक बार भी महंगाई के आंकड़े को नहीं देखता है कि 10 साल या 5 साल में महंगाई कितनी बढ़ गई है। आज सीमेंट के दाम बढ़ गए हैं, लोहे के दाम बढ़ गए हैं, तो क्या इतने कम रुपयों में स्कूल बन सकता है? अगर नहीं बन सकता है, तो जब बनाने की व्यवस्था की जाएगी तो ऐसे ही स्कूल्स बनेंगे, जोकि ऐसे जर्जर स्कूल्स होंगे, जिनमें पढ़ने वाले बच्चों का फ्यूचर आगे कितना ब्राइट होगा, यह कोई भी आदमी सोच सकता है। इसको भी आपको रिव्यू करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या अब आज के हिसाब से आपने सर्वशिक्षा अभियान के तहत यह जो अमाउंट फिक्स किया है, इसमें यह उपयुक्त है या नहीं। अगर यह उपयुक्त नहीं है, तो आप उसको बढ़ाने का काम कीजिए। उसमें आपने जो स्टाफ रखा है, वह contract के हिसाब से रखा है। आपने contractual employment दे रखा है और आज बीस-बीस साल से उसमें इंजीनियरिंग का स्टाफ है या अन्य स्टाफ है। आपकी यह योजना खत्म होने वाली नहीं है। यह योजना चलती ही रहनी है, लेकिन अगर उनको आप रेगुलर स्टाफ नहीं बनायेंगे, तो वे उसी प्रकार का काम भी करते हैं। वे कोर्ट्स में जाते हैं, वहां मुकदमा लड़ते हैं। वे अपनी तनख्वाह के लिए लड़ते हैं, क्योंकि आप उनको, इंजीनियर को 9,000 रुपये ही दे रही हैं, सरकार दे रही है। वह कहती है कि यह fixed है, क्योंकि यह contractual employment है, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। इसलिए आप उनसे भी उम्मीद नहीं कर सकते कि वे आगे कुछ कर सकेंगे। इन स्कूल्स में कौन पढ़ता है? इन स्कूल्स में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। अमीरों के जो बच्चे हैं, वे तो अपना पैसा देकर जो बेस्ट स्कूल होता है, वहां पर एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन Scheduled Castes के, Scheduled Tribes के तथा अन्य सभी कास्ट्स के गरीबों के जो बच्चे हैं, वे कहां जाएँ? वे तो इन्हीं स्कूल्स में जाते हैं। जब वे इन स्कूल्स में जाते हैं, तो वहां उनको पढ़ाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं मिलती है। उनको आगे चल कर किससे कम्पीट कराया जाता है, उन बच्चों से, जो दूसरे स्कूल्स से पढ़ कर आए हैं। फिर जब वे रिजर्वेशन की बात करते हैं, तो सब खड़े हो जाते हैं कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा राइट मारा जा रहा है। आप उनके लिए स्कूलों में व्यवस्था कीजिए, उनको अपने लेवल पर लाइए। उनको आप क्लास वन में अंग्रेज़ी पढ़ाने की जगह अपना करिकुलम देखिए। आप ए, बी, सी, डी क्लास 6 से पढ़ाने का काम करते हैं और आप कहते हैं कि आप उनसे कम्पीट कीजिए। सुश्री मायावती जी जब मुख्य मंत्री थीं, तो उन्होंने पहले वर्ष में पहला काम यह किया था कि उन्होंने कहा था कि ये जो सरकारी स्कूल्स हैं, इन सरकारी स्कूल्स का करिकुलम आपको भी पूरे देश के लिए देखना चाहिए। उन्होंने उसको बदला था और कहा था कि क्लास वन से, जहां से पढ़ाई की शुरुआत

[श्री सतीश चंद्र मिश्रा]

होती है, वहां से उन बच्चों को भी अंग्रेज़ी पढ़ाई जाएगी, जो गरीबों के बच्चे हैं, जो वहां पर पढ़ रहे हैं, न कि क्लास 6 से। यह क्लास 6 वाली बात जो मैं कह रहा हूँ, यह हकीकत के रूप में मैं खुद जानता हूँ। जब मैं इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहा था, तो मैं छठे-सातवें दर्जे में एक हिन्दी मीडियम स्कूल में गया, तो वहां मुझसे ए, बी, सी, डी पढ़वाई गई। जब मैंने ए, बी, सी, डी को ज़ेड तक पढ़ दिया, तो मुझसे टीचर ने कहा कि अब आप इधर आ जाइए, मैं ज़रा काम से जा रहा हूँ, तो आप बच्चों को ए, बी, सी, डी पढ़ाने का काम कीजिए। मैं उसी दिन स्कूल छोड़ कर घर वापस आ गया और मैंने कहा कि मैं उस स्कूल में नहीं जाऊँगा, जहां पर क्लास 6 और क्लास 7 में ए, बी, सी, डी पढ़ाई जा रही है। तो यह वास्तविक स्थिति है। ऐसे में बाद में आगे चल कर उन बच्चों के लिए आप कहते हैं, अगर उनको कुछ अलग से दिया जा रहा है, कोचिंग के लिए इंतजाम किया जा रहा है, तो सबको परेशानी हो जाती है। इससे जितने और लोग हैं, उनको दिक्कत होती है, तो ऐसे लोगों के लिए आपको देखने की जरूरत है।

आपने स्कूल्स बनाने की योजना बनाई है। आप कहती हैं कि हमारे पास जितना पैसा है, वह हम खर्च कर रहे हैं। आपके पास पैसे की कमी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप 3 परसेंट खर्च कर रहे हैं, लेकिन आप तो हम लोगों से भी पैसा ले रहे हैं। आप जितना भी पैसा टैक्सपेयर्स से 1 परसेंट एजुकेशन सेस के रूप में लेते हैं, तो आप ओवरऑल बजट के अलावा एजुकेशन सेस के थ्रू सबसे ले रहे हैं। आप उस रुपये का कहां इस्तेमाल कर रहे हैं? अब मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि इनको एजुकेशन सेस में कितना रुपया मिलता है? एजुकेशन सेस के रूप में टैक्सपेयर्स जो एक्स्ट्रा 1 परसेंट देते हैं, उससे कितना रुपया आता है और उस रुपये को आप कहां लगाते हैं? आप जो प्राइवेट स्कूल्स बनाना चाहते हैं, उनके ऊपर आपने सख्ती कर दी। आपने नये-नये कानून बना दिए कि प्राइवेट स्कूल वालों को अपने स्कूल्स बन्द करने पड़ रहे हैं। मैं आपको लखनऊ का ही एक एग्जाम्पल सिर्फ देता हूँ। अलग-अलग स्टेट्स ने भी RTE Act के तहत अलग-अलग अपने रूल्स बना लिए और कंडीशंस जोड़ दीं। अभी 2013 में यूपी में एक GO जारी हुआ और जारी होने के बाद उसमें एक कंडीशन जोड़ दी गई, 40 कंडीशंस जोड़ दी गईं, कि अगर आप RTE Act के तहत ये कंडीशंस फुलफिल नहीं करते, तो 10,000 रुपए per day का फाइन होगा और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। ऐसे में स्थिति यह हुई कि 2010 और 2014 के बीच जो लगभग 407 सरकारी स्कूल्स थे, वे घटकर 289 हो गए। 110 वार्ड्स में से 31 ऐसे हैं, जहां स्कूल्स ही नहीं है, जबकि 38,000 लोगों का एक वार्ड होता है। गवर्नमेंट ऑर्डर के तहत 108 प्राइवेट स्कूल्स बन्द हो गए। 2010 और 2016 के बीच में पूरी कंट्री में गवर्नमेंट स्कूल्स में पॉपुलेशन 1.16 करोड़ गिर गई है। सर, जहां तक स्कूलों का संबंध है, अगर आपको कोई मॉडल नहीं मिल रहा है, तो उत्तर प्रदेश बहुत नजदीक है, आपको उत्तर प्रदेश अच्छा भी लगता है, आप उत्तर प्रदेश में कहीं दूर मत जाइए, आप नोएडा चले जाइए। सुश्री मायावती जी जब मुख्य मंत्री थीं, तब वहां पर सरकारी स्कूल बनाया गया और कहा गया कि इसमें गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे। आज उस स्कूल में अमीरों के बच्चों के एडमिशन के लिए सिफारिशें होती हैं कि हमें भी उस स्कूल में एडमिशन दिला दीजिए, क्योंकि उस स्कूल में इस तरह की व्यवस्था की गई है, ऐसी बिल्डिंग बनाई गई है, इस तरह की योजना बनाई गई है। अगर आगे और आपको देखना है, तो आप यूनिवर्सिटी चले जाइए। नोएडा में ही गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है। आप उसको देख लीजिए कि किस तरह की यूनिवर्सिटी बनाई है। वह इंटरनेशनल लेवल की बेस्ट यूनिवर्सिटी है। आप लखनऊ जाकर देखिए।

आज 'दिव्यांग' की बात हो रही थी, जिसको हम लोग differently-abled कहते हैं। आपने उसका नाम बदल कर 'दिव्यांग' कर दिया। उसका क्या अर्थ है? दिव्य अंग है या क्या है, उसको समझाने का काम, जो वक्ता थे, उन्होंने नहीं किया, लेकिन उन्होंने 'दिव्यांग' की बात कही थी। हम लोग differently-abled उनको मानते हैं जो किसी चीज में अक्षम होते हैं, लेकिन वे लोग और चीजों में कहीं ज्यादा सक्षम होते हैं, जो हम लोग नहीं जानते हैं।

सुश्री मायावती जी ने लखनऊ में एक यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। उन्होंने डॉ. शकुन्तला मिश्रा रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी बनाई, जिसमें कि हर तरह के विकलांग, हर तरह के differently-abled students हैं, उनके लिए रिजर्वेशन किया गया और उनको मिक्स किया गया। ...**(समय की घंटी)**... हम चाहते हैं कि आप इस aspect को कंसिडर कीजिए। आप ऐसी पॉलिसी बनाइए, जिसके तहत इन बच्चों को अलग स्कूल में न भेजा जाए, इनके लिए अलग स्कूल न बनाइए, बल्कि इनको मिक्स कीजिए। इनको मिक्स करके जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, उनके साथ पढ़ाने का काम कीजिए। जिससे जनरल कैटेगरी के बच्चे भी समझ सकें कि उनकी क्या परेशानियां हैं, ताकि वे भविष्य में कुछ योगदान दे सकें। वे दोनों मिल कर एक सोसाइटी में बढ़ें, जिससे कि आपस में respect बढ़े। उनको अपने भविष्य के लिए कुछ करने को मिले, जैसा कि डॉ. शकुन्तला मिश्रा रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी में किया जा रहा है। In the end, before concluding, I would like to make a few points so that I do not take much time. आज कहा जा रहा है कि माननीय प्रधान मंत्री जी की योजना है कि जॉब सीकर्स की जगह हम चाहते हैं कि जॉब गिवर बनिए। जॉब गिवर क्या करेगा, अगर जॉब सीकर क्वालिफाइड नहीं होगा? अगर जॉब सीकर available नहीं होगा, तो जॉब गिवर कहां से जॉब देगा? इसलिए जो जॉब सीकर है, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। उसको totally ignore मत कर दीजिए। जॉब गिवर बनाने की व्यवस्था बनाते-बनाते ऐसा न हो कि हम लोग बिजनेसमैन और बिजनेस हाउसेज़ के बीच में इतना खेलने लगें कि हम लोग खाली उन्हीं की सोचें और जो नौकरी चाहते हैं, उनके बारे में न सोचें। उनका भविष्य डार्क कर दें, इस तरह की चीज हम लोगों को नहीं करनी चाहिए।

आज हम लोगों को 150 यूनिवर्सिटीज़ के बीच में भी कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाई है, जो विश्व में अपना स्थान बना सके। इसके क्या कारण हैं? मैं इसका कारण शॉर्ट में बोल देता हूँ। Reasons are many, but a few of them are: lack of adequate funds for primary education in the Government schools; lack of teachers, particularly in rural areas; lack of infrastructure, school premises, buildings, classrooms, toilets, particularly for girl-students; roads; approachability for students of rural areas; lack of motivated faculty in colleges; paucity of funds in research and development and higher-level university education; and, too much political interference in schools and universities.

मेरा अनुरोध है कि इन स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में अपना political interference बंद कीजिए। जिस तरह से जेएनयू, हैदराबाद या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रकरण हुए हैं, उनकी चर्चा बहुत विस्तार से हो चुकी है, इसलिए उसको मैं यहां पर दोबारा से दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन यह जरूर चाहता हूँ कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, उनके अंदर confidence डेवलप होने दीजिए। उनको ऐसा न लगे कि उनको सिर्फ दबाने की योजना बन रही है। इस category के कुछ बच्चे स्कूल लेवल से यूनिवर्सिटी लेवल पर पहुंच पाते

[श्री सतीश चंद्र मिश्रा]
हैं और जो वहां पहुंच पाते हैं, उनको आप वहां पोलिटिक्स की वजह से तबाह कर दें, ऐसा मत कीजिए। यह इस देश के लिए और हम सबके लिए बहुत बुरा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।

SHRI C. P. NARAYANAN (Kerala): Thank you, Mr. Vice-Chairman, for giving me this opportunity. I won't repeat what my learned colleages have said. First of all, what I have to say is that a very great attempt is being made to change the curriculum and the content of education. I would request our learned Minister to go through our experience in Kerala. See, we cannot completely change the curriculum and syllabi, whether it is of school or university, because this is not starting with a clean slate. You can continue what others have done. Till yesterday what has been done, you can add something to that; you cannot change the entire curriculum and syllabi. A lot of reports have come in papers, including various things. These are good ideas you can say. A lot of early Indian knowledge has already become a part of our curriculum. So, if you are going to introduce something new, we should discuss about that. What early Indian knowledge that has not been so far noted by our forefathers,-- those who have gone, the earlier generations-- that we have to think of. This is number one. I don't want to go into that. I am just pointing out that.

Secondly, regarding primary education, my other colleagues have said a lot of things. We have introduced RTE. More than 6 years' experience is there. But what we find is that out of the total children who enter primary education, only 72 per cent complete their education; only 48 per cent of those who enter the secondary education complete their course. I am not saying 'passing their course'; I am saying 'completing their course', and only 33 per cent complete their Higher Secondary course. Why is this happening? This is happening because we don't have facilities, starting with trained teachers, educational material in the classroom and various other things are lacking. Even classrooms are lacking. Here, I will just add one point. It is a minor point. Somebody here said that the Mid-Day Meal is not important. That is one of the most important things in the present plight of India. Even more than 60 per cent children are coming from very backward families, whether it is socially, educationally or financially backward families. They can be retained only when they are given nutritive food, not a simple food. That investment will be a great investment for the future of our country. So, I will request the Minister to not to think of curtailing expenses for Mid-Day Meal. There, I will also add that there are people who are preparing these meals. The poor people, throughout India, are getting only ₹ 1,000/- per month, and that too only for 10 months, not all the 12 months! We hear our salary being recommended to be doubled. Double the salary of these people at least. Let us start from there.

The third thing I have to say is that there is PISA Report. Somebody has referred to the PISA Report, which says that 74 per cent of our primary class children do not know mathematics and science. You take the 8th standard children. How many of them know all the letters of alphabets? We have done a study in Kerala, and we found that — it was in the late '80s — as many as 30 to 35 per cent, depending upon various types of schools, of the VII standard children did not know all the letters of alphabet. Why is this happening? This is happening because on day one, when they enter the school, there is a great divide. There are children coming from middle class and other families who learn all the letters and all the digits, whereas there are others who have not come across any of the letters or the digits, and the teachers teach the better- off students. So, we have to make a change, a fundamental change, in this that how we should have a universal pre- school so that by the time they start studying, they are on par with others. I know for certain, from my experience, that even our Adisvasi students, if given a level-playing ground, can compete with any children coming from better-off families. So, what we have to ensure is that we provide funds. I would request the Minister to provide funds so that these people can be given food. In Kerala, we have created, what you call, learning houses. Many of these children live in a single room house. They have no facility to study. So, in the ward, the Panchayat arranges a room where such children go and study in the evening, and there will be somebody to supervise them. Some elders will be there to supervise their studies. And, that has helped to improve the quality of the learning process.

The Government has expressed a great desire that 50 million, that means, 5 crore youngsters have to be trained to become good workers or good graduates. Now, with this rate of retention in the primary, secondary and higher secondary education – as I mentioned earlier that only 72 per cent, 48 per cent and 33 per cent in respective categories complete their courses – it is not easy to reach this goal in a small amount of time. Now, for school education, we are setting apart only about ₹ 42,000 and odd crores. Earlier, it was ₹ 45,000 crores but now it has decreased. Unless we treble this amount, that means to increase it to three times, we will not be able to achieve such broad aims.

Now coming to higher education, I would say – many others have also referred to it – what we have to ensure is that in the universities and other centres of higher education, there is a congenial atmosphere for learning and teaching. Now, by sending police and by filing sedition charges against students or teachers, you cannot create a congenial atmosphere or some such things. ...(*Time-bell rings*)... Sir, there are two more points. So, we have to see that in colleges and universities, we promote discussion between teachers and students on their subjects, and if there are

[Shri C. P. Narayanan]
some problems, that may be settled by the authorities by not using police or other suppressive measures but by discussion and persuasion.

Finally, there are two more things. The previous Government and this Government is trying to increase the GERs for higher secondary education. For that, we now have 700 universities and 38,000 colleges. But many of the experts in education have said that more than half of these universities and colleges are not worth it. So, you have to see why they say that these universities and colleges are not worth it. It is because they do not have competent teachers, they do not have well furnished libraries, laboratories and other things. You have to ensure that. Now, recently, I have read about MOOCs, *i.e.*, Massive Open Online Courses. By running such things, we will not be able to create or train competent people who can handle our things. These things are good and these are certain things which have been tried out in the US and other countries and they have been thrown out after some experience. So, we have to remember that.

Finally, I read about HEFA, *i.e.*, Higher Education Financing Agency. I read somewhere that the Government has got the intention to register a company under the Companies Act which will collect every year ₹ 20, 000 crores for distribution in Higher Education. Now, there are...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Please conclude.

SHRI C. P. NARAYANAN: I am concluding, Sir. Now, the question is whether we should run it as a private company for profit-making or we should run it for universities, UGC, RUSA and other bodies; the question is whether we should have such companies or we should use Government's other methods. The Government should seriously think on these lines. Thank you.

श्री दिलीप कुमार तिर्की (ओडिशा)ः उपसभाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रकवि दिनकर जी जो कभी इस हाउस के मेम्बर थे, उन्होंने एक बार कहा था,

"दो में से तुम्हें क्या चाहिए? कलम या तलवार कि तलवार,
मन में ऊँचे भाव या तन में शक्ति अजय अपार।"

शिक्षा हमारे मन में वही उच्च भाव भरने का माध्यम है। आज कोई शक नहीं है कि बच्चों का भविष्य शिक्षा ही तय करती है, बिना शिक्षा के बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए आज एचआरडी मिनिस्ट्री को लिया गया है और यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं माननीय मंत्री महोदया से अनुरोध करना चाहूंगा कि हमें उनकी और मदद स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए चाहिए। सबसे पहले तो मैं सर्व शिक्षा अभियान की बात करना चाहूंगा। शुरुआत में इसका केंद्र और राज्य का शेयर 75:25 परसेंट था, लेकिन अब इसको घटाकर 65:35 परसेंट कर दिया गया है। मेरी मांग माननीया मंत्री जी से यह है कि इसको फिर से बढ़ाकर 75:25 परसेंट पर ही

रखना चाहिए, क्योंकि हमारे ओडिशा में ट्रायबल एरियाज़ हैं, बहुत बैकवर्ड एरियाज़ हैं। जहां पर आपदाओं से प्रभावित राज्य हैं, उनके लिए 35 परसेंट देना डिफिकल्ट होता है। मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि खर्च का एक पैटर्न एरिया स्पेसिफिक होना चाहिए, जैसे हमारे ओडिशा में KBK डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वे बैकवर्ड एरियाज़ हैं, बहुत ट्रायबल एरियाज़ हैं, वहां पर जो केंद्र और राज्य का शेयर होना चाहिए, वह 90:10 परसेंट होना चाहिए, तभी वहां के ट्रायबल बच्चे आगे बढ़ पाएंगे।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं ट्रायबल एजुकेशन के बारे में भी कहना चाहूंगा और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज़ादी के 68 साल बाद भी हमारा ट्रायबल समुदाय अन्य समुदायों से काफी पिछड़ा हुआ है, इसीलिए हमारे ओडिशा की काफी सालों से एक ट्रायबल यूनिवर्सिटी की मांग रही है। वहां के ट्रायबल बच्चे, जो फीस नहीं दे पाते हैं, जो आश्रम से निकल कर आगे पढ़ नहीं पाते हैं, उनके लिए हमारी मांग है कि वहां पर एक ट्रायबल यूनिवर्सिटी स्थापित की जाए, ताकि वहां के बच्चे अपना आटर्स, कल्चर, स्पोटर्स, सभी एक्टिविटीज़ वहां से सीखें।

इसके साथ ही हमारी यह भी मांग थी कि जितने भी हमारे ट्रायबल एरियाज़ हैं, बहुत से ट्रायबल डिस्ट्रिक्ट् में नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय का अभाव है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस तरफ भी ध्यान दिया जाए।

देश के जो मॉइनारिटीज़ शिक्षण संस्थान हैं, उनमें एक असुरक्षा का वातावरण आजकल बनाया जा रहा है। भारत के संविधान के आर्टिकल 30 में स्पष्ट रूप से यह लिखा है कि सभी मॉइनारिटीज़ को अपनी पसन्द का एजुकेशन सिस्टम बनाने और उसे चलाने का अधिकार होना चाहिए। संविधान में यह भी लिखा है कि मॉइनारिटी संस्थान होने की वजह से सरकारी सहायता में उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि कई सारे स्टेट्स में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो मॉइनारिटी के संस्थान हैं, उनको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की जाती है। इसके बारे में भी मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी जवाब दें।

मैं स्पोटर्स बैकग्राउंड से हूं इसलिए मैं स्पोटर्स के बारे में जरूर कहना चाहूंगा। हमारा देश लगभग 125 करोड़ की आबादी का देश है, लेकिन दुख की बात यह है कि हमारा देश स्पोटर्स कल्चर्ड देश नहीं है। इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि हमारे स्कूल, college, University में भी स्पोटर्स कल्चर नहीं है। मैं इस बारे में दो चीज़ें कहना चाहूंगा। पहली बात तो, National Sports Fitness Programme की है, जो कि स्कूल, college, University में चलाया जाए। दूसरी बात, मैं यह कहना चाहूंगा कि marks for sports होने चाहिए। मैं पहली बात National Sports Fitness Programme के बारे में कहना चाहूंगा। हमने देखा है कि हमारे 15 से, 20, 25 तक की उम्र के बच्चों का जो रिकॉर्ड सामने आया है, जो आंकड़े सामने आए हैं, उनके अनुसार लाखों की संख्या से ऊपर बच्चे डाइबिटीज़ से प्रभावित हैं, कई सारे बच्चे स्मोंकिग कर रहे हैं, उनको बी.पी. हो रहा है, कई सारे स्टूडेंट्स हार्ट अटैक से भी प्रभावित हो रहे हैं। इसका एक ही कारण है कि हम स्कूल में physical fitness training बिल्कुल नहीं देते हैं। मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एनसीसी को साथ लेते हुए National School Fitness Programme चलाया जाए, स्पोटर्स को कम्पल्सरी किया जाए। मेरे ख्याल से तभी यूथ और हमारे जो छात्र हैं, वे काफी दिनों तक मजबूत रहेंगे और देश के लिए अच्छा काम करेंगे। हम कहते हैं, हमारा नारा है, "बढ़े भारत, पढ़े भारत", लेकिन यह नारा तभी सक्सेसफुल होगा, जब हमारा यूथ मजबूत और स्ट्रांग होगा।

[श्री दिलीप कुमार तिर्की]

मैं दूसरी बात मार्क्स फॉर स्पोटर्स की कहना चाहूंगा। हमारी कई सालों से डिमांड रही है कि स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जितने बच्चे नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहे हैं, स्पोटर्स में मेहनत कर रहे हैं, उनको स्पोटर्स के ज़रिए, उनकी परफॉमैंस के जरिए मार्क्स मिलने चाहिए। इसको उनके एजुकेशन मार्क्स में जोड़ा जाना चाहिए। उनको इन मार्क्स के साथ पास करना चाहिए। हमारे जो बहुत सारे स्कूल, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़, स्पोटर्स होस्टल्स हैं, स्पोटर्स ऐकेडमीज़ हैं, इनमें हमारे वे बच्चे, जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको भी स्पोटर्स के ज़रिए, नेशनल और इंटरनेशनल परफॉमैंस के बेस पर, स्पोटर्स मिनिस्टर से बात करके मार्क्स देने चाहिए। इसके ज़रिए भी उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): आपका बहुत अच्छा सुझाव है। खेल और स्कूल का आपस में जुड़ाव होना चाहिए, आपका यह अच्छा सुझाव है।

श्री दिलीप कुमार तिर्की: हमारे बहुत सारे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में ग्राउंड्स हैं, लेकिन वे मेंटेंन्ड नहीं हैं। ग्राउंड्स सूखे पड़े हुए हैं। इस बात का हमेशा डर रहता है कि अगर वहां पर बच्चे जाएंगे तो गिर जाएंगे, उनको गिरने से इंजरी होगी। इसका डर रहता है, इसलिए, एटलीस्ट स्कूल, कॉलेज और युनिवर्सिटी में ग्रीन ग्राउंड होने चाहिए। इससे उनके मन में गिरने का कभी भी डर पैदा नहीं होगा। जब उनके मन में गिरने का डर पैदा नहीं होगा, तभी जाकर उनको स्पोटर्स में इंट्रस्ट आएगा और उनकी परफॉमैंस अप होगी। सभी स्कूलों में ट्रेंनिग का प्रबंध होना चाहिए।

महोदय, मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि हमारे इंडिया से सालाना बहुत टेलेंटेड, स्टूडेंट्स, लगभग दस लाख से ज्यादा, बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। क्या हमारे यहां कोई कमी है? हम बहुत सारा पैसा बाहर खर्च कर रहे हैं। इसके लिए मैं एचआरडी डिपार्टमेंट से अनुरोध करूंगा कि ऐसे इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएं कि जो बच्चे बाहर जा रहे हैं, वे हमारे यहां पर पढ़ें। मेरे ख्याल से अच्छी क्वालिटी के हज़ारों प्रोफेसर्स भी बाहर जा रहे हैं। उनकी हेल्प किस तरह से मिल पाए, हमें उस पर भी सोचना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): आपके सुझावों के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। Now, Shrimati Vandana Chavan; not present. Dr. K. Keshava Rao.

DR. K. KESHAVA RAO: Mr. Vice-Chairman, what kind of a Ministry is this? The Minister is not here We are discussing a very important thing more particularly when the Government has launched a beautiful scheme of inviting and interacting with people on NEP and you are also trying to interact with the House, the Members, who are very much interested in education.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MUKHTAR ABBAS NAQVI): Keshava Raoji, the Minister of State is here. ...(*Interruptions*)...

DR. K. KESHAVA RAO: No, I understand. ...(*Interruptions*)...

SHRI MUKHTAR ABBAS NAQVI: She is coming. ...(*Interruptions*)... You please continue. ...(*Interruptions*)...

DR. K. KESHAVA RAO: I also saw the officers withdrawing from the gallery. ...(*Interruptions*)... It can't be done. ...(*Interruptions*)... Then don't have debate at all. It is not necessary. You have already put it on web. You are inviting all people's suggestions. They are there. You look into them and let the Expert Committee look into all those things. It is not necessary that Mr. Harivansh should spend all the time and read out all the statistics. I do not know what it is. I am really sorry. This should not have happened with a subject like 'education'. Particularly, I am one of those who believe it from heart. Education is the first love for me and there is no other subject in the country which is as important as education. If we are trying to build a nation, it can be done only through education. If we have to believe Kothari, the nation is built in the classroom, but that classroom is not the soulless desk, nor the blackboard, nor the chalk-piece; it is the teacher, the human element, which is in the classroom. We are trying to talk about that human element today. What has been done? Mr. Prabhat Jha has read out all the programme of Government. I will tell you if the Minister can take it seriously, please understand the subtlety of it. This is exactly what ails our education system. उन्होंने ऐसा बताया कि स्कूल में यह शिक्षा तीसरी जमात में शुरू होती है, जिनको addition नहीं आता, जिनको जमा नहीं आता, लेकिन हम उनको multiplication सिखाते हैं। हम आपके प्रोग्राम को समझ ही नहीं पा रहे हैं, आपने 42 प्रोग्राम्स बता दिए। हर वक्त perceptive attention create करने की जरूरत है। हमारा attention span कितना होता है, आप जो बोल रहे हैं, हम उसको कितना समझ सकते हैं, वह स्कूल होता है। जब एक teacher teach करता है, वहां 40 बच्चे बठते हैं, तो जो बच्चा पीछे बैठता है, वह गांव से आता है। वह आपके जितना knowledgeable नहीं है, उसका perception बहुत कम है। सामने आपका बेटा बैठता है, क्योंकि उसके पास चार किताबें हैं। अगर हमारे वी.पी. सिंह साहब का बेटा पढ़ता है, तो वह समझ सकता है। But there is this kind of a wave length that he has to pass through. So, perceptive attention is exactly what is required. What Mr. Prabhat Jha said and what I am saying is exactly the same. I am trying to tell you that we must understand this. Irony यह है कि हर आदमी education के बारे में बात कर लेता है। मैं जानता हूँ कि जो काम किया जा रहा है, यह पहली बार नहीं है। शायद इस देश ने, भारतवर्ष ने, आप जिस शिक्षा की बात करते हैं, इसने वह बहुत-बहुत पहले दी। वर्ल्ड में Egypt के बाद recorded history में हमारी ही education है। जब प्रभात झा जी बोल रहे थे, तो उन्होंने विवेकानंद का नाम लिया था या अरबिदो का नाम लिया था। आप education को समझने की कोशिश कीजिए, हम जो बात कर रहे हैं। क्या literacy की बात कर रहे हैं, जो words को सिखाना चाह रहे हैं? क्या आप क्लास में बैठ कर learning सिखाना चाह रहे हैं, ताकि मैं एक sentence पढ़ लूँ या आप उसके साथ knowledge सिखाना चाह रहे हैं, ताकि मैं उसे कुछ understand कर लूँ या assimilate कर लूँ या आप मुझे enlighten करना चाह रहे हैं, ताकि मैं कहीं useful हो जाऊँ? ये बहुत सी चीजें हैं, जिन पर आप New Education Policy में

[Dr. K. Keshava Rao]
विचार कर सकते हैं। मिनिस्टर आ गई हैं। She will understand now. We can't match her in rhetoric, but, at least, let us match her in sharing our thoughts. First of all, let education be defined in our hearts. First, I congratulate the Minister for the exercise that she has undertaken, as far as the New Education Policy is concerned. But let not the Members from ruling side think that it is the first Education Policy. I have been associated with it earlier in 1986. It is not the first time that we have gone and called thousands of people through Web. And, I have my own complaint to register through you, Sir, to the Minister that I have sent 36 pages' suggestions. There is not even an acknowledgement. At least, they should have acknowledged it. It is not that unnecessary like we have written so many books and they are all thrown into the waste-paper boxes.

Now, let us understand what exactly we are trying to do. I would not repeat because a lot of statistics has been given, particularly Harivanshji has given statistics. But I will tell you what he has not said. The KGBV wanted 5,000 more teachers. That is not given. They wanted 1,300 Kasturba Vidalayas. They have not been given. These are all statistics that he has missed, although he said that he did not want to give big list. Then, there are a few things. What happened in the Mid-Day Meal Scheme? Sixty-nine per cent of the kitchens are not ready. There are all this statistics. I will not repeat them. I will go at the macro level and share the vision because you were talking of the vision of education. What is the vision of education that you are trying to have? There are four things — access to school where you teach; what you teach; how you teach; and, how you evaluate attachments. These are the four simple things. You are saying that there are a lot of schools. I will make it short. Somebody talked about neighbourhood schools, and you also came out with satellite schools. The concept of satellite schools remains on paper I go round the villages. I have an NGO, as far as education is concerned. That is why I am talking from the first-hand experience. Now, they are there. Few of the pieces, we pick up. Somebody, like a postman, particularly, or some teacher, these people come. They come voluntarily as there is no rule that they should come and stay. That is one part. Do you think that a teacher who is going there is attending there schools regularly? Please look into that. Now, if that school is there, the question is that schools run for how many days ...(*Time-bell rings*)... Somebody said, somewhere it runs for 300 days, and, somewhere it runs for 100 days. Let me tell you because Britishers wanted to go and have a summer holiday or picnic or hike somewhere, we have also created summer vacations, not knowing the fact, not understanding the fact that in the rainy season, in the monsoon season, all the boys, not all the boys but most of them, are busy in the fields. Even the school condition is not good enough to keep the boys there. That we have not changed.

Now, let us come to content, which is very important because all of them have talked about quality. I want to draw the attention of the Minister only to this issue. Harvansh*ji* did not ask for a change in syllabus. I know that syllabus cannot just be changed. The way you were reacting to him through your face expressions, I thought, you were objecting to him. But he wanted to talk about the content. Let me tell you. What is that we teach? Sir, through you, I would like to say that we teach trigonometry in schools. I am asking the people here, at the matriculation level, are we not forced to study trigonometry from eighth, in ninth and tenth?

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Keshava Rao ji, please conclude.

DR. K. KESHAVA RAO: All right, Sir. I sit down then. ...(*Interruptions*)... Sir, I am talking about the quality. There is no such thing in the CBSE format. Sir, now I talk about content. What are we teaching? We are teaching trigonometry. Do any are of us use it? Only an Engineer uses it and we are forced to learn it in eighth, ninth and tenth.

This is what exactly happens with regard to the content. सर, आप एक geography की किताब ले लीजिए, नारायणन साहब ने अभी बताया कि 65 per cent dropout होते हैं। खैर, अब करेक्ट फिगर क्या है, 47 से 48 परसेंट तो होगा ही। I will not challenge that or go into that. यहां हम अपने देश की बात कर रहे हैं। जब हम देश की बात करते हैं, तो मेरे देश का बच्चा गांव में बसता है। वह dropout होता है, तो तकलीफ होती है। आप geography की फर्स्ट क्लास का फर्स्ट पेज देखिए, इसमें लिखा है दुनिया गोल है। अब दुनिया गोल है, तब क्या और चपटी है, तब क्या? मैं यहां क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूं, मैं approach of teaching की बात बता रहा हूं कि How do we teach? Second, chapter and peaks of altitude and latitude, which you have not seen, I have not seen. There are another twelve pages on that. Then, it says, the world has six continents. अब 6 continents हैं, तो क्या और 12 continents हैं, तो क्या? I am speaking of pupil who are upto 6 class चलिए, अब थर्ड चैप्टर पर चलिए, इसमें फर्स्ट है — यूरोप। इसमें लिखा है, यूरोप में एस्कीमोज़ क्या ड्रेस पहनते हैं, लिवरपूल में कितना Cold होता है, कैसा होता है। फिर आप नेक्स्ट चैप्टर पर चले जाइए, इसमें अमरीका की बात है कि वहां व्हीट कैसा होता है। नेक्स्ट चैप्टर पर जाइए, उसमें ऑस्ट्रेलिया के बारे में लिखा है कि वहां sheep breeding कैसी होती है। फिर अफ्रीका पर आ जाइए, वहां आप अफ्रीका की Mining को समझ लीजिए, फिर साउथ अमरीका पर आइए, लास्ट में एशिया पर आइए, तब तक स्कूल बदं हो जाता है। None of us are there. एशिया के चैप्टर में इंडिया लास्ट में आता है। Please see the geography book. The last pages contain India, and, by that time, there is no school at all. I have been a teacher myself. I have taught in university, then went to the primary schools. So, I understand it. आप मेरे गांव ही चलिए कि मैं अपने गांव में क्या कर सकता हूं, क्या पहनूं, वहां क्या प्रोड्यूज़ करूं। लेकिन वह उसमें नहीं है। उसमें है कि एस्किमोज़ क्या कपड़े पहनते हैं, लिवरपूल में कितनी ठंड होती है, यह सब उसके कंटेंट में है।

[Dr. K. Keshava Rao]

6.00 P.M.

अब आप हिस्ट्री पढ़िए। हिस्ट्री में हम लोग बच्चों को बताते थे, डेट ऑफ बर्थ को रेड पेन से अंडरलाइन करेंगे, तो एक मार्क ज्यादा आएगा। हिस्ट्री में है कि अशोक की बेटी की शादी का दिन यह है। What is this? What kind of approach towards education is this? Coming to pedagogy, pedagogical skills have to change. You have integrated teachers' training programme. I myself have been to one of the workshops. The report is that hardly thirty to thirty-five per cent of the teachers go there, and, that too, the Government school teachers. As per your own HRD Reports, the boys in the Government schools are declining; their enrolment is declining. They are going to private schools. Why? आप इसको भी देखिए। आप स्कूल में एक्सेस के लिए स्कूल की पोज़िशन देखिए। लेकिन हमने टॉयलेट बना दिए, ये बना दिया, वो बना दिया। They are important but that is not everything. He has very rightly said, आप ये पहले बताते कि ...(**व्यवधान**)

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Keshava Rao ji, please conclude.

DR. K. KESHAVA RAO: Just one minute, Sir. It is regarding content. Now, I come to, how do we teach and how does it matter. हमने सीखने के बाद क्या सीखा है? I am not talking colleges; I am only going to primary school teacher. As they said, इसको आप स्ट्रेंथन कीजिए। उसने बताया कि साहब, मेरी पूरी एजुकेशन एग्जामिनेशन के एक घंटा पहले स्टार्ट होती है, उसके पहले मुझे कुछ याद नहीं रहता है। एक घंटा पहले यानी अगर 10 बजे से एग्जाम है, तो 9.59 बजे तक मैं किताब देखता हूं और एकदम 10 बजते ही मैं किताब बन्द कर देता हूं। किताब बन्द करके लिखने के बाद मैं जब पास होकर आता हूं, तो फिर किताब पढ़के ही सिखाना होता है। टीचिंग करूं तो किताब देख कर बताना, लॉयर बनूं, तो किताब देख के ही आर्ग्यू करना आदि। What exactly is the *jadu* in that? Rote learning system को हमने चेंज करने की कोशिश की, हर वक्त कोशिश की। We have written something like four chapters on that. But it has not been aliened. Even in your present-day questionnaire, I have seen, we have written on that many things. एक चीज़ है। आप इसमें ज़रा ध्यान दीजिए। आप पहले कंटेंट पर जाइए। What we make — I am telling you as Vivekananda said; I will only repeat from your colleague — Education is a man-making machine. आप यह मत समझिए कि आपकी एजुकेशन से बहुत कुछ हो रहा है। आप मेरे गांव में जाइए। वहां गांव में एक घर बना हुआ है।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): केशव राव जी, मैं दूसरे वक्ता को बुला रहा हूं।

डा. के. केशव राव: ठीक है, सर, मैं लास्ट में जो बोल रहा हूं, उसकी इम्पॉर्टेंस देखिए, जो आप नहीं करते हैं। मैं एजुकेशन में हूं, इसलिए ध्यान दे रहा हूं अगर आप फेल हो गए, तो यह हाउस एड्जर्न होता है, उतना ही होता है और कुछ नहीं होता है। अगर आप यहां से निकल कर चले गए, तो हाउस एड्जर्न होता है, अगर कोई लॉयर फेल होता है, तो केस हार जाता है, डॉक्टर फेल होता है, तो एक मरीज मर जाता है, लेकिन अगर टीचर फेल हो गया,

तो जेनरेशन खत्म हो जाती है, आप इसे याद रखिए। इसीलिए हम देश में कोई Politician Day नहीं मनाते। हम कोई Chairman's Day नहीं मनाते। ...**(व्यवधान)**... हम सिर्फ दो ही days मनाते हैं: Teachers' Day और Army Day ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): इसीलिए तो जब उपसभाध्यक्ष बैठा हो, तो सदन को चलना चाहिए ...**(व्यवधान)**... धन्यवाद ...**(व्यवधान)**...

डा. के. केशव राव: सर, लास्ट में मुझे एक ही बात बोलनी है। सर, क्वेश्चंस बहुत हैं। आपने फाइनेंस की बात की। फाइनेंस के लिए इनोवेटिव तारीख सोचिए। इंडिया की फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी मैंने establish की। बाद में हमने distance education की बात की। वैसा ही इनोवेटिव कीजिए, जो financially buden न हो, they can think it over. I have established India's first Open University in Hyderabad, Andhra Pradesh. Whatever it is, I can only say...

[MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair*]

Sir, through you, I would draw the attention of the Minister for very simple reasons ...(*Time-bell rings*)... Because you have taken up a ...(*Time-bell rings*)... Only one minute, Sir. You have taken up a very comprehensive scheme. ...(*Time-bell rings*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What do I do, tell me.

DR. K. KESHAVA RAO: Lastly, I would request the Government, the Ministry, please call a few people who are interested in participation... ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your time is over.

DR. K. KESHAVA RAO: ...who are interested in education. Hold a meeting with them. ..(*Interruptions*)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your time was five minutes. ..(*Interruptions*)..

DR. K. KESHAVA RAO: Thank you very much, Sir. I thought since you have come, I will get five minutes more.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Vice-Chairman was very liberal to you. If there is a vote now, I know you will all select him, not me, because for five minutes, he spoke thirteen minutes.

Now, Shri P. L. Punia - absent. Then, Dr. Pradeep Kumar Balmuchu.

डा. प्रदीप कुमार बालमुचू (झारखंड): उपसभापति महोदय, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। यह मानव संसाधन विभाग एक ऐसा विभाग है, इतना महत्वपूर्ण विभाग है, जो देश का भविष्य बनाता है। इस विभाग पर बड़ी जिम्मेदारी है कि आने वाले समय में हमारा देश कैसा होगा, हमारा भारत कैसा होगा। वह इसको यह तय करता है। हमारे बीजेपी के साथी उज्जवल भारत की कल्पना करते हैं, 'उन्नत भारत' का नारा देते हैं। 'उज्ज्वल भारत, उन्नत भारत' के लिए बहुत जरूरी है कि हम एजुकेशन की नींव ऐसी रखें कि आने वाले भविष्य

[डा. प्रदीप कुमार बालमुचू]

में जो बच्चे हम तैयार करें, जो देश हम तैयार करें, वह इतनी ताकत के साथ काम करे कि दुनिया में हम आगे बढ़ते नजर आएं। अभी हमारी साथी झा जी कह रहे थे कि बीजेपी की सरकार बहुत कुछ कर रही है, जिसको बताना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूं कि अगर आप अच्छा काम करेंगे, सरकार एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छा काम करेगी, तो वह अपने आप लोगों को पता चलेगा। इसका बहुत प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। आप जो बात कह रहे थे, अगर आप committed हैं कि हम भारत के बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी तालीम देंगे, तो स्वाभाविक है कि इसके लिए पैसे भी ज्यादा लगेंगे। अगर आप बजट को देखें, तो आपको पता चलेगा कि इसकी क्या स्थिति है। जब यूपीए की सरकार थी, तब 2012-13 में हम लोगों ने एजुकेशन के बजट को 18 परसेंट बढ़ाया था और 2013-14 में इसको फिर 8 परसेंट बढ़ाया था। जब 2015-16 में आपकी सरकार आई, तब आपने एजुकेशन के बजट को 24.68 परसेंट कम कर दिया। और तो और, इस साल यानी 2016-17 के बजट में एजुकेशन के बजट को देखें, तो पाएंगे कि शिक्षा के बजट को आपने 82,771 करोड़ रूपए से घटाकर 69,074 करोड़ रूपए कर दिया है। इस बार भी आपने इसको घटा दिया है और आप कहते हैं कि हम इस देश को उज्ज्वल बनाना चाहते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं रहेंगे, तो आप यह काम कैसे करेंगे?

सर्व शिक्षा अभियान की बात करें, तो आपने इसके बजट को भी 24.14 परसेंट कम कर दिया है। मिड-डे मिल की बात करें, तो उसमें भी आपने बजट को 16.40 परसेंट कम कर दिया है। अगर पूरे बजट को देखें, तो जो मुझे जानकारी है कि विभाग की तरफ से 50 हजार करोड़ रूपए की डिमांड की थी, मगर वित्त मंत्रालय से आपको मात्र 22 हजार करोड़ रूपए मिले। अब समझ लीजिए कि आपका कितना commitment है। आपकी कथनी और करनी में कितना फर्क है? आपको लगता है कि 55 हजार करोड़ रूपए खर्च होंगे, मगर सरकार तो आपको सिर्फ 22 हजार करोड़ रूपए देती है। यह तो आपकी तस्वीर है। आप कहते कुछ हैं और होता कुछ है। अगर ईमानदारी होती, तो आप 55 हजार करोड़ रूपए खर्च करते।

हम शुरू से कह रहे हैं कि जो प्राइमरी क्लास में एडमिशन होते हैं, अभी कुछ दिनों पहले स्कूलों में एडमिशन चल रहा था। पहली क्लास में एडमिशन के लिए हम लोगों के पास बहुत लोग पैरवी के लिए आते हैं। अच्छे स्कूलों की बहुत कमी है, लेकिन पैरेंट्स आपने बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए बहुत परेशान रहते हैं। जहां तक सरकारी स्कूल की बात है, सरकारी स्कूल की हालत तो ऐसी है कि जो टीचर वहां पर पढ़ाते हैं, वे भी अपने बच्चों को वहां नहीं पढ़ाते हैं। उनका अपना बच्चा पब्लिक स्कूल में पढ़ने के लिए जाएगा, इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाएगा, कॉन्वेंट में जाएगा। वह अपने बच्चों को अपने स्कूल में नहीं पढ़ाएगा।

अभी आपने एडमिशन में लॉटरी सिस्टम शुरू कर दिया है। आपने कहा कि चूंकि पैरवी होती है, इसलिए हम इसमें लॉटरी करेंगे, यह अच्छी बात है। मगर लॉटरी में गरीब आदमी का नाम आता ही नहीं है। आईएएस और आईपीएस आदि ऑफिसर्स के बच्चों का नंबर आ जाता है, लेकिन गरीब के बच्चों का नंबर नहीं आता है। पता नहीं कैसे लॉटरी होती है? उनका बच्चा तो कभी दूसरे स्कूल में नहीं पढ़ता है, सब अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। अगर लॉटरी का सिस्टम है ...(**व्यवधान**)... इसलिए मैंने कहा कि इसमें कहीं तो गड़बड़ी है। आखिर उनके बच्चों को हर समय अच्छे स्कूल में कैसे एडमिशन मिल जाता है? ...(**व्यवधान**)... आज करीब-करीब 35 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं

जा रहे हैं, जो 6 से 14 वर्ष के हैं। अगर ये बच्चे भी स्कूल जाना शुरू कर दें, तब फिर समझ लीजिए कि देश का क्या होगा और बच्चों का क्या होगा? इतने स्कूल हैं नहीं। आज जब हम अच्छे स्कूल की बात करते हैं, तो इस बात की बहुत आवश्यकता है कि हम सरकारी स्कूलों को कैसे मजबूत करें, इसकी क्वालिटी को कैसे बढ़ाएं। अभी बहुत सारे लोगों ने अपनी बातों में इस संबंध में कहा है कि कैसे इसकी क्वालिटी को इंप्रूव किया जाए ताकि गांव के बच्चे, जो देहात में रहते हैं, उनको वहीं पर अच्छी तालीम मिल सके। इसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। अगर सरकार अलग-अलग नॉर्म्स बनाती है, जैसे प्राइमरी स्कूल के लिए यह कहा जाता है कि वह बच्चों को एक किलोमीटर के अंदर उपलब्ध होना चाहिए, सेकंडरी स्कूल, जिसमें कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे पढ़ते हैं, वह दो किलोमीटर के रेडियस में उपलब्ध होना चाहिए। आप देखिए कि क्या स्थिति है। कक्षा एक से पांच तक का जो प्राइमरी स्कूल है, क्या हम बच्चों को एक किलोमीटर के अंदर उपलब्ध कराकर शिक्षा दे पा रहे हैं? अगर हम मिडिल स्कूल की बात करें, तो क्या वह दो किलोमीटर के रेडियस में हम दे पा रहे हैं? कतई नहीं। और तो और, शिक्षकों की भी कमी है और टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टिट्यूशंस की भी कमी है। सरकारी आंकड़े यह बताते हैं कि टीचर्स और बच्चों का रेश्यो 37 परसेंट से कम है और आप सिर्फ 63 परसेंट फुलफिल करते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपके पास टीचर्स की सख्त कमी है। आप "सर्व शिक्षा अभियान" को ही देख लें, तो सिर्फ उसमें ही करीब 6 लाख टीचर्स की जगहें खाली हैं। अगर हम सेंट्रल स्कूल्स की बात करें, तो उनमें 44,529 पोस्ट्स में से करीब 7,698 पोस्ट्स खाली पड़ी हैं। ये ऑकड़े बताते हैं कि अगर आपके पास शिक्षक नहीं होंगे तो आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? आप प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल को देख लें, जिसमें कक्षा पहली से लेकर कक्षा पांचवीं तक है, उसमें दो टीचर्स हैं। अगर हाई स्कूल को देखें तो वहां टीचर्स की 10 पोस्ट्स सैक्शंड हैं, लेकिन वहां तीन टीचर्स ही हैं, जिनमें से एक आॅफिस का काम करता है और दो टीचर्स पढ़ाते हैं। अगर टीचर्स की यही स्थिति रहेगी, उनकी इतनी ही कमी रहेगी तो हम वह कल्पना नहीं कर सकते, जैसा आप सोच रहे हैं कि उज्ज्वल भारत होगा, ऐसा उन्नत भारत होगा। इसकी कल्पना हम लोगों को नहीं करनी चाहिए।

यहां पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, जिसमें अगर एक बार टीचर अप्वाइंट हो गया, तो रिफ्रेशर कोर्स कराया जाए। नई-नई तकनीकें आ रही हैं, मगर टीचर कई सालों से जो पढ़ता आ रहा है, वही पढ़ा रहा है। उसके लिए कहीं पर भी रिफ्रेशर कोर्स की व्यवस्था नहीं है। आपको इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो नई-नई टेक्नीक्स आती है, नई-नई चीज़े आती हैं, उनसे आपका टीचर कैसे ईक्विप्ड हो? उसके लिए यह जरूरी है कि आप बीच-बीच में टीचर्स को रिफ्रेशर कोर्स कराएं।

वर्ष 2009 में एक महत्वपूर्ण चीज़, Right to Education आई। उसमें बच्चों को यह अधिकार दिया गया कि उनको शिक्षा मिलेगी, फ्री शिक्षा मिलेगी। यह अच्छी बात है, मगर उसमें यह कहा गया है कि कक्षा एक से आठ तक के जो बच्चे हैं, उनको आप फेल नहीं कर सकते, उनको पास करना ही पड़ेगा। मैं पूरी तरह से इसके विरोध में नहीं हूं, मगर यह बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि जो बच्चा फेल नहीं करेगा यह ठीक है कि वह पढ़ता चला जाएगा, पढ़ता चला जाएगा, लेकिन वह बच्चा अपना भविष्य क्या बनाएगा? जब वह दसवीं कक्षा में जाता है तो अटक जाता है, नौवीं में जाता है तो अटक जाता है, क्योंकि वह यह समझता है कि हम तो पास होंगे ही। गार्जियन भी उसकी पैरवी करता है कि पास हो रहा है अगर आप उसे फेल कर देते हैं, तो वे कम्प्लेंट करने लगते हैं। मैं इस बात के विरोध में नहीं हूं कि उनको पास करना चाहिए, लेकिन

[डा. प्रदीप कुमार बालमुचू]

ऐसा नीचे की कक्षा तक ही होना चाहिए। आठवीं कक्षा से पहले और छठी कक्षा के बाद उसकी नींव थोड़ी मजबूत होनी चाहिए। अगर हम उसकी नींव मजबूत नहीं करेंगे तो उसका आने वाला भविष्य भी खराब हो जाएगा। यह ऐक्ट वर्ष 2009 में आया है। अगर हम 12-15 साल बाद देखेंगे तो पाएंगे कि जिस क्वॉलिटी के बच्चे् आपको मिलने चाहिए थे, वैसे बच्चे आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए मेरा अपना यह सुझाव है कि इस चीज को आप केवल कक्षा पांच तक ही कम्पलसरी कीजिए कि तब तक बच्चा पास होता रहेगा, मगर कक्षा पांच के बाद उसको फेल करने का अधिकार भी आपको रखना होगा, तभी बच्चा पढ़ पाएगा। डंडा नहीं दिखाने से बच्चा पढ़ने वाला नहीं है। हम लोग भी पढ़ते थे, लेकिन बिना डंडे के पढ़ाई नहीं होती थी। इसलिए थोड़ा प्यार और थोड़ा डंडा, दोनों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों की यह जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को अच्छी तालीम दें।

आज जब बच्चे पढ़ते हैं और वे मैट्रिक पास कर लेते हैं, तो हम देखते हैं कि उसके बाद अगर कोई बच्चा चाहता है कि हम कॉमर्स पढ़ें, कोई चाहता है कि हम साइंस पढ़ें, तो उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। इसका कारण यह है कि कहीं उसका परसेंटेज कम होता है या कहीं कम सीटें हैं। यह स्थिति है, जिसके कारण बच्चा अपने मन मुताबिक पढ़ाई नहीं कर पाता है, क्योंकि वैसे कॉलेज उसको नहीं मिल पाते। आज इस बात की आवश्यकता है और हम लोगों को यह प्रयास करना चाहिए कि वे जो चाहते हैं, वैसी ही शिक्षा वे ग्रहण करें। इसमें दिक्कतें आएंगी, मगर प्रयास शुरू करना पड़ेगा। आज नहीं तो 10 साल बाद इसमें हम सफलता हासिल करेंगे, मगर इसको आज से ही शुरू करना पड़ेगा। मैट्रिक के बाद अगर कोई चाहता है कि वह science पढ़े तो उसे science मिले। ठीक है, उसके जो मार्क्स आते हैं, उन्हें देखना चाहिए, लेकिन मार्क्स अच्छे होने के बावजूद भी अगर उसे science पढ़ने से वंचित होना पड़े तो यह दुखद बात है। अगर मेरी परसेंटेज ठीक है तो जो मैं पढ़ना चाहता हूं, वह मुझे पढ़ने के लिए मिलना चाहिए। ...(**व्यवधान**)... महोदय, अगर हम केंद्रीय विद्यालय की बात करें तो सब भारतीय चाहते हैं कि बच्चों को सस्ती एवं अच्छी एजुकेशन मिले, quality education मिले, जो केंद्रीय विद्यालयों के माध्यम से मिलती है। जब यूपीए की सरकार थी तो हम लोगों का टारगेट था कि हम 500 केंद्रीय विद्यालय खोलें। मगर जब यह सरकार बदल गयी तो वह 500 का टारगेट खत्म हो गया। अब सरकार इसके लिए कोई पैसा ही नहीं दे रही है। महोदय, हम लोगों ने पिछली बार एक सवाल किया था, हमारा 28 अप्रैल का Starred Question No. 48 था, जिसका मंत्री जी ने जवाब दिया था ...(**समय की घंटी**)... सर, अभी तो मैंने शुरू किया है।

श्री उपसभापतिः आप दो मिनट का समय और ले लीजिए।

डा. प्रदीप कुमार बालमुचूः मंत्री जी ने जवाब दिया कि जो ट्राइबल क्षेत्र हैं और जो उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र हैं, उन जगहों पर हम लोग सेंट्रल स्कूल्स खोलेंगे, उसमें आपने annexure दिया है, जिसमें 34 का जिक्र है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारा झारखंड उग्रवाद प्रभावित भी है और पूरा ट्राइबल क्षेत्र भी है, लेकिन उस लिस्ट में, उन 34 में उसका कहीं नाम ही नहीं है। इसलिए जो क्वॉलिटी एजुकेशन, सस्ती एजुकेशन केंद्रीय विद्यालय देते हैं, आज इस बात की बहुत अधिक आवश्यकता है कि हम कैसे अधिक से अधिक केंद्रीय विद्यालय खोलें। इसी तरह से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय ऐसा विद्यालय है, जहां पर वंचित समुदाय के जो बच्चे हैं, चाहे एससी हैं,

एसटी हैं, ओबीसी हैं, माइनॉरिटी के बच्चे हैं, इस प्रकार के 75 परसेंट बच्चों को उसमें एडमिशन दिया जाता है, वहां पर उनके लिए रिजर्वेशन होता है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, please conclude.

डा. प्रदीप कुमार बालमुचूः लेकिन अगर आप देखें तो सरकार उस क्षेत्र में भी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को भी नहीं खोल रही है, जबकि उनका अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। जैसा मैंने कहा कि वहां पर एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के बच्चों को एडमिशन मिलता है, इसलिए उन्हें ज्यादा खोलने की जरूरत है, लेकिन इसमें भी सरकार बड़ी धीमी है और सरकार उन्हें खोलना नहीं चाहती।

महोदय, जहां तक मॉडल स्कूल्स की बात है, 600 मॉडल स्कूल्स backward districts में खोलने का कार्यक्रम था, उनके संबंध में बीजेपी सरकार ने कह दिया है, केंद्र सरकार ने कह दिया है कि हम स्टेट गवर्नमेंट को मॉडल स्कूल्स खोलने के लिए कोई भी पैसा नहीं देंगे। तो आप समझ सकते हैं, मैंने एक तस्वीर दिखाने का प्रयास किया है कि यह सरकार कहती है कि हम ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन अगर आप तस्वीर देखेंगे तो सरकार ऐसा कुछ करती हुई नजर नहीं आ रही है।

महोदय, आज अच्छे-अच्छे इंस्टीट्यूशंस की बात हुई। मैं बहुत थोड़े शब्दों में अपनी बात को रखूंगा। बहुत सारे लोगों ने हायर एजुकेशन के बारे में कहा। जब यूपीए की सरकार थी, हमारा फ्लैगशिप था — आईआईटी खोलना। जब सरकार आयी, तो इसको इन्होंने आगे बढ़ाया और इन्होंने announcement की कि हम पांच आईआईटीज़ खोलेंगे और उसके लिए इन्होंने और उसके लिए इन्होंने 1,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया। ...(**समय की घंटी**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, time is over. Please.

डा. प्रदीप कुमार बालमुचूः जबकि DPR बनी, तो 2,200 करोड़ आ गए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have taken 14 minutes. You have two more speakers.

डा. प्रदीप कुमार बालमुचूः आप समझ लीजिए कि 1,000 करोड़ ...(**व्यवधान**)... आपकी मंशा है कि आप पांच आईआईटीज़ खोलेंगे और आप उनके लिए प्रोवाइड करते हैं, 1,000 करोड़ रूपए। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः आपकी पार्टी के दो लोग और बोलने वाले हैं।

डा. प्रदीप कुमार बालमुचूः और आप ही DPR बनाते हैं तो 2,200 करोड़ रूपए हो जाते हैं। इस प्रकार आपको 2,200 करोड़ रूपए देने चाहिए, तब वे खुल पाएंगे।

श्री उपसभापतिः आपकी पार्टी से दो लोग और बोलने वाले हैं, इसलिए अब आप बैठ जाइए।

डा. प्रदीप कुमार बालमुचूः सर, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं।

एक माननीय सदस्यः सर, पीछे वालों का साल में एक ही बार नम्बर आता है।

डा. प्रदीप कुमार बालमुचूः सर, मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा, जिसे मैं बहुत महत्वपूर्ण समझता हूं। मैं मंत्री महोदया से अनुरोध करूंगा कि वे इस ओर थोड़ा ध्यान दें। अभी जो स्कूलिंग चल रही है और जो सिस्टम है, उसमें इस बात की बहुत आवश्यकता — आपकी सरकार भी स्किल की बहुत बात करती है। हम आपको सुझाव देना चाहते हैं कि हाई स्कूल में ही बच्चों को स्किल का कोई सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. That is enough. Now, Shri Shwait Malik.

डा. प्रदीप कुमार बालमुचूः ताकि आने वाले हर बच्चे को थोड़ा-बहुत स्किल मिले। ...**(व्यवधान)**... हमें लगता है कि इसको स्कूल में ही, कोर्स में डालना चाहिए, तब जाकर आप जो स्किल डेवलपमेंट चाहते हैं, वह स्किल डेवलपमेंट का काम पूरा हो पाएगा।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Shwait Malik.

श्री मुख्तार अब्बास नक़वीः सर, इनकी यह maiden speech है, अगर आप इसको maiden मानते हैं, तो... ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः अगर maiden speech मानते हैं तो मैक्सिमम 15 मिनट, नहीं तो 10 मिनट। आपकी पार्टी का बाकी टाइम 15 मिनट है और दो सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री मुख्तार अब्बास नक़वीः सर, आज इनकी स्पीच को maiden speech रिकॉर्ड मत करिए, फिर किसी दिन कर लेंगे।

श्री उपसभापतिः इनकी स्पीच को maiden speech नहीं मानना। Okay. Then he can take eight minutes.

श्री सतीश चंद्र मिश्राः सर, जब माननीय सदस्य पहली बार बोल रहे हैं, तो वही maiden speech कहलाएगी। बाद में तो सेकंड टाइम हो जाएगा।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is new terminology. हम उस टाइम इसका explanation दे देंगे। ...**(व्यवधान)**... Then, I will say what it is. Now he will get his party's time. His party has got 15 minutes. There are two speakers. He can get 7½ minutes. So, take eight minutes. The rest we will decide later. When he claims maiden speech, then, I will give my ruling.

श्री श्वेत मलिक (पंजाब): सम्मानीय उपसभापति महोदय, मैं आपका और अपनी पार्टी नेतृत्व का बहुत आभारी हूं, कि मुझे संविधान के इस मंदिर में आज पहली बार संबोधित करने का सुअवसर मिला। एक संक्षिप्त परिचय दूंगा कि मैं गुरू नगरी श्री अमृतसर साहिब से आया हूं, जो लव-कुश की धरती है, जो श्री हरमंदिर साहिब की धरती है, जो श्री दुर्गयाना की धरती है, जो जालियांवाला बाग की धरती है और जो इंटरनेशनल बॉर्डर वाघा बॉर्डर की धरती है, जो अटारी बॉर्डर की धरती है। मैं सबसे पहले बधाई दूंगा अपने प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में काम कर रही बहन स्मृति ज़ूबिन इरानी जी को, जो हमारी मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति का आरम्भ किया है और क्रांति का हमेशा विरोध हुआ है। क्रांति कभी रूकी नहीं है और क्रांति करने वाले कभी विचलित नहीं हुए हैं। सम्माननीय

सदस्य ठीक कह रहे थे, मैं तो नया सदस्य हूं, मैं तो ज्यादा समय सुनता हूं। इस शिक्षा के वृक्ष को सालों से दीमक भी लगी है और गम्भीर बीमारी भी है, पर अब समय आ गया है कि इस गंभीर बीमारी का निवारण होगा। हमारी मानव संसाधन विकास मंत्री ने हर विद्यार्थी के लिए जो स्कीम्स निकाली हैं, चाहे प्राइमरी हो, चाहे मिडिल हो, चाहे मैट्रिक के बाद हो, चाहे कॉलेज की शिक्षा हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, सब विद्यार्थियों का ध्यान रखा है। मैं पृष्ठभूमि में जाऊंगा कि यह देश वहीं है, जिसे विश्व गुरू कहा जाता था। यहां के आचार्य, यहां के गुरूकुल, हमारी महान संस्कृति, यहां शिक्षा प्राप्त करने के लिए दुनिया से लोग आते थे। समय-समय पर हमारी संस्कृति पर आक्रमण हुआ और जो लोग आए उन्होंने अपनी सुविधानुसार शिक्षा प्रणाली से छेड़छाड़ की और शिक्षा प्रणाली को खराब करके रख दिया। मैं यह भी नहीं भूलूंगा कि पिछले लम्बे समय से मैकाले के सिस्टम से चलते हुए, जो आज रिजल्ट आया है, मैं सभी सम्माननीय सदस्यों को सुन रहा था, हमारी सरकार अभी दो वर्ष पहले आई है। लम्बे समय के कारण आज भी जो शिक्षा में कमी है, महिलाओं की शिक्षा में कमी है, मैं अपनी सरकार को बधाई दूंगा कि एक महिला बहन स्मृति ज़ूबिन इरानी जी को इस विभाग का मंत्री बनाया है और वह दिन दूर नहीं जब सारी कमियां दूर हो जाएंगी। शिक्षा के साथ लम्बे समय तक जो खिलवाड़ हुआ, उसका कारण यह था कि जो शिक्षा थी, वह एक वर्ग को लाभ पहुंचाती रही। जो दलित समुदाय था, जो पिछड़े हुए लोग थे, उनके लिए यह possible ही नहीं था कि वे शिक्षा प्राप्त कर सकें। यही कारण था कि जो फिगर्स आ रही थीं, मैंने माननीय सतीश मिश्रा जी की फिगर्स देखीं, नरेश अग्रवाल जी की भी फिगर्स देखीं, ये फिगर्स यह दर्शाती हैं कि जो कार्य बहुत पहले हो जाना चाहिए था, उसके लिए आज भी हम संघर्ष कर रहे हैं। किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए शिक्षा ही मूल सिद्धांत है। जिन राष्ट्रों ने, जिन शक्तिशाली राष्ट्रों ने आज तरक्की की है, अगर हम उनका आकलन करें, तो शिक्षा के कारण ही उन्होंने तरक्की की है। आज यह सरकार बहुत जागरूक है, उस स्तर पर शिक्षा लाने के लिए, ताकि भारत एक बार फिर से विश्व गुरू बने, फिर एक बार विश्व शक्ति बने। इसके बारे में सरकार ने अलग-अलग स्कीम्स बनाई हैं, जिसमें हर वर्ग का ध्यान रखा है। उसमें स्कॉलरशिप्स भी दी हैं, उसमें टेक्नीकल शिक्षा पर भी ध्यान दिया है, मेडिकल शिक्षा पर भी ध्यान दिया है, आईआईटीज़ पर ध्यान दिया है, आईआईएम पर भी ध्यान दिया है। हर वर्ग जो शिक्षा देने के लिए माध्यम है, उसका उत्थान करने के लिए प्रावधान किया है। सर, मैं तो केवल यह कहूंगा कि —

"भारत का भविष्य बनाने को हम
ज्ञान का दीप जलाएंगे,
ऊंच नीच का भेद मिटाकर
ज्ञान का दीप जलाएंगे।"

हम जानते हैं कि यह युवा देश है। यहां figures भी दी गईं, इसलिए युवा शक्ति के लिए, युवा शक्ति के स्वर्णिम भविष्य के लिए शिक्षा अनिवार्य है, इसलिए मैं तो स्कीम्स का ही वर्णन करूंगा। जो स्कीम्स नर्सरी क्लास से शुरू होती है, 'पढ़े भारत, बढ़े भारत'।

"The programme was launched on 26th August, 2014 to improve learning outcomes. The programme focusses on language development to create interest in reading and writing and comprehension in teaching Mathematics in a way that develops liking and understanding.

[श्री श्वेत मलिक]

इसके बाद जो स्कीम सारांश है—

"The CBSE Board has launched an online facility titled *Saransh*", हमारी गवर्नमेंट में, on 2nd November, 2014, for affiliated and CBSE schools. It helps the schools to look at their performance at an aggregate level, at the level of each student, स्कूल्स की प्रमाणिकता को सिद्ध करने के लिए।

यहां Mid-day Meal बंद करने की भी बात हुई, तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। गरीब बच्चों के लिए Mid-day Meal एक अच्छी स्कीम है। केवल यह चाहिए कि जो chosen representatives हैं, वे अपने दायित्वों की पूर्ति करें, चाहे वह पंच हैं, चाहे वह कांउसिलर है, चाहे वह नगरपालिका का सदस्य है, चाहे वह विधायक है या संसद सदस्य है, there should be a vigilant supervision of this scheme. इस स्कीम में सुधार के लिए vigilant supervision बन्द करना है, I don't find कि इसका कोई अंत है। इस स्कीम को सुधारने के लिए हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए और सब अपने-अपने क्षेत्र में राजनीति से उठकर प्रयास करें, तो मैं समझता हूं कि इसका proper distribution भी होगा और जो लाभार्थी आखिरी end पर बैठा है, उसको इस स्कीम का लाभ मिलेगा। उसके बाद एक स्कीम 'Pandit Madan Mohan Malviya National Mission for Teachers' Training है। एक teacher well-trained होगा, तभी वह शिक्षा दे पाएगा। "An umbrella scheme to create synergy among the various ongoing initiatives on teachers and teachings was launched. The scheme will address all issues related to teachers' teaching, teachers' professional development and curriculum design. इसके बाद, IMPRINT India कि जो रिसर्च से संबंधित स्कीम है, to identify the needs of the country in terms of its research and technology requirements and to enable proper planning for empowered research infrastructure. जो UGC and AICTE है, उसके ऊपर भी सम्माननीय मंत्री महोदय ने बहुत अच्छा कार्य आरम्भ किया है। "Lots of private institutions have come up in the higher education sector with a growing trend of commercialization और जो standard maintain नहीं कर रहे हैं, उनके लिए भी there is a scheme just to have a vigilant supervision of these institutes. AICTE "recognizing the need for restructuring and strengthening the All India Council of Technical Education to address imperatives and challenges in the technical education sector for full realization".

श्री उपसभापतिः आपके आठ मिनट हो गए हैं।

श्री श्वेत मलिकः इसके लिए भी सुधार हुआ है। आज सबसे बड़ी क्रांति आने वाली है, क्योंकि जब क्रांति आती है, मुझे याद है किसी ने स्वप्न तो देखा है। मैं 1987 में टोक्यों मे काम करता था और मैं एक इंजीनियर हूं। मैं वहां 'शिन्कान्सेन' में ट्रैवल किया, जो एक बुलेट ट्रेन थी। कितने वर्ष हो गए हैं, लेकिन किसी ने भी स्वप्न नहीं देखा है, यदि किसी ने स्वप्न देखा है, तो माननीय मोदी जी ने देखा है और वह पूरा भी होगा। ...**(समय की घंटी)**...

श्री उपसभापतिः मलिक जी, आठ मिनट हो गए।

SHRI SHWAIT MALIK: Sir, I am a new Member. I should be given the privilege of extra time. मुझे दो मिनट का समय और दीजिए। "Five IITs in Andhra Pradesh, Jammu and Kashmir, Chhattisgarh, Goa and Kerala, six Indian Institutes of Management, including Himachal Pradesh, Andhra Pradesh, Punjab and Maharashtra" पंजाब के IIM के लिए, मैं अमृतसर निवासी होने के नाते, माननीय जेटली जी और मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं कि अमृतसर में Indian Institute of Management का तौहफा मिला है, मैं अमृतसर वासियों का धन्यवाद करता हूं। जो अलग-अलग Scholarship schemes हैं, जो बच्चे शिक्षा को afford नहीं कर पाते हैं, उनके लिए Scholarships दी गई हैं। Scholarship में चयन के बाद, उनका जो प्रॉपर चयनर हो, वह merit के हिसाब से हो। किसी बच्चे का रास्ता केवल पैसे के कारण बंद न हो। वह चाहे Technical Education हो, चाहे स्कूल एजुकेशन जो, चाहे कॉलेज एजुकेशन हो, वे स्कीम्स, जो मंत्रालय की तरफ से दी गई हैं, मैं उनके लिए भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि आने वाले समय में उनका भविष्य संवरेगा।

बच्चियों की Technical Education के मामले में यह देखा गया है कि उनकी संख्या कम रहती है। मैं खुद इंजीनियर था, हमारी क्लास में केवल दो लड़कियां हमारी क्लासमेट्स थीं। उसके लिए विशेष ट्रेनिंग की व्यवस्था हो, ताकि अधिक से अधिक बच्चियां Technical Education में आगे आएं, इसका भी प्रयास किया गया है।

सबसे बड़ा अभियान, जो "स्वच्छ अभियान" है, यदि हमारी मंत्री जी खुद स्वच्छ अभियान में लगेंगी तो अच्छा होगा। मैं बहिन स्मृति ज़ूबिन इरानी जी से निवेदन करूंगा कि आजकल Private Schools जो शोषण कर रहे हैं, वे under table practices से कैपिटेशन फीस लेकर पेरेन्ट्स का और विद्यार्थियों का शोषण कर रहे हैं, उन Private Schools के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए।

दूसरा, जो जेएनयू प्रकरण हुआ है, यह हमारे लिए शार्मिंदगी का प्रकरण है। देश की इसी यूनिवर्सिटी में कुछ स्टूडेंट्स ने ये नारे लगाए कि, "अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं।" ...(**व्यवधान**)... उन्होंने राष्ट्र विरोधी नारे लगाए, इसलिए मैं बहिन जी से निवेदन करूंगा कि इस पर कड़े कदम उठाए जाएं। अभिव्यक्ति की आजादी हर एक के लिए होनी चाहिए, परन्तु जो राष्ट्र हित है, उसके साथ किसी तरह का compromise न हो। ऐसे तत्वों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए, ताकि इसकी पुनरावृत्ति न हो। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मेरी जो पहली स्पीच है, उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करके दुबारा opportunity लूंगा, धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is interesting. Now, Dr. K.P. Ramalingam. You know the time for 'Other' category. The total time is 27 minutes with six speakers. That means, five minutes per speaker. That is the time.

DR. K. P. RAMALINGAM (Tamil Nadu): Sir, you are more sympathetic than Shri Jatiya.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I know, if Mr. Jatiya stands for election against me, you will vote for him because he is very liberal! I know that.

DR. K. P. RAMALINGAM: Thank you, Sir. We, in the august House, are from different political parties with different political ideas but we are all under our first Chairman, the great patriot, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. Under his shadow, we are sitting in the House. So, we must rise in one voice to strengthen our nation's education system. For that, whoever may be in the Government, whatever their period, we must encourage them to do something. Finding fault alone is not our business. We have to encourage and get the work done from them. Sir, in that aspect there is a Tamil saying . Thiruvalluvar has said :

* *"Learning is excellence of wealth that none can destroy.*
To man nought else affords reality of joy."

That means –

"Learning is the true imperishable riches;
all other things are not riches."

This means that for everybody education alone is wealth and nothing other than that. Diamond is not wealth. Gold is not wealth. Money is not wealth. Education alone is the wealth. Sir, If we calculate our GDP in terms of education, development-wise, we will be first in the Universe. But we are not calculating the GPD according to education. Thirty or forty years before, if you had gone to any foreign country, that too, Europe or a Western country, they would have said, "Are you coming from India? There will be snakes everywhere! You are living with snakes" Like that, those people would mock at us. But, nowadays, it is not like that. We are teaching them. In so many Army headquarters, like in America's Pentagon city, at the American Army Headquarters, our people, our Indian students, the South Indian youngsters, are there doing programmes for them. Like that, we have improved in it. But I still have some concerns about al those things. As far as our country is concerned, elementary education is a very necessary one. At the same time, the higher education system of a country also plays a significant role in the creation of skilled human resources.

The Right to Education was launched in 2009 with a lot of noble expectations. But the RTE scheme is losing its steam due to half-hearted implementation. According to the Act, all private schools need to reserve 25 per cent of their total seats for students belonging to the economically weaker sections. Is it happening now? No. Nowhere is it happening. However, the Department failed to reimburse the amount despite repeated representations from the schools. Still a majority of private schools do not follow the system of providing admission to children below-the-poverty line. Nowadays private schools are not for improving the education or for service. The

*English translation of Tamil poem.

private schools are functioning as business centres. They are into a sort of business activity. They are not really serving the people. On the pretext of imparting education, the primary schools and higher secondary level schools and even colleges are being run as business centres. There is a need to set up a monitoring mechanism to ensure that 25 per cent admission is given to children below the poverty line by all private schools and the list of such students has to be forwarded to the Government. The hon. Minister must take care of this thing and the Department must directly monitor these things.

The overall literacy rate in the country may have gone up to 74.4 per cent but the drop in the illiteracy rate has not matched the increase in population. Between 2001 and 2011, the population above the age of seven grew by 18.65 crores but the decrease in the number of illiterates is just 3.11 crores. This has to be noted. The fact that illiteracy is not being tackled is evident from the enrolment rates in primary and upper primary schools. Over twelve years, the number of children, who enrolled in primary schools, increased by just 1.86 crores whereas the population increased by more than 18 crores. The country also seems to be having a problem with retaining people in schools and colleges. An average of 326 out of 1,000 students in rural areas are dropping out whereas the number is 383 per 1,000 in urban areas. It shows that the drop-outs in the urban areas is more than that in the rural areas. This is what the records say. Everybody says that rural students are not willing to go to schools. But this is the case with urban students too. So, we have to take care of this and, for that, the Midday Meal Scheme is the solution. The Midday Meal Scheme, the Noon Meal Scheme, is not only a glamorous thing but also an essential one. But a minimum of ₹ 5,000 must be given as payment to the organiser who takes care of the cooking. Otherwise, it will not be effective. The Minister herself knows how difficult the cooking work is and how difficult it is for a woman to do this job. So, a minimum of ₹ 5,000 must be given. I think we are getting ₹ 2,000 as D.A. So, we have to give, at least, ₹ 5,000 to Midday Meal workers. Another thing is that we are also aware that corruption is going on at these Centres. Now, a photo identity card must be given to each and every student to check the malpractices which are going on. They enrol 200 students but, actually, only 20 students come. So, we have to be careful about that.

Then, Sir, another important thing is that 556 engineering courses and departments have been closed down in this year alone. Not only that, several engineering colleges have closed down and not even 50 per cent enrolment has taken palce. So, all the infrastructure which were available in those colleges should be utilised for other purposes.

[Dr. K. P. Ramalingam]

Finally, Sir, the hon. Minister must take care of the language issue. The language formula is a very sensitive issue. Imposing any language will create a problem. She is a very glamorous Minister, known all over the nation. She should not lose her glamour in South India. So she must be very careful to deal with the language issue. Thank you.

SHRI PALVAI GOVARDHAN REDDY (Telangana): Mr. Deputy Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on the working of the Ministry of HRD. We consider education and art as sacrosanct as God. That is why we equate education with Goddess Saraswati and if anybody tries to tamper with education or gives a religious colour to it is greatly doing disservice not only to education and the country, but also to our posterity. I am saying this because this Government is resorting to safronize education, and demand to restrain itself from doing so.

Sir, a lot has been said right from primary education to higher education and from Mid-Day Meal Scheme to providing hostels for boys and girls. So, I wish to focus on the fundamental issues. Rote learning or *Ratna* is still plaguing our education system. Students now are studying only to score marks in exams and sometimes to crack exams like IIT, JEE, AIIMS and CAT. The colonial masters introduced education systems in India to create clerks and civil servants, and we have not deviated much from that pattern till today. Earlier, if students prepared en masse for civil services and bank officers' exams, they now prepare to become engineers. So, there has to be a fundamental change in education in our country. Education has to be knowledge-based. Education has to be skill-based. Education has to be personalized, because one-size-does-not-fit all. And, we have to extensively use technology infrastructure for education. Sir, time given to me is too little. So, I cannot dwell on these issues elaborately. But, hon. Minister has, I am sure, understood what I intend to say.

The second point I wish to make is; Education or the place of education should not become a battleground for political parties. It is a shame that we have lost Rohit Vemula; it is a shame that we are sending police into university campuses; it is a shame that we are not appointing Nobel Laureates as Vice-Chancellors; and, it is a shame that faculty and Vice-Chancellors are not appointed on the recommendations of experts, but on recommendations of political masters of the day. So, this should be stopped if we want to transform our education and want some of our institutions become world-class universities or institutions.

The third point I wish to make is about Administrative Staff College of India. It comes under the Ministry of HRD. It was established in 1956 for providing training to civil servants and managers of corporate and Government sectors and urban management.

Over the years, it has been found that HRD Ministry is showing little interest in the functioning of ASCI, resulting in selection of DG, accused of sexual harassment on Senior Professor, wherein High court had also felt very serious and immediately ordered for an inquiry and he had to resign following an inquiry. Secondly, there are a lot of financial and administrative irregularities and HRD Ministry needs to conduct a performance audit of ASCI. I demand that CAG should audit accounts so that 5 crores' interestfree loan and 20 crores' grant-in-aid are optimally utilized. Thirdly and most importantly, the present Chairman has been in this position for the last 30 years and his age is 90 years. This matter requires serious inquiry as to how this man managed to continue for 30 years with all benefits! Fourthly, ASCI has properties worth thousands of crores and the Government of India should ensure that these properties are not sold off at a throwaway price on the plea of resource constraint. I am given to understand that ASCI is seriously pursuing to dispose some of the precious properties in Hyderabad in connivance with others. So, this should be stopped. And, the Ministry should undertake a complete overhaul of Court of Governors of ASCI under hon. Prime Minister's supervision. A separate body should be constituted to select DG and Chairman and ASCI should not become heaven for retired bureaucrats.

The next point I wish to make is about appoint of Vice-Chancellors of universities. A university without Vice-Chancellor is like a ship without Captain. There are about 10 Central Universities which do not have Vice-Chancellors. Some vacancies are as old as 3 years. It is not only the case relating to universities administered by the Government of India also universities that are run by various States, including Telangana. For example, in Karnataka, six universities do not have Vice-Chancellors. There are 8 or 9 universities in Telangana that do not have regular Vice-Chancellors thereby crippling academic, research and administration of universities. Research in almost all universities is stopped and there are not enough Professors to guide students. Osmania University, one of the oldest universities, which was granted University with Potential for Excellence by the UGC also does not have Vice-Chancellors.

In undivided Andhra Pradesh, earlier Chief Minister amended Universities Act and transferred all powers vested with Government to Governor in appointment of Vice-Chancellors based on recommendations made by Search-cum-Selection Committee. But, present Government of Telangana re-amended Universities Act and brought in Government control which is not good sign for academics and research.

Now, I come to vacancies in KVs. Sir, there are 228 vacancies of teaching staff in KVs of Telangana and 44 teaching vacancies in JNVs. What are the reasons for such huge vacancies? What the Ministry is doing to fill in these vacancies? Secondly,

[Shri Palvai Govardhan Reddy]

Ministry proposed to appoint retired teachers on voluntary basis in 18 States on pilot basis. I want to know what has happened to that proposal and how many teachers have volunteered to teach in Telangana and other States.

Sir, AP Reorganisation Act mandates GOI to set up Tribal University and Horticulture University in Telangana. But, so far, no tangible progress has been made. Secondly, the people of Telangana are also demanding for setting up of an IIM. But, nothing has been done. So, I request the hon. Minister to quicken the process of setting up of these institutions in Telangana as soon as possible.

With these observations, I thank you Sir once again for giving me this opportunity to speak on the functioning of the Ministry of HRD.

Thank you.

श्री बसावाराज पाटिल (कर्णाटक): माननीय उपसभापति जी, भारत जैसे बड़े देश में शिक्षा मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है, जहां पर 4 सेक्रेटरी स्तर के लोग काम करते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा मंत्रालय है। माननीय मंत्री जी से मैं इस विषय पर बात करते हुए कुछ विभिन्न प्वाइंट्स पर महत्वपूर्ण बातें बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले, मैं यह कहना चाहूंगा कि अभी सारे भारत में जो एक छोटा सा All India Entrance Test हो रहा है, यह राज्यों के लिए बहुत खतरनाक होगा। मुझे ऐसा डर लग रहा है, क्योंकि राज्य स्तर के जो बच्चे होते हैं, वे अपनी mother tongue में पढ़ते हैं।

मैं इसका एक छोटा उदाहरण बताता हूं। मैं जहां पर खड़ा हूं, यहीं मेरे सामने चार साल से मेरा नाम कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, क्योंकि इसको पहले इंग्लिश में लिखा जाता है और बाद में हिन्दी में अनुवाद होता है, इसलिए यहां 'बसावाराज' लिखा है, जब कि यह 'बसवराज' होना चाहिए। जब स्टेट के बच्चे परीक्षा में लिखेंगे, तो यही स्थिति होगी और उसका दुष्परिणाम होगा। देश में इसका बहुत विरोध होगा। कोर्ट के सामने केंद्र सरकार को वास्वतिक स्थिति के साथ प्रस्तुत होना चाहिए था। इसमें यह भूल हुई है। आगे आप इसे कैसे ठीक करेंगे, आप इसके बारे में सोचें, यह आपसे प्रार्थना है।

मेरी यह विनती है कि एक विभाग आपसे जुड़ा नहीं है, लेकिन इस देश का कल्याण होना है, इसलिए देश में ये जे आंगनवाड़ी नाम के विद्यालय चल रहे हैं, जिनमें लगभग 10 करोड़ बच्चे, छोटे-छोटे बच्चे, अनाथ और गरीब बच्चे हैं, कृपा करके इनको शिक्षा मंत्रालय में लीजिए। इनको पढ़ाने वाले जो लोग हैं, उनको रेग्यूलर टीचर बनाइए। इन टीचर्स को योग्यता के अनुसार प्रमोशन दीजिए, नहीं तो पीअन बना दीजिए। जब तक इन 10 करोड़ गरीब माताओं के बच्चों की जिन्दगी नहीं सुधरेगी, तब तक वास्तविक भारत का विकास नहीं हो सकता है। इस विषय में सरकार विशेष रूप से सोचे। इस संबंध में मैं सविनय प्रार्थना करता हूं।

आपने केंद्रीय विद्यालय के द्वारा देश के अंदर एक बहुत बड़ा विश्वास प्राप्त किया है, नवोदय विद्यालय के द्वारा एक बहुत बड़ा विश्वास प्राप्त किया है, लेकिन आज अन्य सारे सरकारी

विद्यालयों की संख्या हर राज्य में तेजी से घटती जा रही है। अगर सरकारी व्यवस्था के प्रति श्रद्धा घट जाएगी, तो यह देश के लिए दुखदायी बात होगी। वह राज्य सरकार का होगा या केंद्र सरकार का होगा।

मेरी सविनय प्रार्थना यह है कि ये जो तीन प्रकार के विद्यालय केंद्र सरकार के अधीन चलते हैं, इनकी संख्या दोगुनी कीजिए। इससे आपके ऊपर बजट का थोड़ा बर्डन ज्यादा हो सकता है, लेकिन कृपा करके आप माननीय प्रधान मंत्री जी से चर्चा करके केंद्रीय विद्यालयों की संख्या दोगुनी कीजिए, नवोदय विद्यालयों की संख्या दोगुनी कीजिए, कस्तूरबा विद्यालयों की संख्या दोगुनी कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगी, तो देश की करोड़ों जनता निश्चित रूप से आपको लाख बधाई देगी।

इसके साथ-साथ उच्च शिक्षा के अंतर्गत सबसे ऊंची जो दो शिक्षाएं होती हैं, उनके बारे में मैं कहना चाहता हूं। मैं आईआईटी और आईएएस के बारे में कहना चाहता हूं। मैं यहां नहीं कहना चाहता हूं, अगर आप प्राइवेट में सुनना चाहेंगी... आज कुछ राज्यों में परीक्षा में पास करने के लिए गलत धंधे अपनाए जाते हैं। कुछ राज्यों से ऐसे ही आईएएस पास हो रहे हैं। अगर आप पिछले दो साल का उनका performance देखेंगे, तो आप पाएंगे कि वे देश के लिए घातक हैं। क्या हमें इस देश को बरबाद करने वाले आईएएस को तैयार करना है? इसके बारे में आपको गंभीरता से विचार करना होगा।

देश में आईआईटी किसके लिए बनाए गए हैं? इनको देश को संवारने के लिए बनाया गया है या मल्टी-नेशनल कंपनियों के लिए बनाया गया है? इस संस्था से जितने लोग डिग्री प्राप्त करते हैं, उनमें से कम से कम 80 परसेंट लोग देश के काम में आने चाहिए। आज 90 परसेंट से ज्यादा लोग विदेशों की सेवा में जाते हैं और हम 10 परसेंट को लेकर रोते हैं। पैसा हमारा है, धरती हमारी है, लेकिन भलाई किसकी हो रही है? यह स्पष्ट है। इतने सालों से आए हुए इस रोग को दूर करने में आपको कठिनाई हो सकती है, परन्तु कोई न कोई रिस्क लेकर यह काम करने की आपको हिम्मत हो, यह मैं प्रार्थना करता हूं।

इसके साथ-ही-साथ सबसे भयानक चीज यह है कि आज की युवा पीढ़ी के अंदर आत्म-विश्वास का बड़ा अभाव देखने को मिलता है। अभी उत्तर प्रदेश के पीएचडी किए हुए 253 लोगों ने पीअन की पोस्ट के लिए आवेदन किया। जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा, तो पीएचडी करने वाला कहता है कि मुझे वह सब मालूम नहीं है, मुझे तो economic security चाहिए। अगर 25 साल की पढ़ाई के बाद भी आदमी अपने पैर पर खड़ा नहीं हो सकता है, तो इस देश के लिए, इस शिक्षा पद्धति के लिए सबसे बड़े अपमान की बात है, इसलिए बचपन से ही बच्चों को आत्म-विश्वास की शिक्षा देना अत्यंत आवश्यक है। इस दिशा में सरकार गंभीरता से सोचे, ऐसी मैं आपसे विनती करता हूं। इसके साथ-साथ, आज हमारे देश के अंदर यह मानसिकता बनी है कि पढ़ाई यानी नौकरी। किसी के मन में मालिक बनने की बात नहीं है, किसी के मन में तपस्वी बनने की बात नहीं है, किसी के मन में अनुसंधान करने की बात नहीं है, बस केवल यह है कि नौकरी मिल जाए। इसीलिए शिक्षा ज्ञान के लिए होनी चाहिए। शिक्षा अभी तक साक्षरता के लिए थी, डिग्री के लिए थी, अब थोड़ा स्किल के लिए भी सोच रहे हैं, लेकिन बिना ज्ञान के देश का कल्याण नहीं हो सकता है। उसके समान ध्यान कोई दूसरा नहीं हो सकता है। ...**(समय की घंटी)**... इस दिशा में आप ध्यान दें, यह मेरी आपसे विनती है।

[श्री बसावाराज पाटिल]

साथ ही साथ, हमारा भौतिक विकास तो बहुत हुआ है, लेकिन हमें आंतरिक विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आज के छोटे-छोटे बच्चे जिस प्रकार की चीज़ नशे में खाते हैं, जिस प्रकार की आदत में वे लिप्त हैं, उसमें कल का भारत अंधकारमय दिख रहा है। मुझे यह सुनकर बहुत डर लगा कि आज गांवों में betting के अंदर 10-10 लाख रूपये से लेकर करोड़ रूपये तक जवान बच्चे बरबाद कर रहे हैं। अगर इसे रोकना है, तो हमारी शिक्षा-नीति में एक नई सोच की आवश्यकता है, इसके लिए मैं आपसे विनती करता हूं।

[**उपसभाध्यक्ष (श्री वी. पी. सिंह बदनौर)** *पीठासीन हुए*]

इसके साथ ही, हमारे देश की जो अनमोल सम्पति है, वह ट्राइबल है। वे असम के सप्तकन्या राज्य हो सकते हैं, या ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के अन्य ट्राइबल क्षेत्र हो सकते हैं। जैसे पहाड़ों में अनमोल खनिज सम्पत्ति है, वैसे ही अनमोल व्यक्ति इन ट्राइबल एरियाज़ में रहते हैं, उन पर अगर आप अच्छी तरह से ध्यान देंगे तो देश के असल हीरे बाहर आएंगे और वे इस भारत मां को उसकी गरिमा के अंदर ले जाएंगे। इस दिशा में विशेष रूाप से सोचना अत्यंत आवश्यक है। ...**(समय की घंटी)**... इसी तरह, हम अपनी शिक्षा में अपने बच्चों को बचपन से ही अगर लाइफ स्टाइल और फूड स्टाइल के बारे में बताएंगे कि हमें कैसे जीना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए, तो यह देश हित के लिए उत्तम होगा। इस प्रकार, मैं अपने देश की शिक्षा-नीति के बारे में बताते हुए आपसे विनती करता हूं, कि हमारे प्रधान मंत्री जी के साथ बात करके मैंने कुछ जो सलाह दी है, उसके लिए बजट में ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन हमारी पार्टी की शिक्षा-नीति वह है, जो गाधी जी कल्पना है, मदन मोहन मालवीय जी की कल्पना है, विनोबा भावे की कल्पना है, आचार्य धर्मपाल की कल्पना है, पं. दीनदयाल उपाध्याय की कल्पना है, विवेकानन्द की कल्पना है और जो धरती से जुड़ी हुई है। इससे विचलित न होते हुए अगर दुनिया के 200 विश्वविद्यालयों के इतिहास में हमारा नाम न भी आए तो हमें इसकी चिन्ता नहीं है, लेकिन हमारी शिक्षा-पद्धति हमारी धरती से जुड़ी होनी चाहिए, यह विनती करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI ANIL DESAI (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you. The education sector influences the future of the nation and, therefore, it should ascend in importance. Simply put, education can fuel Government's ambitious programmes such as 'Make in India', 'Digital India', and 'Skill India'. The impact of this sector can be felt both by the industry and the common people and, of course, it is an investment into the future. A welleducated population is the key to the economic growth of the country. Therefore, the Government's agenda to revive the economic growth must include strengthening of the education system further.

Sir, the National Policy on Education stipulates that investment in education should be gradually increased so as to reach a level of expenditure of 6 per cent of the national income as early as possible. Sir, if you happen to compare the last year's Budget with the current one, there is a rise of 3 per cent in the budgetary allocation in school sector. Of course, there is an increase of 7.3 per cent in the

7.00 P.M.

budgetary allocation for the higher education compared to the last year's provisions. This increase in the education Budget is a welcome step and, I am sure, very soon, expenditure on education will reach its desired level of 6 per cent of the GDP.

Sir, it is a fact that overall condition of most of the schools, that too Government schools across India, is poor and needs to be improved. Therefore, this should be given topmost priority over other scheduled educational programmes. Also, Mid-Day Meals programme needs strict monitoring and accountability if it is to continue further. In order to improve Gross Enrolment Ratio (GER) across schools and colleges, and increase student retention, we have to focus on increasing collaborative efforts between the private sector and the Government to promote quality education for all. There is a need to substantially add quality institutions to ensure that Indian students do not need to look overseas for higher education. *Sarva Shiksha Abhiyan*, which is the vehicle for the Right to Education (RTE) has been allocated ₹ 22,500 crores in this Budget, an increase of 2.2 per cent over the last year's Budget. Out of the resources provided by the Government, only 8 per cent schools comply with the infrastructure norms mentioned under the RTE Act. Sir, 8.3 per cent schools have single teacher; it seems that the overall pool of resources by the Union Government is inadequate to fulfill the RTE norm in all elementary schools. Basic school infrastructure, teacher training, teacher recruitment, community mobilisation are some of the basic factors to improve quality of education. I hope hon. HRD Minister will do her best to cater to the needs of the respective categories successfully with the resources available and build up a strong educational system in the country.

Similarly, the *Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan* for universalisation of secondary education, and *Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan* for higher education are already in operation and they too need, not only proper budgetary allocations, but, also proper monitoring for their success.

To promote girls' education, I thank the Government that they have announced a number of schemes like *Beti Bachao Beti Padhao*, PRAGATI, UDAAN, Swami Vivekananda Single Girl Child Scholarship in the last two years. Sizeable budgetary allocations are needed to support the above schemes in their implementation. I am sure the hon. HRD Minister would ensure the success of these schemes in the years to come.

Here I would like to congratulate the HRD Minister for the timely intervention and taking steps to discontinue the four-year undergraduate programme of Delhi University, which was not recognised and approved by the authorities. It would have spoiled the careers of not less than four lakh students, if allowed to continue.

[Shri Anil Desai]

While commemorating the 125th Birth Anniversary of Dr. Babasaheb Ambedkar, I would urge upon the HRD Minister to allocate sufficient funds towards special scholarships to SC/ST students and a special drive to send deserving students abroad for higher studies.

Higher education in India affects around 30 million youths in the age group of 18-23 years, who are enrolled in our colleges and universities. More than 300 State universities and around 35,000 colleges account for more than 90 per cent of the enrolment in higher education. It is observed that State universities suffer from poor governance, insufficient faculty, infrastructure and shortage of funds. I am sure, the hon. Minister would take corrective steps to strengthen the States' higher educational institutions.

Sir, ₹ 1,000 crores have been allocated in the current Budget for infrastructure development of higher education. I hope it is meant for the States' higher educational institutions. In his Budget Speech, hon. Finance Minister said that the Government would strive to help ten private and ten public institutions to become world class institutions. This is a welcome step towards empowering select institutions of excellence to compete at the global level.

Sir, I would like to mention about vocational courses which were started by the Central Government in the 90s in banking and insurance sector. It was a vocational course at 10+2 level which ensured services in the banking and insurance industry. For around five to six years, this course was continued and gave jobs to thousands of youths in the country. That was really a very effective step by the Government to address the problem of unemployment. I think, the Central Government might know as to what the reason was for stopping that course. I would request the hon. HRD Minister to reconsider restarting those courses which would address the problem of unemployment.

Creation of Higher Education Funding Agency (HEFA) has been announced with a fund of ₹ 1,000 crore initially. This agency can play a catalyst in designing a new scheme of educational loan with low interest rates and long payment period. Currently, only 1.5 per cent students are getting educational loans due to high interest rates and lengthy procedures. Most of the student fraternity is deprived of this costly facility.

Sir, there are one or two more points which I wish to make. Sir, recently, the litigation which is pending in the Supreme Court regarding the National Eligibility Entrance Test has created furore in most of the States. In the State of Maharashtra, what we had envisaged, the Maharashtra State Government has taken the care.

...(*Time-bell rings*)... Those students who have prepared for the test, *i.e.*, MH-CET, today only they are appearing for the exam; thousands and lakhs of students must have appeared for the exam. The main thing is, the syllabus of NEET is based on CBSE level, whereas in the State Government, it is based on the State level. So, mixing of the two syllabuses should not be there. At least, the Government should take care of it. I would urge upon the hon. Minister to take it to the Supreme Court to see that this is not mixed up, and, at least, two years' period be given to the students so that they take up extensive study during that period. That will be of great help to the students.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. P. SINGH BADNORE): Thank you very much.

SHRI ANIL DESAI: Sir, last but not the least, I hope the HRD Minister while framing the New Education Policy, which is on the anvil, will take all the stakeholders on board and make a very strong and comprehensive Education Policy. Thank you, Sir.

श्री राम कुमार कश्यप (हरियाणा): उपसभाध्यक्ष महोदय, आज़ादी के बाद हमारे देश ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उन्नति की है। आज़ादी के समय हमारा literacy rate जो 18 परसेंट था, वह बढ़कर अब 74.04 परसेंट हो गया है। आज़ादी के समय स्कूलों की, विद्यालयों की, महाविद्यालयों की बहुत कमी थी, यहां तक कि 10वीं की शिक्षा ग्रहण करने के लिए दस-दस किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, तब जाकर कोई बच्चा शिक्षा ग्रहण करता था। जब कॉलेज की शिक्षा ग्रहण करनी होती थी, तो 40-40 किलोमीटर तक जाना पड़ता था। उस समय प्राइमरी स्कूलों की अपनी बिल्डिंग नहीं होती थी। प्राइमरी शिक्षा के लिए गांव की चौपालों, मस्जिदों, धर्मशालाओं में शिक्षा ग्रहण की जाती थी। कई प्राइमरी स्कूलों में तो एक-दो ही कमरे होते थे और उसकी चारदीवारी होती ही नहीं थी। जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, तो हम जंगल से कांटे वाली लकड़ी काटकर लाते थे और स्कूल की चारदीवारी बनाया करते थे। खुद जाकर स्कूल की सफाई करते थे। उस समय स्कूल में बैठने के लिए टाट, बैंच इत्यादि नहीं होते थे। स्कूल में पानी की और शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं होती थी। परन्तु उस समय पढ़ाई बहुत अच्छी थी। शिक्षा की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। आज हर जगह स्कूल्स हैं, महाविद्यालय हैं, न जाने कितनी यूनिवर्सिटीज़ खुल गई हैं, अब स्कूलों की अपनी बिल्डिंग्स हैं, शौचालय हैं, पीने के पानी की व्यवस्था है, परन्तु इसके बावजूद भी हमारे देश में शिक्षा का स्तर निरंतर गिरता जा रहा है, विशेषकर जो हमारे सरकारी प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स हैं, उनमें शिक्षा की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। आज आठवीं पास बच्चे को पांचवीं की किताब पढ़ना नहीं आता है और पांचवीं पास बच्चे को दूसरी क्लास की किताब पढ़ना नहीं आता है। अंग्रेजी की स्थिति तो बहुत ही चिंताजनक है। आज दसवीं और बारहवीं वाले बच्चे को अगर कह दिया जाए कि वह जाता है, मैं जाता हूं की अंग्रेजी बना दो, तो वह बिल्कुल नहीं बना पाएगा। अंग्रेजी की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है।

इस वजह से हर मां-बाप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लग गया है। सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वे केवल एस.सी. और बी.सी. के बच्चे पढ़ रहे हैं, जो गरीब लोग हैं। माननीय मंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो राइट टू एजुकेशन का एक्ट, 2009

[श्री राम कुमार कश्यप]

में आया है, इसका भी इसमें अहम योगदान है। यह ठीक है कि इसके आने से 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिला, उनको मुफ्त शिक्षा मिली, स्कूलों में बच्चो के दाखिले बढ़े, शौचालय बने, बिल्डिंग्स बनीं, परन्तु इसमें एक प्रावधान है जिसके अनुसार कक्षा एक से कक्षा आठ तक के बच्चों को फेल नहीं किया जाता है। पहले कक्षा पांच और कक्षा आठ की बोर्ड परीक्षा होती थी, उसे खत्म कर दिया गया, इस कारण से आज बच्चा पढ़े या न पढ़े, उसको आठवीं तक पास कर दिया जाता है। आज बच्चे को यह चिंता नहीं है कि अगर मैं नहीं पढूंगा तो मुझे फेल कर दिया जाएगा। जब ये बच्चे आठवीं कक्षा से पास होकर नौवीं कक्षा में, दसवीं कक्षा में जाते हैं, तो ये अपने आपके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और दूसरे बच्चों तथा टीचर्स/अभिभावकों के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इसीलिए हमारा जो दसवीं और बारहवीं का रिजल्ट आता है, वह बहुत निम्न आता है, बहुत डाउन आता है। हरियाणा प्रदेश में पीछे दसवीं कक्षा का 40 per cent और बारहवीं कक्षा का 50 per cent रिजल्ट आया यानी 50 per cent बच्चे फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनकी नींव बहुत कमजोर होती है। यह बहुत ही चिंताजनक विषय है। मैं मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहूंगा और कई माननीय सदस्यों ने भी कहा है... यह नई शिक्षा नीति कब आएगी? उसके आने से पहले स्कूलों में पहले जो बोर्ड की परीक्षा होती थी, उसको पुनः लेने का काम करें। आप कम से कम आठवीं कक्षा तक बोर्ड की परीक्षा लेने का काम करें, ताकि जब बच्चों की परीक्षाएं हों और जो बच्चे सीरियस नहीं हैं, वे फेल होकर नीचे न रह जाएं और अच्छे बच्चे आगे चले जाएं। आज अध्यापकों से गैर शैक्षिक काम लिए जाते हैं, चाहे वह चुनाव की ड्यूटी है या जनगणना का काम है, चाहे वह वोट बनाने का काम है या फिर स्कूलों में मिड-डे-मिल का काम है। इसमें कई अध्यापकों की ड्यूटी लग जाती है और वे सारा साल इसी काम में लगे रहते हैं तथा बच्चों को पढ़ाने का कोई काम नहीं होता है, इसलिए शिक्षा में बड़ी गिरावट आ जाती है। मैं इसके लिए आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि यदि possible हो सके, तो अध्यापकों से गैर शैक्षिक कार्य न लिए जाएं। विशेष रूप से स्कूलों में जो मिड-डे-मिल बनाने का काम है, वे अध्यापक करते हैं, परसेंट यह काम किसी दूसरी एजेंसी को देने का काम करें, जो खाना बनाने का काम करती हैं। अध्यापकों से कम से कम यह काम न लिया जाए। शिक्षा के स्तर का डाउन होने का जो तीसरा मेन कारण है, वह शिक्षकों की कमी और उनके तबादले हैं। महोदय, आज स्कूलों में शिक्षकों की बहुत कमी है। अब टीचर्स की भर्ती कमीशन के द्वारा होती है। इस प्रोसेस में सालों लग जाते हैं और स्कूलों में टीचर्स की जो कमी होती है, उसके कारण बच्चे सफर करते हैं। जब टीचर्स का तबादला हो जाता है, विशेष रूप से मैथ्स और इंग्लिश टीचर्स का, तो सालों उनकी जगह पर नए टीचर्स नहीं आते हैं, तो बच्चों का मैथ्स और अंग्रेजी का काफी नुकसान होता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षकों की कमी को दूर किया जाए। जब तक भर्ती द्वारा टीचर्स नहीं आते हैं, जो स्कूल का इंचार्ज, हैडमास्टर है या प्रिंसिपल है, उसको अपने लेवल पर कांट्रेक्ट बेस पर या डेली वेजेज़ पर अध्यापक नियुक्त करने की अनुमति होनी चाहिए, ताकि टीचर्स की कमी न रहे।

मैं एक चीज और मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि आज शिक्षा बहुत महंगी हो गई है। आज गरीब से गरीब बच्चा भी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, परन्तु गरीबी के कारण वह उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। मैं भी जब 1976 में लॉ में एडमिशन लेना चाहता था, उस समय दाखिले में 200, 300 रुपए लगते होंगे, मेरे दाखिले में 100 रुपए की कमी रह गई थी, मैं लॉ में एडमिशन नहीं ले सका था। ...(**समय की घंटी**)... इसलिए यह तो एक उदाहरण है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V.P. SINGH BADNORE): Thank you. ...(*Interruptions*)...

श्री राम कुमार कश्यपः हिन्दुस्तान में ऐसे कितने ही गरीब बच्चे हैं, जो पैसे की कमी के कारण दाखिला नहीं ले पाते हैं और उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जो गरीब बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उनके लिए फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एजुकेशन लोन देने की सुविधा होनी चाहिए, ताकि उस लोन से गरीब बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण करके राष्ट्र निर्माण में अपना अहम योगदान दे सकें।

श्री नीरज शेखर (उत्तर प्रदेश)ः सर, मिनिस्टर का रिप्लाई भी आज ही होगा?

उपसभाध्यक्ष (श्री वी.पी. सिंह बदनौर)ः अभी होगा, अभी होगा।

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानीः मैं आज ही रिप्लाई दूंगी।

एक माननीय सदस्यः कल कर लेंगे।

श्री नीरज शेखरः सर, कल अगस्ता पर चर्चा हो रही थी, तब पूरा सदन भरा था। आज शिक्षा पर चर्चा हो रही है, तो सदन खाली दिखाई दे रहा है। जब सूखे पर चर्चा होती है, तब भी सदन खाली दिखाई देता है। मैं यही तो कह रहा हूं, यही तो इस देश का दुर्भाग्य है कि हम लोग शिक्षा के प्रति कितने जागरूक हैं, आज हमें यह पता चल रहा है। ...(**व्यवधान**)...

श्री भुपेंद्र यादव (राजस्थान)ः आप चर्चा कर रहे हैं, इसलिए आप हैं। ...(**व्यवधान**)....

उपसभाध्यक्ष (श्री वी.पी. सिंह बदनौर)ः आप प्लीज़ बंद करिए। डी. राजा। ...(**व्यवधान**)....

श्री नीरज शेखरः मैं तो प्रतीक्षा कर रहा हूं ...(**व्यवधान**).... मैं खड़ा हो गया था। ...(**व्यवधान**)....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. P. SINGH BADNORE): Don't worry, serious Members are always here. ...(*Interruptions*)...

SHRI NEERAJ SHEKHAR: So, only thirty-five Members are serious. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. P. SINGH BADNORE): I don't know. ...(*Interruptions*)... Shri D. Raja.

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, I share the strong feelings expressed by my respected colleague, Shri Neeraj Shekhar.

We are discussing the Ministry of HRD. The Ministry of HRD is a very key Ministry of the Government. We all know the Human Development Index of our country. It is one of the lowest in the world. On one side, we are proud of the achievements being made by the ISRO; on the other hand, we continue to be the home for the largest number of illiterates in the world. Here, I think the Ministry of Human Resource Development has a great task and it has to discharge the mandate given by the people.

[Shri D. Raja]

Sir, when I rise to speak on this Ministry, one should not think we are only making criticism. We are fair in our criticism; we are equally fair in our appreciation. There was a problem in Delhi University with regard to the four-year course. Teachers were agitating and students were also agitating. The Ministry accepted that position and took a favourable position on that. In the same manner, there was a problem in Vishwa Bharathi University. The Ministry took a favourable position. I can say there was a problem in Coimbatore Avinashilingam University for women and the Minister assured that that would continue as a public-funded institution, implementing the UGC guidelines. These are all certain good things the Ministry did and the Minister personally intervened. Having said that, I urge upon the Minister and the Ministry to address certain urgent issues. In Jawaharlal Nehru University, there is a problem. The University Authorities have taken some disciplinary action against students, including the Students' Union President. The students think this action is disproportionate. They are asking the authorities to reconsider their action. They are on an indefinite fast. The Students' Union President has been shifted to hospital because of his ill health. Tomorrow, what will happen, I do not know. I am asking the Minister whether she can advise the University Authorities not to go for such action against the students. After all, they are students! They are the future of our nation. Their interest must be our concern, concern of this Parliament, concern of the Ministry and concern of the Government. So I urge upon the Ministry to advise the authorities to reconsider their action so that students get out of this turmoil. This is exam time. They will have to prepare for their exams. They will have to write down their dissertations. So, these are all real issues. I hope the Minister and the Ministry understand. In the same way, in Hyderabad Central University, there are problems. My colleagues also referred to it. What they are saying is, bring back the normalcy in the University. To restore normalcy in Hyderabad Central University, they say the present Vice-Chancellor can be replaced, and the Ministry can take a call on this. They say there is a discrimination against the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe students, and also against the OBC students in Central Universities. In order to contain this discrimination, let there be a Rohith Act. I don't think the HRD Ministry alone can do this, but she can very well take up the issue with the Goverment in the Cabinet. This is a demand coming up. Sir, in Allahabad University also there is a problem. Why to subject our children and our students to such ordeals/sufferings? The Minister personally should intervene and the Ministry also should intervene to help our students. Sir, my colleague referred to the philosopher poet, Thiruvalluvar. I would also refer to the philosopher poet, Thiruvalluvar. He is the source of our inspiration. He says, arithmetics and alphabets are the real eyes for any human being.

'*Ennum ezhuthum kannena thagum*.' That means, arithmetics and alphabets are the real eyes. We have eyes but the real eyes that one should have are arithmetics and alphabets. He emphasized the importance of education. So, the HRD Ministry has the responsibility to spread education. But, Sir, what is the budgetary allocation for education? The 1966 Kothari Commission Report was presented, and the first line of the Kothari Commission says, 'The destiny of India, the nation, is determined in classrooms'. The destiny is determined in classrooms. And, what is the spending on education? Prof. Kothari proposed that six per cent of the GDP should be spent on education. Now we are in 2016. But I do not think we are spending even four per cent or five per cent on it. I doubt. Even now it cannot be six per cent. Ideally speaking, it should be ten per cent or more than ten per cent. Sir, every nation is speaking about spending more on education, more on health. Why doesn't India spend more on education? The Minister should take it up. We will fight with the Finance Ministry, if you have constraints. You take it up with the Finance Ministry. You do not have enough money to spend on education. ...(*Time-bell rings*)...

Sir, coming to some vital issues, it is true that we have passed the Right to Education Act and the Right to Education Act takes care of children from 6-14 years. Ideally speaking, we should have free and compulsory education up to the secondary level. The Government should think on this line. ...(*Time-bell rings*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. P. SINGH BADNORE): Please.

SHRI D. RAJA: It is important, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. P. SINGH BADNORE): I know. Everything is important.

SHRI D. RAJA: Now, many people spoke on Mid Day Meals. Yes, that is why the Gross Enrolment Ratio is high as far as the elementary education is concerned and the drop-out is also relatively less in comparison to secondary education and other things. It is because there is an element called 'Mid Day Meal' but the Mid Day Meal cooks are not treated as workers. It is not her problem. They are not being paid well. The salary has to be increased. It is not her problem. I am not asking her. But I ask her to fight with the Finance Ministry. We will also support you, and we will ask the Finance Ministry. ...(*Time-bell rings*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. P. SINGH BADNORE): Okay. Thank you.

SHRI D. RAJA: Let me finish, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. P. SINGH BADNORE): Okay, your last point.

SHRI D. RAJA: On higher education, Madam, you should understand that, for the first time, the first generation of SC/ST/OBC boys and girls are entering into institutions of higher learning whether it is JNU or Delhi University or Hyderabad University or Allahabad University or any other University. These are all first generation students who are entering into these universities and they are being harassed. For instance, they need remedial coaching. In fact, they are targeting the SC/ST students. ...(*Time-bell rings*)... I will finish, Sir. Let me finish. There must be a special effort to plug the drop-out of SC/ST students.

Then, Madam, there is delay in scholarships. Students are finding it difficult. You must be aware of the problem, and it should be addressed. Even my friend, Shri Anil Desai was saying ...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V.P. SINGH BADNORE): 'SC/ST' is a very important point which you are raising. But please conclude.

SHRI D. RAJA: The SC/ST and OBC students must be given opportunity for foreign visits and there must be reservation in Ph.D. and Research Associate positions. There is a problem. These are all certain immediate issues which can be taken up. There are larger issues. I know you are working on New Educational Policy and the philosophy must be the one which is in tune with our Constitution. ...(*Time-bell rings*)... No other philosophy should influence the philosophy of education.

Sir, finally, I would like to tell the Ministry that there should not be any attempt to reverse the policies, which have a democratic and secular character. While education is becoming commercialized, privatization is on a high, the Government has a greater role to play to protect the interests of the socially, educationally oppressed sections of our society, particularly *Dalits, Adivasis*, OBCs and the minorities. People should understand this. So, the Ministry has a role cut out for itself on all these matters. I hope the Ministry would be sensitive to these issues and act accordingly without any further delay.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. P. SINGH BADNORE): Shri Ramdas Athawale, not present. Mr. Punia, you were absent earlier. You can take two minutes to make your points. He was absent and I am being generous. आप शुरू कीजिए।

श्री पी. एल. पुनिया (उत्तर प्रदेश)ः सर, सुबह मैं यहां पर नहीं था।

उपसभाध्यक्ष (श्री वी. पी. सिंह बदनौर)ः जी हां, मैं इसीलिए कह रहा हूं। जब आप नहीं होते हैं, तो आपका चांस चला जाता है। ठीक है, अब आप बोलिए।

श्री पी. एल. पुनियाः उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने का मौका दिया। शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसी के माध्यम

से व्यक्ति सशक्त होता है। बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर जी ने सबसे ज्यादा महत्व शिक्षा को ही दिया था और कहा था, "शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो"। इसके पीछे एक रहस्य है। विशेष रूप से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को शिक्षा से वंचित रखा गया, बाकी के कारोबार से वंचित रखा गया, लेकिन बाबा साहेब ने माना कि शिक्षा के माध्यम से ही वे आगे बढ़ सकते हैं।

अभी बताया गया कि बहुत प्रगति हुई है। कश्यप जी अभी बता रहे थे कि हमारी साक्षरता दर 74 प्रतिशत है, लेकिन अनुसूचित जाति में यह दर 66 प्रतिशत है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि एक-तिहाई लोग अभी भी निरक्षर हैं। ऐसा इसलिए है, क्योंकि उन्हें पढ़ने का चांस ही नहीं मिला। मैं इसे थोड़ा विस्तार से बताना चाहूंगा। अनुसूचित जाति की जो 66 प्रतिशत साक्षरता दर है, उसमें 41 फीसदी प्राइमरी से भी कम शिक्षित हैं, लेकिन उन्हें शिक्षित श्रेणी में मान लिया गया। 41 फीसदी लोगों की शिक्षा प्राइमरी स्कूल से भी कम है, केवल 15 फीसदी लोगों की शिक्षा प्राइमरी स्कूल तक है। अगर डिग्री और डिग्री से ऊपर पढ़े लोगों के बारे में देखा जाए, तो उसमें केवल 2.5 प्रतिशत लोग ही आते हैं। आज इस चीज़ की आवश्यकता विशेष रूप से है कि सबसे पहले प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ाया जाए। प्राइमरी एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के माध्यम से शिक्षा की शुरुआत होती है और इसी के माध्यम से शिक्षा की नींव पड़ती है। अगर नींव ही कमजोर होगी, तो आगे की शिक्षा सही ढंग से नहीं हो पाएगी।

जब 41 प्रतिशत लोग प्राइमरी से भी कम पढ़े हैं और 15 प्रतिशत प्राइमरी स्कूल तक पढ़े हैं, इसका मतलब यह हुआ कि केवल 10 फीसदी लोग ही प्लस टू और डिग्री तक पहुंचे हैं और उनमें से भी 2.5 प्रतिशत लोग डिग्री और डिग्री से ऊपर पहुंच पाए हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इसके ऊपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। एक आकलन के अनुसार क्लास फोर में अधिकतर उन कम पढ़े-लिखे लोगों की नौकरियां लगती हैं।

अभी जो Socio-Economic and Caste Census, 2011 आया है, उसके हिसाब से अनुसूचित जाति के केवल 4 फीसदी परिवार ही सरकारी नौकरियों में हैं और 2.5 फीसदी परिवार प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं। इस तरह 4 प्रतिशत और 2.5 प्रतिशत परिवारों को ही नौकरियों में प्रतिनिधित्व मिल पाया है, यह बड़े अफसोस की बात है। आज जरूरत इस बात की है कि उनकी शिक्षा के ऊपर विशेष जोर देना चाहिए, साथ ही क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर जोर देना चाहिए। आज शिक्षा का स्तर बहुत गिर गया है। किसी-किसी विद्यालय में टीचर्स ही नहीं हैं और अगर टीचर्स हैं भी, तो पढ़ाते नहीं हैं, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्वॉलिटी एजुकेशन के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय एक ऐसा concept है, जिसे सब जगह दोहराना चाहिए। आपने तय किया है कि एक जिले में एक जवाहर नवोदय विद्यालय अवश्य खोलेंगे, लेकिन आवश्यक यह है कि ये हर ब्लॉक में खुलें। अगर जवाहर नवोदय विद्यालय हर ब्लॉक में खुलेंगे तो क्वॉलिटी एजुकेशन अवश्य मिलेगी। इसलिए इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ध्यान देने का मतलब यह होता है कि हम बजट बढ़ा दें, उस पर ज्यादा फोकस दें, लेकिन आपने तो बजट कम कर दिया। आप overall यह कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में बजट ज्यादा हुआ है, लेकिन वह केवल हायर एजुकेशन में आपने किया है। प्राइमरी एजुकेशन, जो कि स्कूल एजुकेशन है, उसका बजट आपने कम कर दिया, "सर्व शिक्षा अभियान" में आपने बजट कम कर दिया, "मिड-डे मील" में आपने बजट कम कर दिया, pre-matric scholarship, post-matric scholarship में आपने बजट

[श्री पी. एल. पुनिया]

कम कर दिया। इसी तरह माइनॉरिटीज़ की स्कॉलरशिप है, तो उसमें भी आपने बजट कम कर दिया। जो बेसिक चीज़ें हैं, जो आम आदमी से जुड़ी हैं, उन मदों पर तो आपने बजट कम कर दिया, यह बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए इसको बढ़ाया जाना चाहिए। हम तो अच्छी तरह से जानते हैं कि स्कॉलरशिप के आधार पर वे यहां तक पढ़े, लेकिन आज तीन-तीन साल और चार-चार साल से उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। लोग मांग करते हैं कि वह उनको मिले, लेकिन भारत सरकार से पैसा राज्य सरकारों तक नहीं पहुँचा, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि राज्य सरकारों को पूरा पैसा मिले।

अब मैं Right to Education के ऊपर ध्यान दिलाना चाहूँगा कि उसके ऐक्ट में सेक्शन 12 है, उसमें लिखा है कि 25 परसेंट सीटें Economically Weaker Sections या deprived sections को देनी चाहिए। संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन RTE के माध्यम से वह प्रावधान खत्म है, वह economic consideration तथा deprived sections के आधार पर किसी को भी दिया जा सकता है। परसेंट हमने यह प्रस्ताव रखा था कि 25 परसेंट में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए भी एक विशेष व्यवस्था रखी जाए, ताकि उनका एडमिशन सुनिश्चित हो सके।

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair*)

सर, अभी डी. राजा साहब ने कैम्पस के बारे में कहा। इस तरह की टकराव की स्थिति पहले कभी नहीं आई, लेकिन आज एक विशेष विचारधारा को थोपने की कोशिश की जा रही है। ...(**व्यवधान**)... इसलिए जगह-जगह पर ऐसा हो रहा है। आप IIT, मद्रास की बात ही ले लीजिए। वहां अम्बेडकर-पेरियार स्टडी सर्किल को बिना किसी क़ानून के बैन किया गया और वह वापस लिया गया। फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हैदराबाद में समस्या हुई। वहां रोहित वेमुला को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आखिर ये परिस्थितियां क्यों हैं? जेएनयू के साथ-साथ बाकी जगहों पर भी ऐसा हो रहा है।

माननीय मंत्री जी ने वाइस चांसलर्स की एक बैठक बुलाई। हम समझे कि रोहित वेमुला वाले केस के तत्काल बाद बैठक हो रही है, तो कैम्पस में आमूल-चूल परिवर्तन करने के आदेश दिए जाएँगे। हमने यह अंदाज़ लगाया था, लेकिन दूसरे दिन हमने अख़बारों में देखा कि मंत्री जी ने कहा है कि 240 फीट ऊँचा एक तिरंगा झण्डा लगेगा। तिरंगा झण्डा जरूर लगे, लेकिन जिन परिस्थितियों में, जिस पृष्ठभूमि में वह मीटिंग हुई थी, उसके हिसाब से हम उम्मीद करते थे कि अनुसूचित जाति के छात्रों के खिलाफ कैम्पस में जो भेदभाव होता है, उसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए कुछ न कुछ बात हुई होगी, लेकिन उस तरह की बात नहीं हुई। एएमयू में भी इसी तरह की स्थिति पैदा हो रही है। वहां पर एक नई बात की जा रही है।

सर, अब मैं एक लास्ट प्वाइंट कह कर अपनी बात खत्म करूँगा। Private professional institutions के बारे में ये आंकड़े हैं कि टोटल सीट्स की 43 फीसदी सीट्स private unaided institutions में हैं और बाकी की 55 परसेंट non-private में हैं, जिनमें गवर्नमेंट के हैं, लोकल बॉडीज़ के हैं और aided private institutions हैं। उनमें अनुसूचित जाति का केवल 2 परसेंट रिप्रेजेंटेशन है। जिसकी आबादी 25 परसेंट है, उसे आप 2 परसेंट का प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमें इसको एड्रेस करना चाहिए। जो भागीदारी उसमें उपलब्ध हो सकती है, वह

भागीदारी उन्हें मिलनी चाहिए। इसके लिए संविधान में संशोधन करके इसको किया जाए। इसके लिए संविधान में प्रावधान है कि अन-एडेड इंस्टीट्यूशन्स में भी आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन आरक्षण की व्यवस्था होने के बावजूद भी वहां वह प्रतिनिधित्व नहीं है। सरकार को इसमें हस्तक्षेप करके इसको सुनिश्चित करना चाहिए। मैं विशेष रूप से यह कहना चाहूंगा कि जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राइमरी एजुकेशन है, इसके ऊपर जोर दिया जाना चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन दिया जाना चाहिए और बजट में जो कटौती की गई है, बजट में कटौती को बहाल करके इसको ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। विशेष रूप से जो स्कॉलरशिप की दिक्कत है, स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, उसके ऊपर ध्यान देते हुए सैंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के कैम्पसेज़ में जो तनाव की स्थिति है, उस तनाव की स्थिति को खत्म करना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री नरेश अग्रवालः सर, हमारी पार्टी से श्री रवि प्रकाश वर्मा दो मिनट बोलना चाहते हैं, उनको बोलने दिया जाए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Will he finish within two minutes? If it is two minutes, I can allow. Mr. Ravi Verma, you can take two minutes. After two minutes, the mike will be switched off.

श्री रवि प्रकाश वर्मा (उत्तर प्रदेश): सर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दे दिया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से बात करना चाहता हूँ। Sir, India is a rich country inhabited by poor people. जब मैं यह सुनता हूँ, तो मुझे गाली जैसी लगती है। आज़ादी के 69 वर्षों में आज यह हालत है कि धरती का सबसे समृद्ध देश एक ऐसी टिप्पणी का शिकार है। मैं और लोगों को दोष नहीं देता, कहीं न कहीं कमी हमारे अंदर है। अभी नीरज जी इस बात को कह रहे थे कि आज शिक्षा पर बहस चल रही है, तो हाउस खाली है और कल जब फुटबॉल का मैच हो रहा था, तो पूरा हाउस भरा हुआ था। सर, हमारी क्या priorities हैं और हमें कहां जाना है? लाचारी, गरीबी, मजबूरी, बदहाली, इससे हिन्दुस्तान को लड़ना था, पर यह पार्लियामेंट हमारा टूल था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि 2002 में जब हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, तब माननीय अटल जी ने पहली बार संविधान संशोधन करके शिक्षा को अधिकार का मोल दिया था। सर, शिक्षा भीख नहीं थी, शिक्षा अधिकार थी, लेकिन 2002 के बाद जब 2009 में कानून बना है, इस मुल्क के साथ धोखा हो गया। जिस देश के अंदर गरीब-अमीर सभी को बराबर का हक मिलना चाहिए था, वहां पर शिक्षा के नाम पर एक ऐसा कानून बना, राइट टू एजुकेशन, भांति-भांति की शिक्षा! गरीबों की शिक्षा अलग, अमीरों की शिक्षा अलग, कहने का मतलब यह है कि जो जितना समृद्ध है, उसकी शिक्षा अलग।

मेरे बहुत से साथी तथ्यों पर बात कर चुके हैं, मैं उन पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ विचार और उसकी philosophy पर बात करना चाहता हूँ। सर, सच्चाई तो यह है, आदरणीय मंत्री जी को मैं बताना चाहता हूँ कि इस देश की जनता ने, यहां की महिलाओं ने और यहां के बच्चों ने आपको बहुत आदर, बहुत सम्मान और बहुत प्यार दिया है। यह वतनपरस्ती का तकाज़ा है, इसलिए आप उनके बारे में सोचें। हिन्दुस्तान के बच्चों के साथ discrimination हो रहा है। यदि गरीब का बच्चा कहीं पढ़ेगा, अमीर का बच्चा कहीं पढ़ेगा, तो हिन्दुस्तान कैसे एक होगा? स्कूल सिर्फ शिक्षित करने के लिए नहीं होता है, बल्कि स्कूल बच्चे को socialise करने के लिए भी होता है। यह 7200 जातियों का देश, मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि यह न्याय के सहारे आगे बढ़ेगा। ...**(समय की घंटी)**...

श्री उपसभापतिः आपके दो मिनट हो गए। Now, Shri Tarun Vijay, please take only two minutes.

SHRI RAVI PRAKASH VERMA: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You will get another chance. I have got your point.

SHRI RAVI PRAKASH VERMA: *

श्री उपसभापतिः आपकी बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है। ...(**व्यवधान**)... आपको दूसरा अवसर मिलेगा। ...(**व्यवधान**)... आपको दूसरी opportunity मिलेगी।...(**व्यवधान**)... You can give notice for a discussion. It is not going on record.

SHRI RAVI PRAKASH VERMA: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is not going on record. Now, Shri Tarun Vijay, after two minutes, the mike will be switched off.

SHRI TARUN VIJAY (Uttarakhand): Sir, I just want to raise one issue for the attention of the hon. Minister. I have been trying to raise the issue of dyslexic children for the last two years, but I have never got a chance because the political issues overwhelm the other issues. According to one mapping, there are more than one crore dyslexic children and 50 lakh autistic children. The parents run from pillar to post. वे धक्के खाते हैं, सर। उनको किसी स्कूल में काउसिलर नहीं मिलता, उनको किसी स्कूल में inclusive education नहीं मिलती। Sir, I come from Uttarakhand, which is known all over the world for its educational system. They are not schools; they are factories of education. Not a single school has got a dyslexia counsellor; not a single school has got inclusive education for the dyslexic and autistic children. Are they not our children? Think beyond politics. मैं संस्कार, सभ्यता, गुरुकुल वगैरह-वगैरह बड़ी-बड़ी बातें नहीं करता। ये बच्चे हमारे हैं। इन बच्चों के मां-बाप आत्महत्या करने के कगार पर पहुँचे हुए हैं। जिन क्षेत्रों में ये जाते हैं, वहां जो एनजीओज़ खुले हैं, वे बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं। वे एक हफ्ते के 75,000 रुपये लेते हैं। पूरे उत्तर भारत में dyslexic बच्चों के लिए कोई काउसिंलिगं सेंटर नहीं है, किसी स्कूल में नहीं है। हम दिल्ली में धक्के खाते हैं। हम पूरी दिल्ली में घूमकर आए। आपको एक-दो स्कूल गुड़गांव में मिलेंगे, एक लक्ष्मण विद्यालय, हौज खास में मिलेगा, एक श्रीराम स्कूल है, जहां पर लिमिटेड सीट्स हैं और बच्चों को वहां सीट्स नहीं मिलती हैं। सर, क्या उन लोगों को जहर खा लेना चाहिए? क्या उन लोगों को अपने मां-बाप के साथ दूसरे देश में जाना चाहिए? हम विदेशों में जाते हैं, हम मिट्टी, सभ्यता और 5000 साल पुराने संस्कारों की बात करते हैं। यह असत्य बात है, हममें संवेदना नहीं है। हममें अपने बच्चों की इन तकलीफों के बारे में कोई ममता और वात्सल्य नहीं है। ऐसा किसी विद्यालय में देखने को नहीं मिलता। इसलिए माननीय मंत्री महोदया, भगवान के लिए इन बच्चों के बारे में कुछ सोचिए। ...(**व्यवधान**)...

---

*Not recorded.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. ...(*Interruptions*)... आपके दो मिनट हो गए। Now, Shri Rapolu. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU (Telangana): Mr. Deputy Chairman, Sir, this is not my participation as a speaker... ...(*Interruptions*)...

KUMARI SELJA: Sir, I strongly support what Mr. Tarun Vijay has said. ...(*Interruptions*)...

SHRI D. RAJA: Sir, I also support what he has said. ...(*Interruptions*)...

श्री नीरज शेखरः सर, तरुण विजय जी ने जो कहा, उसका मैं भी समर्थन करता हूँ।

श्री सतीश चंद्र मिश्राः सर, इन्होंने जो कहा है, उसका मैं भी समर्थन करता हूँ।

श्री हरिवंशः सर, इन्होंने जो कहा है, उसका मैं भी समर्थन करता हूँ।

श्री रवि प्रकाश वर्माः सर, इन्होंने जो कहा है, उसका मैं भी समर्थन करता हूँ।

श्री अरविन्द कुमार सिंह (उत्तर प्रदेश)ः सर, इन्होंने जो कहा है, उसका मैं भी समर्थन करता हूँ।

श्री आलोक तिवारी (उत्तर प्रदेश)ः सर, इन्होंने जो कहा है, उसका मैं भी समर्थन करता हूँ।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश)ः सर, इन्होंने जो कहा है, उसका मैं भी समर्थन करता हूँ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is good. ...(*Interruptions*)... We all support this. ...(*Interruptions*)... Mr. Rapolu, you have only two minutes. After two minutes, mike will be switched off.

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: Sir, I will give only one suggestion and I won't take even one minute. Sir, as the hon. Minister emotionally expresses her motherness, and, since a broad-based discussion has happened on the Ministry of Human Resource Development, I appeal to her that keeping in view the prevalent conditions across the universities, if she could show the generosity to remove all the punishments announced towards all the students across all the universities of the country, it will be a great gesture, it will be a good beginning, and, it will harmonise the environment throughout the country. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Now, Dr. Prabhakar Kore.

DR. PRABHAKAR KORE (Karnataka): Sir, I have to give only two suggestions. One suggestion is regarding the higher education system. I do not know whether the Government knows about the college system now. Most of the subjects are dying. There are no Sociology students in higher education, particularly, in universities; there is no History, there is no Physics...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Very correct.

DR. PRABHAKAR KORE: No research is happening because there is no staff. I am not talking about State universities...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Not even Political Science.

DR. PRABHARKAR KORE: Most of the subjects, Sir. Today, what is happening is that everybody wants to go either for engineering or medical. The minimum marks will be 35, 40, or, 45 to be eligible because there are many vacancies in engineering colleges. If the students don't get into engineering colleges, they go to other colleges for these subjects. They have got absolutely no interest because there is no staff, there is nothing. You are opening a new Central university with same subjects. There is no use of opening a new university. Existing university, old university, hundred years old university, you have to strengthen that university, and see that staff is available; and, post-graduation and research should take place. That is my suggestion. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Now, Shri Bhattacharya.

SHRI P. BHATTACHARYA (West Bengal): Sir, I have a few points to make. Sir, I got all the information from different corners, from the hon. Members. Unfortunately, it does not speak about the disabled students, who are studying in different schools. We have not mentioned a single word about them. I feel that the hon. Minister should take full care for this type of people. And how to reveal their future, that also has to be looked into.

Sir, the second thing is, I would request the hon. Minister to change the Central Universities Act. It has to be changed because I have experience about the Vishwa Bharati University. After what I raised in this House, the Ministry inquired and the Vice-Chancellor was removed. That was a good gesture from the Ministry and the Minister herself. I feel that the Central Universities Act is a very old Act. This Act must be changed immediately with the modern concept so that the Vice-Chancellors and the University court can function properly. Sometimes, the University court functions as if it is absolutely about their functioning. The Government cannot interfere, neither the State nor the Central Government. But the entire financial assistance is given by the Central Government. If they don't have the power to control the University, then it is being misused. So, I feel the Minister would take care of it. Thank you.

SHRI SATISH CHANDRA MISRA: Sir, I know I am speaking again. लेकिन इश्यू ऐसा है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा झा साहब ने कहा था, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कीम है, "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" माननीय प्रधान मंत्री जी का सबसे इम्पॉर्टेंट इश्यू है, जो इन्होंने रेवाड़ी,

हरियाणा से शुरू किया था। मैं सदन को यह सूचना देना चाहता हूं कि अभी जब मेरे बोलने के बाद मैं बाहर गया तो "इंडिया टीवी" में एक न्यूज़ चल रही थी, उसमें वे दिखा रहे थे कि 18 अप्रैल को जो incident रेवाड़ी में, वहां की एक लड़की जो स्कूल जा रही थी, उसके साथ हुआ, उसका नतीजा यह रहा — इसके पहले भी वह उसी स्थान पर हो चुका था, जहां उन्होंने यह प्रोग्राम शुरू किया था — कि वहां पर इस समय 45 स्कूल जाने वाली लड़कियां धरने पर बैठी हैं। जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वहां पर और लोग भी उनके साथ बैठे हैं। उन्होंने कहा है कि हम लोग स्कूल नहीं जाएंगी। यह बात माननीय प्रधान मंत्री जी की नॉलेज में आ जानी चाहिए क्योंकि यहीं से उन्होंने यह प्रोग्राम स्टार्ट किया था। यहां हम लोग आज सदन में बैठे हुए हैं और इस समय भी वे सब धरने पर बैठी हैं, वहां पर धरना दे रही हैं क्योंकि उन्होंने स्कूल न जाने की कसम खायी है। उन्होंने कहा है कि हम लोग स्कूल नहीं जाएंगी क्योंकि हम लोगों की कोई सेफ्टी, सिक्योरिटी नहीं है। यह बात मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं।

SHRI TAPAN KUMAR SEN (West Bengal): Sir, I think that is a very serious concern. The Minister will be addressing it. The Haryana Government is there. They will be taking it up with them also very seriously.

My only point is, and I will retire in just one sentence, I would like to again request, my other colleagues have already requested, that the Mid Day Meal workers are being treated very inhumanly which, I believe, is the foundation of elementary education system in our country. I heard the hon. Minister, while replying to a question, mentioning earlier in this House that that is a matter of their right and Government is determined to carry on the Scheme. I compliment the Minister for such an attitude. Having said that, I request, I know her limitations, her to see the manner, the kind of service they are given and the kind of inhuman treatment they are getting, all women mostly. I think, in one or two States, there are some male cooks; otherwise all are women. Their honorarium must be increased.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes. I also support that.

DR. K. P. RAMALINGAM: Sir, the entire House supports that.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: I know it is difficult. I urge, through you, all the members of the Government side and also the Finance Minister to help the HRD Ministry to see that this state of inhuman treatment is improved to some extent. I don't expect overnight a big change, but at least improve it to some extent so that a message goes to them that they are being taken care of. Kindly consider it. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All right. You made your point. Chair also supports you.

श्री नरेश अग्रवालः उपसभापति जी, हमारा आपसे अनुरोध है कि अब आठ बजने वाले हैं, करीब एक घंटा मिनिस्टर को भी reply के लिए चाहिए, अगर आप reply कल करा दें, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि और भी जगह लोगों के प्रोग्राम हैं। आप इसे कल करा दें या सोमवार को करा दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि अब आठ बजने वाले हैं।

DR. K. P. RAMALINGAM: Tomorrow morning, at 11 o'clock, it can be taken up.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What does the hon. Parliamentary Affairs Minister say?

श्री मुख्तार अब्बास नक़वीः सर, ऑनरेबल नरेश भाई जो कह रहे हैं, मंत्री जी ने तीन बजे से बैठकर लगातार सभी माननीय सदस्यों की बातें सुनी हैं। मुझे लगता है कि माननीय मंत्री जी, आपका जो समय है, उसका ध्यान रखेंगी, इसलिए अगर आज reply खत्म हो जाएगा तो better होगा। इसलिए माननीया मंत्री जी आज reply कर दें और इस इश्यू को खत्म करें तो better होगा।

श्री नरेश अग्रवालः हम लोगों ने भी बैठकर सुना है। ...**(व्यवधान)**... अगर इसका रिप्लाई अच्छी तरह से दिया जाएगा, तो आपको one hour minimum चाहिए। रात के 9 बजेंगे, one hour reply चाहिए। मेरा अनुरोध है कि ...**(व्यवधान)**...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वीः आप अभी से समय क्यों तय कर रहे हैं? हो सकता है कि उससे कम समय में माननीया मंत्री जी उत्तर दे दें। ...**(व्यवधान)**...

श्री नरेश अग्रवालः मैं जानता हूं ...**(व्यवधान)**...

श्री सतीश चंद्र मिश्राः आप उनको सीमित क्यों कर रहे हैं? ...**(व्यवधान)**...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वीः नहीं, नहीं। ...**(व्यवधान)**... इसीलिए कह रहे हैं कि रिप्लाई एक घंटे क्यों, दो घंटे का भी हो सकता है। ...**(व्यवधान)**...

श्री नरेश अग्रवालः मैंने इसीलिए minimum one hour कहा है। ...**(व्यवधान)**... It may be two hours. मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मैं सीमित करना चाहता हूं।...**(व्यवधान)**...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वीः अभी उन्होंने तैयारी की है, फिर क्या होगा?...**(व्यवधान)**... मिश्रा जी, हमें चाइल्ड एंड लेबर के रिप्लाई के लिए रोज़ हमको टोकते थे ...**(व्यवधान)**... इसका रिप्लाई हो जाए। ...**(व्यवधान)**...

श्री नरेश अग्रवालः इसका रिप्लाई Monday को हो जाए। ...**(व्यवधान)**...

श्री तपन कुमार सेनः माननीय मंत्री जी को क्यों आप ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have to call the consensus of the House for extension. ...(*Interruptions*)... The problem is.....(*Interruptions*)... Naqvi ji. ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Sir, I am prepared to respond to an exhaustive debate which has taken place since 3 o'clock, close to five hours' debate

and deliberation. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is the point.

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: I would urge upon the entire House, you have been extremely patient in hearing everybody's views. ...(*Interruptions*)... And since most of them are my elders, I would urge them to hear the response today itself because everybody has passionately spoken about this issue. So, I am well-equipped to answer every question that has been posed. I am also aware of the fact that everybody is predisposed to hearing a response. I would urge upon you, Sir. I know it is exhausting for some who have continuously sat here, especially, those who are sitting right in the centre. ...(*Interruptions*)... But I would appreciate if I am allowed to give the answer today itself. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have to take the consent of the House for extension because it is already going to be 8 o'clock. ...(*Interruptions*)... Now, Minister wants today. ...(*Interruptions*)...

SHRI NARESH AGRAWAL: Maybe, tomorrow. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The point is, tomorrow, where is the time? ...(*Interruptions*)...

DR. K. P. RAMALINGAM: Tomorrow morning at 11 o'clock, Sir. ...(*Interruptions*)... We can have it at 11 o'clock itself. ...(*Interruptions*)...

SHRI MUKHTAR ABBAS NAQVI: Sir, 11 o'clock is the Zero Hour. 12 o'clock is Question Hour. ...(*Interruptions*)... How can we do that? ...(*Interruptions*)... 12 o'clock is the Question Hour. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: If not today, it will be possible only on Monday. ...(*Interruptions*)...

श्री मुख़्तार अब्बास नक़वीः सर, अगर मंत्री जी रिप्लाई देना चाहती हैं, तो उनको टाइम दे दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Naqviji, if not today, it will be possible only on Monday. ...(*Interruptions*)... Okay. ...(*Interruptions*)... I am asking how much time you will take for reply, if it is today. ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Sir, I know that most of the questions posed... ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We are all tired. ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: ...are concerning teachers, curriculum and the existing situation in many universities. Pre-dominantly, these are the three main topics on which every Member has expressed concern. I want to give them reply in response to this. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: How much time do you want? ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Post with, if there are any other questions, which they feel are left unanswered, they can ask. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: But how much time will you take? ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: So, I will beg your indulgence, as Satishji, the learned lawyer, said, do not limit me. But I will base it broadly on these three spheres on which every Member has expressed concern. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: But the point is, beyond 8 o'clock for extension, the consent of the House is needed. I cannot unilaterally say that. ...(*Interruptions*)... If all of you agree,.....(*Interruptions*)... That is what I say. ...(*Interruptions*)... If it is half-an-hour, we can sit. ...(*Interruptions*)...

श्री नरेश अग्रवालः सर, पूरा हाउस खाली है। ...(**व्यवधान**)...

चौधरी मुनव्वर सलीम (उत्तर प्रदेश): सर, जब मंत्री जी बोलें, तो हाउस भरा होना चाहिए। ...(**व्यवधान**)...

†**چودھری منور سلیم :** سر، جب منتری جی بولیں، تو ہاؤس بھرا ہونا چاہئے۔ ---**(مداخلت)**---

श्री नरेश अग्रवालः सर, आप मान लीजिए। इसको आप Monday को कर दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

चौधरी मुनव्वर सलीमः एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ...(**व्यवधान**)... एजुकेशन से ज्यादा महत्वपूर्ण और क्या हो सकता है? ...(**व्यवधान**)...

†**چودھری منور سلیم:** ایجوکیشن بہت اہم موضوع ہے۔ ---**(مداخلت)**--- ایجوکیشن سے زیادہ اہم اور کیا ہوسکتا ہے ---**(مداخلت)**---

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. ...(*Interruptions*)... On Monday, there is Finance Bill. And Appropriation Bill is also there. ...(*Interruptions*)...

श्री नरेश अग्रवालः सर, मैं ठीक कह रहा हूं। ...(**व्यवधान**)... जब मंत्री जी इस मिनिस्ट्री पर जवाब दें, तो हाउस में लोगों की presence तो हो। हाउस पूरा खाली है!

श्री मुख़्तार अब्बास नक़वीः नरेश जी, आपने initiate किया है। आपने इतनी अच्छी तरह से विषय रखा है ...(**व्यवधान**).... इतनी अच्छी तरह से विषय को रखा है ...(**व्यवधान**)... ऑनेबल मिनिस्टर कोशिश करेंगी ...(**व्यवधान**).. सारे ऑनेबल मेम्बर्स ने जो बात रखी है, उसके बारे में

† Transliteration in Urdu script.

वे बोलें और आपकी जो चिंता है कि दो घंटे या एक घंटा, यह तो वे समझती हैं कि आप चाहते हैं कि जल्दी...

श्री नरेश अग्रवालः मैं चाहता हूं कि हाउस भरा हुआ हो। जब इस मिनिस्ट्री का रिप्लाई हो ...(**व्यवधान**)... तो हाउस भरा हुआ हो।...(**व्यवधान**)...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वीः आप इसकी कैसे गारंटी ले लेंगे कि जब माननीया मिनिस्टर अगली बार रिप्लाई करेंगी, तो हाउस भरा रहेगा? ...(**व्यवधान**)...

श्री नरेश अग्रवालः आप मिनिस्टर ...(**व्यवधान**)...दो-तीन बजे तो हाउस भरा ही रहता है। ...(**व्यवधान**)... इसमें कौन सी दिक्कत है? ...(**व्यवधान**)... tomorrow or Monday ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Naqvi, to extend the House beyond 8.00 p.m., I need the consensus. That is not there. That is my problem. ...(*Interruptions*)... Nareshji, I will tell you something. बैठिए, बैठिए। One, I also want to hear the reply of the Minister. I want that the Minister should reply. I used to teach in a college. So, I am also concerned about the problem of education. So, there should be a reply. Two, on Monday, there will be important business – The Appropriation Bill and The Finance Bill. They have to be taken up. The House should agree that all these three things will be taken up on Monday. If that can be done...(*Interruptions*)...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Why don't you have it tomorrow? ...(*Interruptions*)...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वीः अगर हाउस की सहमति होती है, तो कल साढ़े चार बजे के बाद रिप्लाई हो जाए। Then do it today. कल भी नहीं होगा। Till 4.30 p.m. or 5.00 p.m., there will be Private Members' Business and after that we will have the reply. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is okay. ...(*Interruptions*)...

SHRI MUKHTAR ABBAS NAQVI: You don't want it today. You don't want it tomorrow. ...(*Interruptions*)... When do you want it then? ...(*Interruptions*)...

SHRI NARESH AGRAWAL: Sir, we agree to it. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is okay. ...(*Interruptions*)...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: You can do it tomorrow morning. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will give another suggestion. We decide to have the reply tomorrow, if the hon. Chairman agrees to it. I have to consult the hon. Chairman. We will have the reply between 11.00 a.m. and 12.00 noon tomorrow. ...(*Interruptions*)... Otherwise, we will have it tomorrow between 5.00 p.m. and

[Mr. Deputy Chairman]

8.00 P.M.

6.00 p.m. ...(*Interruptions*)... Or in the morning itself. ...(*Interruptions*)... This is the decision. ...(*Interruptions*)... That is okay. ...(*Interruptions*)... The decision is that if the hon. Chairman agrees...(*Interruptions*)... Listen to me. I will consult the hon. Chairman. If he is in agreement, it will be taken up between 11.00 a.m. and 12.00 noon. Otherwise, it will be taken up at 5.00 p.m. Okay. Now, we shall take up admitted Special Mentions.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. P. SINGH BADNORE) *in the Chair*]

SPECIAL MENTIONS

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. P. SINGH BADNORE): Shri C.P. Narayanan; absent. ...(*Interruptions*)... Shri Tarun Vijay...(*Interruptions*)... Shri Ravi Prakash Verma.

Demand to make traffic rules more stringent to reduce casualties in the Country

श्री रवि प्रकाश वर्मा (उत्तर प्रदेश): सर, मार्ग दुर्घटना सर्वे 2016 में अवगत कराया गया है कि पूरे भारत में लगभग एक लाख पचास हजार लोग प्रतिवर्ष मारे जाते हैं तथा चार लाख पचास हजार प्रति वर्ष घायल और विकलांग हो जाते हैं। यह अत्यंत गंभीर बात है। अतः मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि यातायात नियमों को और सख्त बनाकर राष्ट्रीय स्तर पर... उनका पालन एक समान कराने हेतु विशेष प्रयास करें। ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. P. SINGH BADNORE): You can lay it now.

श्री रवि प्रकाश वर्मा: ताकि इन कीमती जानों को बचाया जा सके।

श्री आनंद भास्कर रापोलू (तेलंगाना): महोदय, मैं स्वयं को इससे संबद्ध करता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. P. SINGH BADNORE): Shri Ronald Sapa. ...(*Interruptions*)... It will come back. You lost it that time.

Demand to start more exploration projects of oil and natural gas in North-Eastern region

SHRI RONALD SAPA TLAU (Mizoram): Sir, hon. Minister of Petroleum and Natural Gas unveiled ₹ 1,30,000 crore plan to double oil and gas production in North-East on 9.2.2016. The Plan aims to help the country's energy economy to explore its linkages and trade opportunities with neighbours. The project is to help make clean fuels accessible, fast-track projects, generate employment opportunities, etc. Out of ₹ 1,30,000 crore, ₹ 80,000 crore is upstream, ₹ 20,000 crore is